असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

04 मार्च, 2022

सप्तदश विधान सभा — शुक्रवार, तिथि 04 मार्च, 2022 ई॰
पंचम सत्र — 13 फाल्गुन, 1943 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

समय पर उठाइयेगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : भागलपुर में बम ब्लास्ट हुआ है, 14 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इसपर सरकार का अभी तक कोई बयान नहीं आया है और न वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है । इसलिए आपके संज्ञान में देना चाहते हैं यह बहुत बड़ा मामला है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । श्री ललित कुमार यादव ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्षः उचित समय पर । अभी बैठिये ।

(व्यवधान)

अलग-अलग फोरम पर यह प्रश्न आया भी है, सरकार ने उसका जवाब भी दिया है, बैठ जाइये, उचित समय पर उठाइयेगा ।

(व्यवधान)

प्रश्न किए हैं न । आप प्रश्न किए थे न ।

(व्यवधान)

अभी क्वेश्चन होने दीजिए, उत्तर मुद्रित है आपका ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, यह बड़ा अन्याय हुआ है, बेलागंज में बड़ा अन्याय हुआ है इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए ।

अध्यक्षः इसको समय पर उठाइयेगा ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये सबलोग ।

(व्यवधान)

इसे समय पर उठाइयेगा और आज कार्यस्थगन है, कार्यस्थगन का भी मामला है उस समय । बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0-21 (श्री ललित कुमार यादव, क्षेत्र सं0-82, दरभंगा ग्रामीण)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: (1) गुड गवर्नेंस इंडेक्स-2020-21 के प्रतिवेदन में ग्रुप बी में राज्यों में 8 राज्यों में बिहार 6वें स्थान पर है ।

(2) गुड गवर्नेंस इंडेक्स-2020-21 रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड सेक्टर का ग्रोथ रेट वर्ष-2019-20 में 2.3 प्रतिशत था, जो 2020-21 में बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गया न कि निगेटिव ग्रोथ हुआ है । उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019-20 में खाद्यान्न उत्पादन का वृद्धि दर 1.3 प्रतिशत था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गया है ।

कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री में 8 राज्यों में बिहार 7वें स्थान पर है । बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के कार्यान्वयन से बिहार में 38 हजार करोड़ रुपयों का निवेश संभावित है । बिहार इथेनॉल पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य है । इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 के तहत 4 इथेनॉल इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया है तथा 17 इकाइयों की स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है ।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एन0एफ0एच0एस0)-4(2015) की तुलना में एन0एफ0एच0एस0-5(2019-20) में नियमित टीकाकरण के तहत पूर्ण प्रतिरक्षण का आच्छादन 61.7 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया है । चिकित्सकों के लगभग 49 प्रतिशत पद रिक्त हैं, जिनपर नयुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

(3) राज्य सरकार की विफलता का प्रश्न नहीं उठता है । गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 में वर्ष 2019 की तुलना में बिहार का ओवरऑल स्कोर 2019 के 4.40 से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 4.62 हो गया है । अर्थात् वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020-21 में 5 प्रतिशत की प्रगति हुई है । प्रगति के हिसाब से बिहार तीसरे स्थान पर है ।

बिहार में तीन प्रक्षेत्रों, यथा, "Public Infrastructure & Utilities", "Social Welfare & Development" तथा "Judiciary & Public Safety" में प्रगति हुई है ।

इसके अतिरिक्ति पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड यूटीलीटीज सेक्टर बिहार समूह बी में शीर्ष स्थान पर है । इस सेक्टर के दो सूचकांकों 'Connectivity to Rural

Habitation' तथा 'Energy Availability against requirement' में बिहार का प्रतिशत वैल्यू कमशः 99.9 प्रतिशत तथा 99.7 है ।

बिहार की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2005-06 में (-) 1.69 प्रतिशत थी, जो अर्थव्यवस्थ की गिरावट का प्रतीक रहा है । वर्ष 2006-07 में बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर (स्थिर मूल्य पर) 16.18 प्रतिशत हो गयी । वर्ष 2006-07, 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2018-19, 2019-20 में राज्य की आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से ज्यादा रही है । वर्ष 2019-20 में भी राज्य की वृद्धि दर 10.5 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक है । कोविड 19 के द्वारा उत्पन्न त्रासदी में वर्ष 2020-21 में भारत की वृद्धि दर निगेटिव (-7.3) हो गयी थी फिर भी बिहार राज्य की वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत रही है । यह राज्य की सशक्त अर्थव्यवस्था को दर्शाता है ।

कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र- कृषि रोड मैप की उपलब्धि है कि राज्य में खाद्यान्न, ईख, अंडा, मछली, मीट एवं फलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है । दुग्ध उत्पादन 57.67 मेट्रिक टन से बढ़कर 115 मेट्रिक टन हो गया है । राज्य को पांच कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है ।

पथ- वर्ष 2005 से अबतक पथ निर्माण विभाग की 18992 किलो मीटर सड़क तथा 6047 पुलों का निर्माण किया गया है । वर्ष 2005 में ग्रामीण पथों की लम्बाई 3112 किलो मीटर थी जो वर्ष 2021 तक 102306 किलो मीटर हो गयी है । हर घर तक पक्की गली-नालियां योजना अंतर्गत 117991 वार्डों के विरुद्ध 117464 वार्डों को आच्छादित किया जा चुका है ।

ऊर्जा- प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 2012-13 के 145 किलोवॉट प्रति घंटा से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 350 किलावॉट प्रति घंटा हो गयी है ।

पेयजल- सात निश्चय योजना के हर घर नल का जल कार्यक्रम अन्तर्गत नल का जल पा रहे घरों की संख्या 162.78 लाख हो गयी है ।

राज्य की न्याय के साथ विकास की नीति की सफलता राज्य को आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति की नई ऊंचाई की तरफ ले जा रही है ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब तो बहुत लंबा चौड़ा है । हम गुड गवर्नेंस इंडेक्स को 2020-21 में 8 राज्यों में छठे स्थान पर, माननीय मंत्री जी का भी जवाब स्वीकार किए हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री में भी 8 राज्यों में सातवें स्थान पर है और डॉक्टर का ये हम 50 प्रतिशत कहते हैं यह भी 49 प्रतिशत पद रिक्त कहे फिर भी राज्य सरकार अपनी चालबाजी हर क्षेत्र में वृद्धि दर्शा रही है महोदय लेकिन भारत सरकार भी बिहार सरकार के आंकड़े को नहीं मानती है यह जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स

की जो रिपोर्ट है जो भारत सरकार के गृहमंत्री द्वारा, गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है । हम कह रहे हैं कि ये बताएं कि 4 इथनॉल फैक्ट्री का उत्पादन शुरू हो गया है । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि 4 इथनॉल फैक्ट्री कौन सी है और किस फैक्ट्री में कितना उत्पादन हुआ है कृपया माननीय मंत्री जी बताया जाय ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: इनका जो प्रश्न था एक-एक प्वायंट, डीटेल उत्तर में सन्निहित है इसमें सप्लीमेंट्री की तो कोई गुंजाइश नहीं है, अब ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार, तो हम कहां कह रहे हैं कि बिहार बहुत समृद्ध राज्य है । हम जो डेवलपमेंट किए 2005 के बाद जो हमारा इंडेक्स है सभी सेक्टर में जो विकास हुआ है उसका डीटेल है इसमें । हम यह तो नहीं कह रहे हैं कि हम हो गए एकदम समृद्ध राज्य और भारत हो गया अमेरिका की तरह समृद्ध देश । हम तो पिछड़े राज्य में हैं ही इसीलिए तो कह रहे हैं कि इसे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए इसमें कहां कोई दो...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जरा अब सुनिये, जरा इसको अब सुन लीजिए...

श्री भाई वीरेन्द्र: उधर कौन है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष: आप विषयांतर मत होइये, बैठिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: आप सुन तो लीजिए इसको पॉलिटिकल इशू मत बनाइये इकोनॉमिक पॉजिशन पॉलिटिकल इशू का सब्जेक्ट ही नहीं है अपनी-अपनी बुद्धि, अपने-अपने कौशल से लोग अपनी-अपनी बात कहते हैं यह अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर बात है लेकिन जो डबल इंजन की सरकार है तो एक-एक फिगर आप देखिए कि कितना काम हुआ है, काम तो हुआ है लेकिन सुन तो लीजिए...

अध्यक्ष: ठीक है, बैठ जाइये, शांति रखिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: सुनिये, डबल इंजन की सरकार, जरा पढ़ा करिए भाई वीरेन्द्र जी ऐसे मत बोला कीजिए । इकोनॉमिक पॉजिशन को ठीक से हृदयंगम करने की जरूरत है, कोई पेट से पैदा होकर विद्वान नहीं होता है । आप जीवन के हरेक क्षण क्षेत्र में ज्यों-ज्यों आगे बढ़िएगा, बल्कि एक कहावत तो यह है कि जो आदमी संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण होता है, तो वह दुनिया से चला ही जाता है । ज्ञान हमेशा सीखने की बात है इसीलिए इसको पॉलिटिकल इशू मत बनाइये, बिहार पिछड़ा राज्य है इसको कौन इनकार कर सकता है, लेकिन लगातार बिहार डेवलपमेंट किया है हमारी सरकार जबसे आई है । एक-एक ग्राफ, एक-एक फिगर यही तो हमलोग कह रहे हैं और हम कहां कह रहे हैं कुछ ? एक चीज, अब मान लीजिए कि महाराष्ट्र का जो फिगर है वह कंपरीजन हो जाय बिहार से तो हम थोड़े कहेंगे, हमारे पॉपूलेशन इंटेनसिटी हाई है,

हमारा ज्योग्रैफी कम है, हमारे यहां स्वाभाविक तौर से भारतीय संस्कृति में कहावत है कि यह गंगी-जमुनी सभ्यता है । आज लोग जब आए यहां तो सबसे ज्यादा ईजी एवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, समशीतोष्ण वातावरण, हिमालयन बेसिन में ज्यादा से ज्यादा उसकी बसावट हुई इसके लिए हमलोग कारण नहीं हैं कि प्रजनन दर बहुत बढ़ गयी, यह तो ऐतिहासिक कारण है इसको गंगी-जमुनी सभ्यता कहा ही जाता था, इन सब कारणों से इसकी अपनी अलग-अलग एक पहचान है अब कहीं बाढ़ आए न आए हमारे यहां बाढ़ आती है, हिमालय के बेसिन में है और पेनेलियल रिवर कहीं नहीं है, हिमालयन रिवर में है, पेनेलियल रिवर का करेक्टेरिस्टिक यह होता है कि गर्मी में अन्य नदियां सूख जाती हैं, लेकिन हिमालयन रिवर में यह है कि बर्फ पिघलता है, गर्मी जो होती है नदियां भर जाती हैं, हल्की भी वर्षा होती है तो बर्फ फ्लो करके बाढ़ आ जाती है यही कारण है । इसलिए हमलोग कंपरीजन नहीं कर सकते हैं उन राज्यों का लेकिन एक वक्त था जब गंगी-जमुनी सभ्यता में ज्यादा समृद्धि थी और साउथ के स्टेट में हमारे यहां के वनिस्पत गरीबी थी, क्योंकि कृषि युग को अगर आप देखेंगे तो गंगी-जमुनी सभ्यता को ही कृषि युग का कहा जाता था कि यह गोल्डन इतिहास है इसका । इसीलिए, आंकड़े इसमें डिटेल दिए हुए हैं इससे संबंधित कोई प्रश्न की कोई जरूरत ही नहीं है ।

श्री ललित कुमार यादवः माननीय मंत्री जी, आंकड़ा से ही संबंधित, आपका जवाब जो है 4 इथनॉल फैक्ट्री चालू हो गयी हैं हम यही आपसे पूछे कि चारों इथनॉल फैक्ट्री में कितना उत्पादन हो रहा है, कब चालू हुई है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः कहां लिखा हुआ है चालू हो गयी हैं ।

श्री ललित कुमार यादवः देखिए महोदय, अपने उत्तर में देखिए, आप अपने उत्तर को पढ़िए महोदय, 4 इथनॉल चालू हो गयी हैं और 17 पर अग्रेतर की कार्रवाई चालू की स्थिति में है, अब देखा जाय महोदय । अपने उत्तर में देखा जाय महोदय ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य...

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब में आप भी अध्यक्ष महोदय देख लीजिए, 4 इथनॉल फैक्ट्री चालू हो गयी हैं, हम माननीय मंत्री जी से यही पूछ रहे हैं कि...

अध्यक्षः चारों इथनॉल फैक्ट्री की जानकारी चाहिए अलग से माननीय मंत्री जी इनको बता देंगे ।

श्री ललित कुमार यादवः चारों इथनॉल फैक्ट्री कहां-कहां चालू हुई और प्रतिदिन...

अध्यक्षः अब समय भी देखिये ।

श्री ललित कुमार यादवः क्या महोदय, सदन है, महोदय सदन में माननीय मंत्री जी जवाब दिए हैं, चार इथनॉल फैक्ट्री चालू हो गयी हैं, चार इथनॉल फैक्ट्री कौन हैं और 17 पर बोल रहे हैं कि चालू की स्थिति में हैं वह 17 कौन हैं चालू की स्थिति में, महोदय माननीय मंत्री जी का जवाब आया है उसी से पूरक पूछ रहा हूं और दूसरा महोदय ये राज्य में बागवानी की...

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः यह चालू वाली अलग से सूचना दे देंगे ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, यह सदन है, सदन में उत्तर आया है माननीय मंत्री जी का और माननीय मंत्री जी बोले हैं चार...

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप चारों इथनॉल फैक्ट्री की जानकारी चाहते हैं । माननीय मंत्री जी उपलब्ध करा देंगे, माननीय सदस्य को ।

श्री ललित कुमार यादवः नहीं, हम जानकारी नहीं चाहते हैं...

अध्यक्षः आपको उपलब्ध करा देंगे ।

श्री ललित कुमार यादवः ये 4 इथनॉल फैक्ट्री...

अध्यक्षः आप सुन लीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः आप सुनिये, योजना और विकास विभाग सभी विभागों से आंकड़े इकट्ठे करके प्रश्नों का उत्तर बनाता है, तो जो विभाग समझे कि माननीय सदस्य को जानकारी...

टर्न-2/अंजली/04.03.2022

अध्यक्ष : आप उपलब्ध करा देंगे ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जी महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य, श्री नीतीश मिश्रा । जो जानकारी चाहिए वह उपलब्ध करा देंगे ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सदन में गलत जवाब आने पर...

अध्यक्ष : गलत जवाब ? एक मिनट, बैठिये-बैठिये ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : चार जगह गन्ना से इथेनॉल मिल रहा है, आपके राम नगर से इथेनॉल मिल रहा है, नरकटियागंज से इथेनॉल मिल रहा है, बेतिया से इथेनॉल मिल रहा है और गोपालगंज से मिल रहा है । इन चार जगहों से से इथेनॉल मिल रहा है।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : सुगौली से मिल रहा है ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : सुगौली से भी, यह इथेनॉल बन रहा है ।

श्री ललित कुमार यादव : सिर्फ चालू हुआ है, आप फैक्टरी की बात करिये, आपके जवाब में है, आप डायवर्ट मत करिये ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : चीनी मिल फैक्टरी है । चीनी मिल फैक्टरी से बन रहा है ।

अध्यक्ष : श्री नीतीश मिश्रा, पूरक पूछिये ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-22, श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र सं0-38 झंझारपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. वस्तुस्थिति यह है कि (i) विभागीय संकल्प 6737, दिनांक-29 दिसंबर, 2017 के द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका में गली-नाली/संपर्क पथ की योजना अनुमान्य है ।

(ii) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में अनुमान्य योजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप सृजित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव का प्रावधान नहीं रहने के कारण इसके अनुरक्षण एवं रख-रखाव का कार्य नहीं हो पाता था । ऐसी स्थिति में विभागीय संकल्प संख्या-1172, दिनांक- 24 मार्च, 2021 के द्वारा मार्गदर्शिका में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप सृजित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग के स्थानीय पदाधिकारियों को हस्तांतरित किया जायेगा ।

(iii) सृजित परिसंपत्तियों के संबंधित प्रशासी विभाग को हस्तांतरण के उपरांत इसके अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा एक अलग विषय शीर्ष खोलकर प्रत्येक वर्ष बजट प्रावधान कराया जायेगा ।

(iv) यदि किसी विभाग के पास पूर्व से अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु बजट शीर्ष उपलब्ध नहीं है तो ऐसे विभागों द्वारा परिसंपत्तियों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु अलग से बजट शीर्ष खोलकर सृजित एवं हस्तांतरित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु बजट प्रावधान कराया जायेगा । ऐसी हस्तांतरित परिसंपत्तियों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण पर हुये व्यय का लेखा-जोखा संबंधित प्रशासी विभाग के द्वारा अलग से रखा जायेगा ।

2. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत निर्मित गली-नाली/संपर्क पथ के अनुरक्षण एवं रख-रखाव के लिये संबंधित प्रशासी विभाग को बजट में प्रावधान कर अनुरक्षण एवं रख-रखाव के दायित्व का प्रावधान मार्गदर्शिका में किया गया है ।

3. उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, 2 मार्च को इस पर वृहद ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस विषय पर चर्चा हो चुकी है मेरा यह प्रश्न स्पेसिफिक मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास के तहत जिन सड़कों का निर्माण हुआ है उसको ग्रामीण कार्य विभाग को...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ललित जी, आप बैठ जाइए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, एक मिनट । इथेनॉल पानी से बनता है क्या ? मक्का से बनता है, ईख से बनता है, इथेनॉल किसी न किसी अवयव से बनेगा । तो हमने कहा कि जानकारी लेकर, लेकिन माननीया उप मुख्यमंत्री के इलाके में चीनी मिल है वहां से मिल रहा है तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बता दिया तो इसमें इतना क्या है, समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री ललित कुमार यादव : क्या उत्पादन होता है यह भी बता दीजिये ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अब सुन तो लीजिये, उद्योग विभाग से डिटेल लेकर आपको दे देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री नीतीश मिश्रा ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर 2 मार्च को ध्यानाकर्षण के माध्यम से विस्तार में चर्चा हो चुकी है । मेरा यह प्रश्न स्पेसिफिक ग्रामीण कार्य विभाग को उन सड़कों को ट्रांसफर करने का है जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत जिन सड़कों का निर्माण हुआ है उनका रख-रखाव ग्रामीण कार्य विभाग अपने मेन्टेनेंस पॉलिसी के तहत करे । मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि उन सड़कों को वह अधिग्रहण कर ले और अपनी सूची में लेकर उन सड़कों को मेन्टेन करे ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि वहां के जो ऑफिसर हैं उस डिपार्टमेंट से कोआर्डिनेट करके और कार्रवाई करें।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, मेरा एक पूरक है इसमें । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि संबंधित प्रशासी विभाग को हस्तांतरण करके अनुरक्षण किया जायेगा । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में जो लिस्टेड है उसमें क्या प्रशासी विभाग तय हो गये हैं कि इसके कौन-कौन से प्रशासी विभाग उसको हस्तांतरण लेंगे, उदाहरण स्वरूप अगर हम कहीं सामुदायिक भवन बनाये हैं तो उसमें कौन सा प्रशासी विभाग लेगा, ऐसे ही जो विभिन्न-विभिन्न योजनाएं हैं उसमें सभी प्रशासी विभाग तय हो गया है तो कौन लेगा, कौन प्रशासी विभाग, कौन सी योजनाओं को लेगा और फिर उसका जो अनुरक्षण करायेगा यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, सभी विभाग विभिन्न कामों को देखते हैं, करते हैं । ऐसा नहीं है कि कोई काम सरकारी अगर हो रहा है तो कोई विभाग उसका कंट्रोलर नहीं है लेकिन चूंकि विधायक फंड के तहत यह नई नीतियां बनाई गई हैं कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वह मेन्टेनेंस करेगा उस विभाग को सौंपने का काम लोकल ऑफिसर कोआर्डिनेट करके उनको हस्तांतरण कर देंगे ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, यह पूछ रहा था कि प्रशासी विभाग तय हो गया है कौन योजना को कौन प्रशासी विभाग लेगा और वह लिस्ट, कम से कम तय नहीं हुआ है तो उसकी सूची कम से कम हमलोगों को मिल जाय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, सड़क विभाग है, सड़क को जायेगा । यह कम्युनिटी हॉल की बात कर रहे हैं वह भी कंसर्न विभाग को जायेगा ।

श्री संजय सरावगी : कौन सा कंसर्न विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वह आपका काम नहीं है ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, वह सूची हमलोगों को उपलब्ध करा दी जाय कि कौन सी योजना को कौन सा प्रशासी विभाग है और उसको कौन प्रशासी विभाग लेगा और अनुरक्षण करेगा यह सूची हमलोगों को उपलब्ध करा दी जाय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, जो डायरेक्शन होगा, वह माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, जब सदन में प्रश्न आया है तो सदन में जवाब भी होना चाहिए। महोदय, सभी सदन के माननीय सदस्य को यह चिंता है कोई सामुदायिक हमलोग बना देते हैं और जर्जर होकर गिर जाता है खतरा बना हुआ रहता है उसके मेन्टेनेंस का काम कौन विभाग करेगा यह माननीय सदस्य का प्रश्न है । रोड का जर्जर हो गया तो कौन विभाग उसको बनायेगा, माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट कर दें । सरकार का उत्तर आना चाहिए सदन में, कह रहे हैं कि सूचना दे दी जायेगी, कब सूचना दे दी जायेगी यह चलते सत्र में यदि सूचना दे दी जायेगी, तो यह भी माननीय मंत्री जी बता दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, गंभीर विषय है बस एक ही विषय है ।

अध्यक्ष : अब विषय तो आ ही गया है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, अन्य जगह भी कम्युनिटी हॉल गवर्नमेंट भी तो बनाती है उसका कंसर्न जो विभाग है डिटेल प्रश्न में निहित है ।

अध्यक्ष : चलते सत्र में जानकारी दे दीजियेगा ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : ठीक है ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, इसी में एक मामला और है ।

अध्यक्ष : अब हो गया । श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, जो सामुदायिक भवन जर्जर हो गया है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से, क्या वह प्रशासी विभाग उसको लेगा, उसकी योजना बनायेगा तो उसमें यह भी प्रावधान माननीय मंत्री जी कर दें, यही मेरा कहना था ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी चलते सदन में देंगे ।

श्री संजय सरावगी : ठीक है ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-23, श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र सं0-33 खजौली)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या-450 (1), दिनांक-15 अप्रील, 2017 के अनुसार राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों से पी0जी0/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों से बॉण्ड के तहत तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा लिया जाना है ।

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा पी0जी0/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों का परीक्षाफल माह दिसंबर, 2021 में प्रकाशित किया गया ।

तदालोक में 312 पी0जी0/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को विभागीय आदेश संख्या-80 (17), दिनांक-23 फरवरी, 2022 द्वारा राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में आवंटित किया गया है । शेष 138 चिकित्सकों के संस्थान आवंटन प्रक्रियागत है ।

2. उपर्युक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिये और पूरक संक्षिप्त में पूछिये । भूमिका में बहुत समय जाता है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : एकदम संक्षिप्त में पूछ रहे हैं । महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में इसे अस्वीकारात्मक माना गया है । मेरा मानना है कि कहीं से भी यह प्रश्न अस्वीकारात्मक नहीं है । माननीय मंत्री जी संवेदनशील हैं परंतु विभाग ने इसको अस्वीकारात्मक क्यों लिखा है जबकि जो प्रश्न में है उसी का उत्तर भी है और उत्तर स्पष्ट भी है लेकिन माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं महोदय कि जब 14 फरवरी को मैंने प्रश्न दिया, 23 फरवरी को इन्होंने 312 पी0जी0 डिप्लोमाधारियों का विभिन्न चिकित्सा संस्थानों को आवंटित कर दिया । 138 जो शेष उसमें बच गये हैं उसका माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रक्रियागत है तो यह प्रक्रिया कब तक समाप्त हो जायेगी, कब तक उसको चिकित्सा संस्थान मिल जायेगा क्योंकि मैंने प्रश्न में डाला

था कि अगस्त में परीक्षा हो गयी, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया और कहा कि दिसंबर, 2021 को परीक्षाफल प्रकाशित हुआ । तदनुसार 312 छात्रों को 23 फरवरी के पत्र के माध्यम से चिकित्सा संस्थान एलॉट हुआ तो 138 क्यों बच गये ? किन कारणों से शेष 138 बच गये और दूसरा, मेरा प्रश्न है इसी के साथ कि क्या उन छात्रों को जो मेरे प्रश्न में है उसको अमिट कर दिया गया है उसका उत्तर नहीं आया है कि वह छात्र परीक्षा के साथ ही अपनी छात्रवृत्ति से वंचित हो गया और वह जो तीन महीने लगभग, बाकी अगस्त से लेकर अभी तक चार-पांच महीने की जो उसकी छात्रवृत्ति की राशि है क्या उन छात्रों को मिलेगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : महोदय, मैंने अपने जवाब में हर चीज को बहुत स्पष्टता से लिखा है । 312 लोगों की नियुक्ति हुई, परीक्षा अगस्त में हुई, परिणाम आया है दिसंबर में, तो परिणाम आने के बाद ही नियुक्ति होगी न और नियुक्ति 312 करने के बाद 138 बचे हुये हैं यह जो पी0जी0 की डिग्री प्राप्त करते हैं इसमें दो तरह के लोग होते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र के लोग होते हैं और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लोग होते हैं । स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लोगों का जब पदस्थापन किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया भी अलग से अपनाई जाती है जो प्रक्रियाधीन है और अगले 15 दिनों में इनलोगों की भी नियुक्ति कर दी जायेगी । जो उन्होंने तीन महीना का विषय उठाया है उसको हम दिखवा लेते हैं।

अध्यक्ष : छात्रवृत्ति का, ठीक है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय,..

अध्यक्ष : अब हो गया, सकारात्मक जवाब है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, बस एक प्रश्न है । केवल छात्रों को बंध पत्र के आधार पर नियुक्ति होती है और हमने बंध पत्र का उपयोग किया है उनके उत्तर में बॉण्ड का उपयोग है, केवल हमने हिंदी कर दिया । इसलिए मेरा प्रश्न अस्वीकारात्मक हो जाय तो हिंदी इस सदन का चलन है ।

अध्यक्ष : ठीक है, माननीय मंत्री जी दिखवा लेंगे । डॉ0 रामानुज प्रसाद ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-24, डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र सं0-122 सोनपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अस्वीकारात्मक है ।

इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में जब भी कोई मरीज इमरजेंसी एवं ट्रामा सेंटर में उपचार हेतु आते हैं, तो इमरजेंसी एवं ट्रामा सेंटर में उपस्थित चिकित्सक द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया जाता है ।

बेड की उपलब्धता देखते हुये उसे भर्ती किया जाता है । बेड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मरीज का प्राथमिक उपचार करते हुये सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है । आई0जी0आई0एम0एस0 में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुये सरकार द्वारा निरंतर यहां शैय्याओं की संख्या बढ़ाई जा रही है । आई0जी0आई0एम0एस0 में 500 शैय्या के अस्पताल का निर्माण अंतिम चरण में है तथा 1200 शैय्याओं के अस्पताल निर्माण कार्य शुरू हो चुका है । आई0जी0आई0एम0एस0 में ही 210 शैय्या का का क्षेत्रीय चक्षु संस्थान निर्माणाधीन है। इस तरह अगले तीन वर्षों में संस्थान में लगभग कुल 3000 शैय्या उपलब्ध होंगे ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है तो उनसे कहते हुये उनके संज्ञान में देते हुये, सदन के संज्ञान में देते हुये सभी सदस्यों से जुड़ा हुआ मामला है कि यह जो हमारे प्रश्न में है कि आई0जी0आई0एम0एस0 में या इसी तरह के सुपर स्पेशलिटी जो संस्थान हमारे हैं उसमें जो मरीज जिलों से, प्रखंडों से, गांव से अस्पतालों से रेफर होकर आते हैं, तो मैं आई0जी0आई0एम0एस0 को यह चिन्हित किया हूं...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये । डायरेक्ट पूरक पूछिये, प्रश्न तो देख ही रहे हैं लोग ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : पूरक मैं पूछता हूं कि यह जो होता है और वहां मरीज को माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि देखा जाता है । देखा ही नहीं जाता है, सीधे कह दिया जाता है कि बेड उपलब्ध नहीं है और दलाल परिसर में घूमते रहते हैं जो अपने-अपने निजी क्लिनिकों में ले जाते हैं वहां मरीजों की लूट होती है और मरीज मरते हैं ।

अध्यक्ष : रामानुज बाबू, आप पूरक पूछिये, प्रश्न है, जवाब है, सब देख रहे हैं ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, पूरक यह है कि क्या सरकार ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जिससे डॉक्टर इलाज करे, मरीज को टेकअप कर उचित स्थान पर भेजे ।

(क्रमशः)

टर्न-3/सत्येन्द्र/04-03-22

डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्रमशः) दूसरा स्पेसिफिक डिजीज और सुपर स्पेशलिटी के नाम पर जिला अस्पताल से जो जानकारी के हिसाब से भेजे जाते हैं, मंत्री जी से हम जानना चाहेंगे कि क्या प्रतिदिन जो अस्पताल की स्थिति है, अस्पताल में अगर बेड नहीं है, तो इस बात को नेट पर डालेंगे और इसको डिस्पले बोर्ड पर अंकित करेंगे..

अध्यक्षः समय समाप्त हो रहा है, इतना लंबा पूरक पूछियेगा तो कैसे सब सदस्य का आयेगा? माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः महोदय, माननीय सदस्य की चिंता से विभाग भी वाकिफ है, मैं भी वाकिफ हूँ और चिंता भी जायज है और उस चिंता को दूर करने के लिए ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण आई0जी0आई0एम0एस0 के अंदर किया जा रहा है । जहां तक सवाल है आये हुए व्यक्तियों को इमरजेंसी में देखने और उपचार करने का, तो जो इमरजेंसी में आते हैं उनका प्राथमिक उपचार किया जाता है, लेकिन विभागवार जो बेड या आई0सी0यू0 है, बेड की उपलब्धता रहने पर ही मरीज को आई0पी0डी0 में लिया जाता है और उनका इलाज किया जाता है । आई0जी0आई0एम0एस0 की ख्याति विगत वर्षों में बढ़ी है, विश्वास बहुत बढ़ा है और आने वाले मरीजों की संख्या में भी बहुत इजाफा हुआ है । इसीलिए राज्य की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह निश्चय किया है कि आगे आने वाले समय में उस अस्पताल की क्षमता तीन हजार बेड की बनायी जायेगी और 500 बेड के अतिरिक्त अस्पताल भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, 1200 बेड के अस्पताल के निर्माण का कार्य लग गया है, 200 बेड के 186 करोड़ की लागत से रिजिनल इंस्टीच्यूट ऑफ ऑपथैल्मोलोजी उसके अंदर बन रहा है । कैंसर इंस्टीच्यूट नया बन गया है और अगले तीन वर्षों में आई0जी0आई0एम0एस0 की क्षमता 3 हजार बेड की होगी । आज लगभग 1130 बेड की है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता विभाग ने इसीलिए महसूस की कि जो माननीय सदस्य की चिंता है उसी चिंता के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी चीजों पर विमर्श कर के उस संस्थान को बड़ा करने का निर्णय लिया है ।

डॉ0 रामानुज प्रसादः अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि उसके परिसर में जो दलाल घूमते रहते हैं, इसका मैं स्पेसिफिक बतलाता हूँ, हमारे क्षेत्र का एक मरीज श्रीराम होस्पीटल से ले जाया गया वहां और ..

अध्यक्षः शेष अल्पसूचित प्रश्न के भी ऑनलाईन उत्तर आ चुके हैं ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, डॉ0 रामानुज प्रसाद जी ने जो प्रश्न उठाया है, माननीय मंत्री जी का जवाब ठीक है जो है सो, लेकिन दलाल जो परिसर में घूमते रहते हैं...

अध्यक्षः मंत्री जी, इसको संज्ञान में ले लें ।

आज 10 अल्पसूचित प्रश्न आये और सभी के उत्तर आ चुके हैं, शत प्रतिशत प्रश्नों का जवाब आया है । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 462(श्रीमती वीणा सिंह, क्षेत्र सं0 129,महनार)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 813(10) दिनांक 28-02-22 द्वारा मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना),बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, अस्पताल रोड शास्त्रीनगर, पटना से वैशाली जिलान्तर्गत प्रखंड जन्दाहा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चाहरदिवारी निर्माण/मरम्मति कराये जाने हेतु प्राक्कलन तैयार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

अध्यक्ष: उत्तर आया हुआ है ।

श्रीमती वीणा सिंह: जी।

तारांकित प्रश्न संख्या- 463(श्रीमती अनिता देवी,क्षेत्र सं0- 211,नोखा)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय: 1.स्वीकारात्मक है।

2-हीमोफिलिया के उपचार में आने वाले फैक्टर 8 एवं 9 का दर अनुबंध बी0एम0एस0आई0सी0एल0 में उपलब्ध है तथा List of essential drug list(ELD) में शामिल है । बी0एम0एस0आई0सी0एल0 द्वारा बिहार सरकार के सभी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में उनके मांग के आधार पर नियमित रूप से उपलब्ध करायी जा रही है । चालू वित्तीय वर्ष में फैक्टर 8 एवं 9 के जिलों में आपूर्त्ति तथा बी0एम0एस0आई0सी0एल0 में उपलब्धता की स्थिति निम्न प्रकार है:-

मद	जिलों को आपूर्त्ति मात्रा	बी0एम0एस0आई0सी0एल0 में उपलब्धता
फैक्टर 8	24047 वॉयल	7249 वॉयल
फैक्टर 9	1830 वॉयल	720 वॉयल

3- उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष: उत्तर आया हुआ है, पूरक पूछिये । एक आग्रह सभी माननीय सदस्य से करेंगे कि जब उत्तर आता है तो उसका पूरक आप पहले से ही तैयार कर लें और एक से दो सेनटेंस में ही पूरक पूछें, इससे ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की भागीदारी हो सकेगी ।

श्रीमती अनिता देवी: अध्यक्ष महोदय, यह जो हीमोफिलिया बीमारी है जिसकी सुई माननीय मंत्री स्वीकार किये हैं कि है, लेकिन यह सुई सभी जिलों में नहीं है, पटना में भी पूछा गया था..

अध्यक्ष: पूरक क्या है ?

श्रीमती अनिता देवी: पूरक है कि जो फैक्टर 9 सुई है न जिला में है, न पी0एम0सी0एच0में है और न एन0एम0सी0एच0 में है । जो इसके मरीज हैं, उनको बाहर से दूसरे अन्य राज्य

से लाकर लेना पड़ रहा है और यह सुई गरीब आदमी के बस के चीज नहीं है वह 15-16 हजार की सुई एक पड़ रही है । इसलिए जो गरीब आदमी है इस सुई ..

अध्यक्ष: उपलब्ध कराने के संबंध में न ?

श्रीमती अनिता देवी: हां, जिला में हो ताकि आम आदमी को मिले, जो इसके मरीज हैं उनको सहूलियत हो ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि फैक्टर 8 की दवाइयां 24 हजार 47 वॉयल आपूर्ति की गयी है इस वित्तीय वर्ष में और 7249 वॉयल हमारे स्टेट वेयर हाउस में आज भी हैं । इसी प्रकार फैक्टर 9 की 1830 वॉयल दवाईयां आपूर्ति की गयी हैं, 720 वॉयल आज भी हैं । माननीय सदस्या ने स्वयं भी माना है कि यह बहुत ही कीमती दवाई होती है और इतनी कीमती दवाई भी इतनी मात्रा में जिलों को आपूर्ति की गयी है । यह मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ यदि माननीय सदस्य को कोई स्पेसिफिक जानकारी है कि किसी मरीज को कोई कठिनाई हुई है तो वे मुझे उपलब्ध करायें ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 464 (श्री विनय कुमार,क्षेत्र सं0- 225,गुरूआ)

(लिखित उत्तर)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: जिला पदाधिकारी, गया से विभागीय ज्ञापांक 475 दिनांक 26-02-2022 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गयी है । पुन: दिनांक 28-02-22 एवं दिनांक 02-03-22 द्वारा विभागीय ई-मेल के माध्यम से स्मारित किया गया है ।

श्री विनय कुमार: पूछता हूँ ।

अध्यक्ष: पूरक पूछिये न ?

श्री विनय कुमार: महोदय, उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष: उत्तर ऑनलाईन आया हुआ है ।

श्री विनय कुमार: अभी तक महोदय है कि जिला पदाधिकारी को लेटर भेजे हैं, क्या उत्तर आया है पढ़कर बतला दें।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, गया से विभागीय ज्ञापांक 475 दिनांक 26-02-2022 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गयी है । पुन: दिनांक 28-02-22 एवं दिनांक 02-03-22 द्वारा विभागीय ई-मेल के माध्यम से स्मारित किया गया है ।

और माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन लगकर भिजवायें और निश्चित तौर पर ये पर्यटन स्थल जो है उसका विकास किया जायेगा।

(व्यवधान)

विधायक जी का काम भी है कि वहां लगकर भिजवायें ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी आप अपने स्तर से मंगवा लें ।

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री: ठीक है महोदय ।

श्री विनय कुमार: अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: अब हो गया, मंगवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 465(श्री राजेश कुमार गुप्ता,क्षेत्र सं0-208,सासाराम)

अध्यक्ष: यह आपदा प्रबंधन विभाग से गृह विभाग में स्थानांतरित है ।

श्रीमती रेणु देवी, उपमुख्यमंत्री: जी, यह गृह विभाग को स्थानांतरित हो गया है ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता: इसका उत्तर कब आयेगा महोदय ?

अध्यक्ष: जिस दिन गृह विभाग का रहेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-466(श्री प्रणव कुमार,क्षेत्र सं0-165,मुंगेर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: आंशिक स्वीकारात्मक । मुंगेर जिला स्थित बेलवा घाट से किला तक गंगा नदी के तट के किनारे वर्ष 1980 से 33 के0बी0 कर्णचौरा फीडर गुजरी है जिसके आसपास कलांतर में घनी आबादी बस गयी है । जान माल की सुरक्षा हेतु रिकंडक्टरिंग योजना अन्तर्गत दो पोलों के बीच इंटरमीडियेट पोल गाड़कर जर्जर तारों को बदल दिया गया है । गंगा के तटीय इलाकों एवं बाढ़ के दृष्टिगत अंडरग्राउंड केबलिंग तकनीकी एवं अनुरक्षण कारणों से फिजिवल नहीं है । विषयगत लाईन से जिला मुख्यालय एवं मुंगेर शहर को विद्युत आपूर्त्ति की जाती है ।

अध्यक्ष: पूरक पूछिये ।

श्री प्रणव कुमार: सर, बहुत ही घनी आबादी है वहां और हम चाहते हैं सदन के माध्यम से कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, वहां बराबर घटना घटती रहती है । विभाग को हम कई बार लिखे हैं, लेकिन विभाग के उत्तर से हमलोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: तार की व्यवस्था कर दी गयी है माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, फिर भी माननीय सदस्य कह रहे हैं तो हम दिखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-467(श्री कुमार सर्वजीत,क्षेत्र सं0- 229 बोधगया,अ0जा0)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री: 1-स्वीकारात्मक ।

2-स्वीकारात्मक ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 808(10)दिनांक 27-02-22 द्वारा मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना)बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, अस्पताल रोड, शास्त्रीनगर पटना से चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के आवास निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । आगामी वित्तीय वर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा ।

अध्यक्षः पूरक पूछिये।

श्री कुमार सर्वजीतः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया गया है इन्होंने लिखा है कि अगले वित्तीय वर्ष में निधि की उपलब्धता होगी तो हम इसको पूरा करेंगे । महोदय वह अंतराष्ट्रीय पर्यटक स्थल है और विश्वविख्यात वहां 10लाख विदेशी पर्यटक..

अध्यक्षः आप पूरक पूछिये । देखिये, आपलोग भूमिका बनाने में समय बहुत बर्बाद करते हैं जिस कारण कई सदस्य वंचित हो जाते हैं इसलिए सीधे पूरक पूछिये ।

श्री कुमार सर्वजीतः अध्यक्ष महोदय, क्या हुआ हमारे प्रश्न का?

अध्यक्षः चलिये बैठिये । श्री रामप्रवेश राय ।

श्री कुमार सर्वजीतः हम पूछेंगे नहीं तो आप इसको प्रोसीडिंग का पार्ट बनवा दीजिये ।

अध्यक्षः आपके कहने से ? बैठिये, आग्रह किये, हमने कहा कि अगला सदस्य का बढ़ेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-468(श्री रामप्रवेश राय,क्षेत्र सं0-100,बरौली)

(लिखित उत्तर)

श्री प्रमोद कुमार,मंत्रीः आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिला के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति वर्ष 2015 में एवं अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति वर्ष 2008 में की गयी है । वर्त्तमान समय में जिला पदाधिकारी,गोपालगंज से लोक अभियोजक एवं अपरलोक अभियोजक की नियुक्ति हेतु अनुशंसा सूची विभाग को प्राप्त हुई है जिसके आलोक में नियुक्ति सम्प्रति प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्षः पूरक पूछिये ।

श्री रामप्रवेश रायः अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिले में लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति के संबंध में मेरा प्रश्न था । माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि ...

अध्यक्षः जवाब आप देख लिये तो पूरक पूछिये ।

श्री रामप्रवेश राय: नियुक्ति हेतु अनुशंसा सूची विभाग को प्राप्त हुई है जिसके आलोक में नियुक्ति सम्प्रति प्रक्रियाधीन है । मैं माननीय मंत्री जी यह जानना चाहता हूँ कि डेढ़ वर्ष नई सरकार के गठन को हो गया, ये सम्प्रति प्रक्रियाधीन कबतक रखेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री: शीघ्र करा देंगे ।

श्री रामप्रवेश राय: कोई समय तो बताईए, यह पूरे राज्य का मामला है ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: विधान सभा के बाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 469(श्री इजहारूल हुसैन,क्षेत्र सं0-54 किशनगंज)

अध्यक्ष: आपका, ट्रांसफर हो गया है आपदा प्रबंधन विभाग से गृह विभाग में ।

श्री इजहारूल हुसैन: कबतक आयेगा सर?

अध्यक्ष: जिस दिन यह वर्ग रहेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या- 470(श्रीमती मंजू अग्रवाल,क्षेत्र सं0-226,शेरघाटी)

अध्यक्ष: यह भी स्थानांतरित है, वन एवं पर्यावरण विभाग में ।

टर्न-4/मधुप/04.03.2022

तारांकित प्रश्न संख्या-471 (श्री राजीव कुमार सिंह, क्षेत्र सं0 164, तारापुर)

(लिखित उत्तर)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : जिला पदाधिकारी, मुंगेर से विभागीय ज्ञापांक-493 दिनांक-28.02.2022 द्वारा प्रतिवेदन की मॉग की गई है । पुन: दिनांक-02.03.2022 द्वारा विभागीय ई-मेल के माध्यम से स्मारित किया गया है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । पूरक पूछिये ।

श्री राजीव कुमार सिंह : महोदय, माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुंगेर जिला के तारापुर के असरगंज प्रखंड में ढ़ोलपहाड़ी पहाड़ है, वहॉ स्वतंत्रता सेनानियों का कर्मस्थल रहा है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वहॉ उसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है या नहीं ?

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, उसे पर्यटक स्थल विकसित करने की योजना है और इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी, मुंगेर से विभागीय ज्ञापांत-493 दिनांक-28.02.2022 द्वारा प्रतिवेदन की मॉग की गई है । पुन: दिनांक-02.03.2022 को ई-मेल द्वारा भी प्रतिवेदन की मॉग की गई है । महोदय, उनका प्रतिवेदन आ जायेगा तो शीघ्र इसे पर्यटकीय स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–472 (श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, क्षेत्र सं0 216, जहानाबाद)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक ।

2. अस्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि सेवनन ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत है । जहॉ नियमित तौर पर श्रीमती रेणु कुमारी, ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण एवं प्रतिरक्षण संबंधी कार्य संचालिये किये जा रहे हैं । यहॉ से सदर अस्पताल की दूरी लगभग 6–7 कि0मी0 है । केवल बेहतर चिकित्सा हेतु सदर अस्पताल जहानाबाद जाना पड़ता है ।

3. उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, उत्तर आया है उसमें माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि वहॉ ए0एन0एम0 पदस्थापित है । लेकिन अपने क्षेत्र के भ्रमण के क्रम में जब ग्रामीणों ने शिकायत की तब जाकर हमने विधान सभा में सवाल किया है और वहॉ अभी तक कोई नर्स नहीं, सवाल करने के बाद शायद दो दिन से वहॉ ए0एन0एम0 जाने लगी हैं ।

अध्यक्ष महोदय, आखिर इस तरह कब तक उप स्वास्थ्य केन्द्रों की उपेक्षा होती रहेगी सरकार की ओर से, माननीय मंत्री महोदय ।

अध्यक्ष : यही पूरक है ?

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : जी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है कि व्यवस्था ठीक कर दी गई है तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ...

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : दो दिन से ही ए0एन0एम0 गई है, उप केन्द्र में दो दिन से।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : माननीय सदस्य स्वीकार कर रहे हैं ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : हम तो कह ही रहे हैं कि दो दिन से जा रही है ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : महोदय, मेरे पास तस्वीर भी है वहॉ ए0एन0एम0 के साथ सेन्टर की ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : नहीं महोदय, यह तो हम कह ही रहे हैं कि भेजा गया है। लेकिन क्षेत्र के भ्रमण के क्रम में....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके प्रश्न में ए0एन0एम0 की चर्चा है क्या ? एक बार देखें तो ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : चर्चा नहीं है, जवाब में है, महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी थोड़ा दो कदम आगे बढ़कर दे दिये ।

एक आग्रह करेंगे सभी सदस्यों से कि सरकार सजगता से जवाब शत-प्रतिशत प्रश्नों का दे रही है, हमारे माननीय विधायक भी सभी जवाब को पढ़कर पूरक की पूरी तैयारी करें और तभी हम अवसर देंगे, बिना पूरक के नहीं, चूंकि सदन का समय कीमती है, इसमें दूसरे के लिए भी अवसर आने का आप मौका दें ।

श्री नन्द किशोर यादव जी ।

(व्यवधान)

आपको भी तो मौका मिल ही जाता है । बैठ जाइये ।

श्री सत्यदेव राम : सरकार की सजगता इतनी है कि गलत जवाब भी दे रही है...

अध्यक्ष : गलत जवाब के बारे में आप पूरी प्रमाणिकता के साथ लिखकर उपलब्ध करायें, मंत्री जी कार्रवाई भी करेंगे । बैठिये, समय बर्बाद मत करिये । अब बैठ जाइये ।

माननीय नन्द किशोर यादव जी ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 473 (श्री नन्द किशोर यादव, क्षेत्र सं0 184, पटना साहिब)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक है ।

2. अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि श्री गुरू गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना में अधीक्षक के पद पर डॉ0 पशुपति प्रसाद सिंह का नियमित पदस्थापन विभागीय अधिसूचना संख्या-732(3), दिनांक- 22 सितम्बर, 2020 द्वारा किया गया था जो जुलाई, 2021 में सेवानिवृत्त हो गये हैं । वर्तमान में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना अधीक्षक, सदर अस्पताल, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में हैं ।

3. श्री गुरू गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना में अधीक्षक के पद पर पदस्थापन किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसे एक माह में पूर्ण कर दी जायेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, गुरू गोविन्द सिंह सदर अस्पताल में अधीक्षक का पदस्थापन एक माह में कर देंगे, ऐसा आश्वासन माननीय मंत्री जी ने दिया है और माननीय मंत्री जी ने जब कहा है तो जरूर पूरा करेंगे । इसलिये उनको बहुत-बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 474 (श्रीमती स्वर्णा सिंह, क्षेत्र सं0 79, गौड़ाबौराम)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि ए0एन0एम0 स्कूल, बिरौल, दरभंगा को विभागीय आदेश ज्ञापांक 1009(6), दिनांक- 23 सितम्बर, 2021 के द्वारा सत्र 2021-22 के लिये 60 सीटों पर नामांकन हेतु मान्यता प्रदान किया गया है । बी0सी0ई0सी0ई0 बोर्ड, पटना के द्वारा छात्राओं के नामांकन के लिये काउंसलिंग की प्रक्रिया की जा रही है जिसमें प्रथम काउंसलिंग में 41 छात्राओं का चयन किया गया है जिसमें से 17 छात्राओं का नामांकन किया जा चुका है, शेष छात्राओं का नामांकन प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह : धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सत्यदेव जी, देखिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या-475 (श्री छोटे लाल राय, क्षेत्र सं0 121, परसा)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । इन परिसरों की चाहरदिवारी नहीं होने के कारण आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेक्युरिटी गार्ड रखकर मरीजों एवं उनके जान-माल की सुरक्षा उपलब्ध करायी जाती है ।

2. अगले वित्तीय वर्ष में राशि की उपलब्धता के आधार पर इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की चाहरदिवारी के निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा ।

श्री छोटे लाल राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी तो आश्वासन दिये लेकिन कबतक करायेंगे ? ऐसा आश्वासन सुनते-सुनते तो....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपके आश्वासन पर भरोसा है उनको ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : माननीय सदस्य छोटे लाल राय जी से बहुत आत्मीय संबंध हैं, मैंने लिखा है प्राथमिकता पर करेंगे । प्रायोरिटी देंगे, हम लिखे हैं ।

श्री छोटे लाल राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी उसी रास्ते से जाते हैं, परसा, दरियापुर होते हुये ।

तारांकित प्रश्न संख्या-476 (श्री सत्यदेव राम, क्षेत्र सं0 107, दरौली(अ0जा0)

श्री सत्यदेव राम : उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष : आपका ट्रांसफर हो गया है गृह विभाग में ।

(व्यवधान)

सत्यदेव राम जी, भाई वीरेन्द्र जी कह रहे हैं कि गृह विभाग में इनका भी ट्रांसफर न हो जाय ।

श्री सत्यदेव राम : सरकार जो करेगी, वह तो मंजूर ही है । सरकार है और आपका आदेश है ।

अध्यक्ष : इतना विश्वास आपको है ?

श्री सत्यदेव राम : जी, विश्वास है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 477 (श्री जितेन्द्र कुमार राय, क्षेत्र सं0 117, मढौरा)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिले के सभी गाँवों में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (New) परियोजनाओं के तहत एल0टी0 लाईन में कवर तार का उपयोग करते हुये विद्युतीकरण का कार्य किया गया है ।

श्री जितेन्द्र कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जो उत्तर प्राप्त हुआ है, हमने प्रश्न किया था कि दर्जनों गाँव में कवर तार से विद्युतीकरण नहीं किया गया है । सरकार ने उत्तर दिया है कि कवर तार से प्रखंड के जो गाँव हैं विद्युतीकरण कर दिया गया है ।

मैं स्पेसिफिक आधा दर्जन गाँवों का नाम अभी इस सदन में बता सकता हूँ जहाँ पर कवर तार से विद्युतीकरण नहीं किया गया है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त प्रखंडों के दर्जनों गाँव में जहाँ घनी आबादी है वहाँ कवर तार की जगह खुला तार से विद्युतीकरण किया गया है ? महोदय, कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में कवर तार से नहीं किया गया है, खुला तार से ही विद्युतीकरण किया गया है । यही उत्तर है ।

श्री जितेन्द्र कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, गाँव में जो एल0टी0 लाईन है, सब जगह कवर तार से किया गया है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : कहीं कवर तार से नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष : कह रहे हैं कि कहीं कवर तार से नहीं किया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-478 (श्री रणविजय साहू, क्षेत्र सं0 135, मोरवा)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि अनुमंडलीय अस्पताल, पटोरी के भवन की स्थिति का आकलन करते हुये चाहरदिवारी के निर्माण हेतु निर्माण एजेन्सी

(BMSICL, Patna) को निदेशित किया गया है । शीघ्र ही निविदा निष्पादन के उपरान्त इसका निर्माण किया जायेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । पूरक पूछिये ।

श्री रणविजय साहू : पूरक है, सर । चाहरदिवारी नहीं रहने के कारण आवारा कुत्ते से लेकर जानवर और असामाजिक तत्व लगभग सभी जगह अब तो दलाल जो होते हैं अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में कहते हैं कि अच्छी सुविधा होगी, ईलाज होगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इस तरह का विषय उचित नहीं है । माननीय मंत्री जी को आप उम्रदराज कह कर, आज भी सबसे ज्यादा संवेदनशील है ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, मंत्री जी से आग्रह होगा कि इसकी समयसीमा निर्धारित करके बतायें और इसको जल्द करवा दें । यही मेरा पूरक है ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : महोदय, हमने जवाब में लिखा है कि निविदा निष्पादन करके उसका काम पूरा कर देंगे । निविदा निष्पादित होगी, तो तुरंत हो जायेगा अगले वित्तीय वर्ष में ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-479 (ई0 शशि भूषण सिंह, क्षेत्र सं0 11, सुगौली)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं किया जाता है । इन केन्द्रों द्वारा टीकाकरण एवं प्रसव पूर्व जॉच की जाती है । इस हेतु स्वास्थ्य उप केन्द्रों में ए0एन0एम0 की पदस्थापना की जाती है । सभी स्वास्थ्य उप केन्द्र में ए0एन0एम0 पदस्थापित एवं कार्यरत हैं ।

सुगौली विधान सभा अन्तर्गत भवन को हेल्थ वेलनेस सेन्टर के रूप में चिन्हित कर मरम्मति का कार्य किया जा रहा है तथा भेड़ियारी, चम्पापुर, छपरा बहास, भरगॉवा, डुमरी एवं लाल परसा के नये भवन के निर्माण का कार्य BMSICL द्वारा प्रारम्भ किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

ई0 शशि भूषण सिंह : अध्यक्ष महोदय, सुगौली में उप स्वास्थ्य केन्द्र का न कोई भवन है, न वहॉ कोई डॉक्टर रहता है । जवाब संलग्न है । कबतक वहॉ डॉक्टर उपलब्ध कराया जा सकता है और भवन बनवाया जा सकता है ? मंत्री जी बतायें ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य उप केन्द्र में चिकित्सकों का पदस्थापन नहीं किया जाता है ।

चिकित्सक वहॉ नहीं होते हैं, वहॉ ए0एन0एम0 होती हैं और उनके द्वारा टीकाकरण और अन्य सुविधाएँ लोगों को दी जाती है, प्रसव पूर्व की जॉच वगैरह होती है ।

सुगौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत भवन को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में चिन्हित किया गया है । मतलब, हमने यह तय किया है कि राज्य के अन्दर के स्वास्थ्य उप केन्द्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिये वहॉ उसको उन्नत करेंगे और हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में उसको उत्क्रमित किया जायेगा । उत्क्रमित करने का निर्णय विभाग के द्वारा ले लिया गया है और माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में जो उन्होंने प्रश्न किया है उसके अतिरिक्त भी हमने काम किया है, उसकी भी जानकारी दी है, भेड़ियारी, चम्पापुर, छपरा बहास, भरगॉवा, डुमरी एवं लाल परसा में भी नये भवन के निर्माण का कार्य BMSICL के द्वारा प्रारम्भ किया जा रहा है । माननीय सदस्य ने एक जगह की चिन्ता जाहिर की थी, हमने 6 जगह का उनका निराकरण कर दिया है ।

ई0 शशि भूषण सिंह : अभी कहीं नहीं भवन बन रहा है, न स्टार्ट हुआ है ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : मैंने कहा कि स्टार्ट होने जा रहा है । मैंने यह नहीं कहा कि स्टार्ट हो गया है ।

ई0 शशि भूषण सिंह : एक डॉक्टर वहॉ भेज दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-480 (श्री युसूफ सलाहउद्दीन, क्षेत्र सं0 76, सिमरी बख्तियारपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1. जिला योजना पदाधिकारी, सहरसा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि तत्कालीन माननीय स0वि0स0 श्री जफर आलम द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुमान्यता राशि से बेंच-डेस्क आपूर्ति की अनुशंसा की गयी थी ।

2. सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में बेंच-डेस्क आपूर्ति हेतु दिनांक-31.08.2020 को उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिलास्तरीय क्रय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से न्यूनतम दर (L1) पर निविदादाता को आपूर्ति हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया । उक्त के आलोक में आपूतिकर्ता द्वारा सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा क्षेत्र के सदर प्रखंड में 80 विद्यालय, महिषी प्रखंड में 21 विद्यालय एवं सलखुआ प्रखंड में 42 विद्यालय को मिलाकर कुल 143 विद्यालय में 20-20 जोड़ी बेंच-डेस्क की आपूर्ति की गयी ।

3. बेंच-डेस्क की आपूर्ति के उपरांत उप विकास आयुक्त, सहरसा-सह-अध्यक्ष जिलास्तरीय क्रय समिति द्वारा आपूर्ति की गयी बेंच-डेस्क के गुणवत्ता की जॉच हेतु त्रिस्तरीय जॉच समिति गठित की गयी । संयुक्त जॉच दल ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि आपूर्तिकर्त्ता द्वारा विद्यालयों में आपूर्ति किये गये बेंच-डेस्क की गुणवत्ता कार्यादेश में निर्धारित शर्त्तों के अनुरूप है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री युसूफ सलाहउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, हम विधान सभा कमिटी से जॉच की मॉग करते हैं क्योंकि जो एजेन्सी है उसने गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किया है । हम विधान सभा कमिटी से जॉच की मॉग करते हैं ।

अध्यक्ष : विधान सभा कमिटी से जॉच कराइयेगा, जब विभाग जॉच कर रहा है ? माननीय मंत्री जी।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जॉच तो डी0डी0सी0 ने कमिटी गठित करके करा ली है, जॉच में कमिटी ने सही पाया है और उसमें सीनियर अफसर लोग थे । फोटो के साथ स्पेसिफिक दें तो और जॉच करवा देंगे ।

टर्न-5/आजाद/04.03.2022

अध्यक्ष : बोलिए माननीय सदस्य ।

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : नहीं समझ में आया ।

अध्यक्ष : नहीं समझ में आया तो लगा लीजिए ईयर फोन ।

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : माननीय मंत्री जी की बात सुनाई नहीं दी ।

अध्यक्ष : डी0डी0सी0 ने कमिटी गठित कर जॉच करा दी है, माननीय मंत्री जी का कहना है।

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : उस जॉच से हमलोग संतुष्ट नहीं हैं अध्यक्ष महोदय, हड़बड़ी में वह जॉच करायी गयी है और ...

अध्यक्ष : और उसको सही माना गया है कि गड़बड़ी नहीं हुई है । आप उत्तर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं ?

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : पढ़े हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, अपने विधान सभा क्षेत्र का मामला उठाये हैं और बेंच-डेस्क जो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से माननीय विधायक अनुशंसा करते हैं । यदि ये जॉच से संतुष्ट नहीं हैं तो मुख्यालय स्तर से या दूसरे एजेंसी से जॉच करा दिया जाय महोदय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय सदस्य जो उस समय के थे, उन्होंने उसकी अनुशंसा की थी, ये नहीं किये थे, ये तो बाद में चुनाव जीतकर आये हैं । उसपर जॉच करने के

लिए डी0डी0सी0 ने एक कमिटी बनाकर अब उस कमिटी में महोदय देखा जाय, उस कमिटी में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, निदेशक, लेखा प्रशासन ये तीन सीनियर लोग थे, इन्होंने जॉच करके रिपोर्ट दी कि यह सही है ।

अध्यक्ष : ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे । श्री अजीत शर्मा ।

तारांकित प्रश्न सं0-481 (श्री अजीत शर्मा, क्षेत्र सं0-156,भागलपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : 1.अस्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित National Cancer Registry Programme Report 2020 (Posted on 27-07-2021) के अनुसार 1,03,371 लोगों के कैंसर रोग से ग्रस्त होने की संभावना व्यक्त की गई है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि (National Programme for Prevention and Control of Cancer Diabetes Cardiovascular Disease and Stroke) कार्यक्रम अंतर्गत राज्य में 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जाती है । जिसके अंतर्गत राज्य में Population Based Mass Screening for NCDs के माध्यम से कैंसर रोगियों की खोज एवं स्क्रीनिंग की जाती है । उक्त स्क्रीनिंग के क्रम में विगत 4 वर्षों में मुख कैंसर के पन्द्रह लाख तेरह हजार दो सौ अस्सी (15,13,280), स्तन कैंसर के छः लाख नवासी हजार नौ सौ सताईस (6,89,927), गर्भाशय कैंसर के तीन लाख उनतीस हजार छः सौ साठ (3,29,660) व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है ।

3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत NPCDCS कोषांग में इससे संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

राज्य में कैंसर के उपचार की सुविधा निम्नांकित संस्थानों में उपलबध कराई जा रही है :-

1. IGIMS, Patna में 138 करोड़ की लागत से कैंसर अस्पताल विकसित किया गया है एवं यहां कैंसर का उपचार किया जा रहा है ।

2. SKMCH परिसर में Homi Bhabha Cancer Research Institute.

3. Mahavir Cancer Sansthan, Patna

4. मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से कैंसर पीड़ितों के उपचार हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वर्ष 2022-23 में राज्य के चिन्हित 06जिलों (यथा-पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर एवं पूर्णिया) में Chemotherapy यूनिट की स्थापना करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से बजट की मांग की गई है । वर्तमान में बिहार राज्य के चौदह जिलों यथा औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, समस्तीपुर, सीवान, सुपौल एवं वैशाली में टाटा मेमोरियल हॉस्पीटल, मुजफ्फरपुर के सहयोग से तीनों प्रकार के सामान्य कैंसर (मुँह, स्तन एवं गर्भाशय का मुख) की स्क्रीनिंग प्रारंभिक जाँच एवं उससे बचाव हेतु आम जनमानस में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछा जाय ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, आई0जी0आई0एम0एस, एस0के0एम0सी0एच0 और महावीर कैंसर संस्थान में कुल मिलाकर कितने कैंसर रोगियों के ओ0पी0डी0 और आई0पी0डी0 में इलाज करने की क्षमता है, यह मेरा पहला पूरक है ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य के द्वारा पूछा गया है, उसमें इसका स्पेसीफिक जानकारी नहीं मांगी गयी है कि कितने मरीजों की जाँच की गई है, मैं कल ही उपलब्ध करा दूँगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अजीत शर्मा : सर, आपके ही जवाब में है कि इतना-इतना रोगियों के बारे में, इसलिए मैंने इसके बारे में सवाल किया ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : स्क्रीनिंग के बारे में, नॉट ट्रीटमेंट ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मेरा दूसरा पूरक है, सरकार के उत्तर के अनुसार चार वर्षों में मुख कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय कैंसर के 25,32,867 रोगी राज्य में चिन्हित हुए, यानी 6,33,616 और सरकार किस आधार पर कह रही है कि 1,03,000 संभावित है ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैंने जवाब में लिखा है कि नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, रिपोर्ट 2020 के आधार पर कहा है ।

श्री अजीत शर्मा : मेरा तीसरा पूरक है कि विगत चार वर्षों में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से कैंसर के इलाज के लिए राज्य के अस्पतालों में एवं राज्य के बाहर के अस्पतालों में कितना अनुदान दिया गया, यह बताने का माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : यह भी मैं अगले कार्य दिवस जो होगा, मैं बता दूँगा ।

आप सब लोगों की जानकारी के लिए, बहुत अच्छा विषय पर चर्चा छेड़ी है । मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना से राज्य के सभी गरीबों को जिनकी आय ढ़ाई लाख रू0 से कम होती है, उनको गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पैसा दिया

जाता है और खासकर कैंसर मरीज के रोगियों के लिए पैसा यह दिया जाता है । कैंसर के मरीजों में अलग-अलग तरह की राशि की जरूरत पड़ती है, किसी का ऑपरेशन होता है, किसी की सेकाई होती है और किसी की कीमोथेरापी होती है और एक बहुत बड़ी संख्या में प्रत्येक बुधवार को मुख्यालय के स्तर से वह राशि स्वीकृत करके अगले एक सप्ताह के अन्दर संबंधित अस्पतालों में भेजा जाता है । मैं तो माननीय सदस्यों को पूर्व में पत्र लिखकर कई बार आग्रह किया हूँ कि राज्य के गरीब लोगों को यह सुविधा दी जाय, इसके लिए आपके पास यदि कोई गरीब कैंसर मरीज किसी अस्पताल से आता है जो सी0जी0एच0एस0 के अन्दर हो, सेंट्रल हेल्थ गवर्नमेंट सिस्टम के अन्दर हो । वैसे सारे अस्पतालों में जो रोगी कैंसर का इलाज करायेगा तो उसको आर्थिक सहयोग बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है । मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि पहले कैंसर के इलाज के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग टाटा कैंसर होस्पीटल, मुम्बई जाते थे और जब मुम्बई जाते थे तो उनको इस सुविधा के तहत इस पैसे को प्राप्त करने में कठिनाई होती थी, चूँकि आवेदन फिर पटना आकर के देना पड़ता था । अब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज से डेढ़ साल पहले से हम सब लोगों ने व्यवस्था बना दी है कि टाटा कैंसर हॉस्पीटल, मुम्बई के अन्दर ही बिहार का एक अलग हेल्प डेस्क है और एक अन्डर सेक्रेटरी रैंक का उद्योग विभाग का एक अधिकारी है और वहीं पर उसको आर्थिक सहयोग कर देता है जो मरीज के परिजन वहां जाते हैं सहयोग मांगने के लिए तो सरकार बहुत ही संवेदनशील है और इस विषय को हम बहुत ही संवेदना से लोगों की सेवा करना चाहते हैं और लगातार करते हैं । इस राज्य के अन्दर भी चाहे महावीर कैंसर हॉस्पीटल हो, पारस कैंसर हॉस्पीटल हो, आई0जी0आई0एम0एस0 हो, एम्स हो या राज्य के बाहर के जो बड़े संस्थान जो सी0जी0एच0एस0 में हैं, उन सभी को देते हैं । जो संख्या और राशि पूछी है माननीय सदस्य ने , मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, इसको स्थगित किया जाय ।

अध्यक्ष : आपका तीन पूरक हो गया ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, जवाब नहीं आया ।

अध्यक्ष : बता दिये हैं कि जवाब भेज देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-482 (श्री शमीम अहमद, क्षेत्र सं0-12, नरकटिया)

श्री शमीम अहमद : महोदय, जवाब तो आया है लेकिन किस भाषा में है, यह समझ में नहीं आ रहा है ।

अध्यक्ष : भाषा बदल गई है ।

श्री शमीम अहमद : जी, देख लिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । हमलोगों के पास तो हिन्दी में जवाब आया है, आपके पास किस भाषा में है ?

इनका ठीक से नहीं निकाला है ।

श्री शमीम अहमद : महोदय, अभी निकाल कर लाये हैं ।

अध्यक्ष : उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से विभागीय ज्ञापांक 405, दिनांक 23.02.2022 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई है । पुनः दिनांक 26.02.2022 को ई-मेल के माध्यम से स्मारित किया गया है ।

2. पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चाती माई सहित सिंघासनी माई, लखौरा, मोतीझील, लाईट एंड साऊंड, सूर्य मंदिर, बेलवतिया कबीर पंथ मठ, यह सब योजना पर्यटन के दृष्टिकोण से फिजिबिलिटी का आकलन करते हुए पर्यटकीय विकास हेतु डी0पी0आर0 निर्माण कर उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना को पत्र प्रेषित किया गया था । बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा प्रारंभिक योजना का प्रतिवेदन तैयार किया गया है । नियमानुसार यह प्रतिवेदन जब प्राप्त हो जायेंगे तो राशि की उपलब्धता से पूर्वी चम्पारण का जो चयनित स्थल है, उसका शीघ्र अगले वित्तीय वर्ष में विकास कराया जायेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब बहुत सकारात्मक है लेकिन एक प्रश्न बार-बार मंत्री जी बोलते हैं कि जिला पदाधिकारी को अमुक पत्र दिया गया, स्मार पत्र दिया गया, लेकिन जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । यह महोदय, आपत्तिजनक है, यह सदन की अवमानना है । सदन में जब प्रश्न आता है, सदन में माननीय मंत्री जी बार-बार इस तरह का जवाब दे रहे हैं तो ऐसे जिला पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकार के सदन में कम से कम उत्तर नहीं आता है, ये कह रहे हैं कि बार-बार स्मार दे रहे हैं और उसका प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है तो वैसे जिला पदाधिकारी पर महोदय कार्रवाई होनी चाहिए, हम आसन से आग्रह करते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-483 (श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव,क्षेत्र सं0-90,मीनापुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से विभागीय ज्ञापांक-434, दिनांक

24.02.2022 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई है । पुनः दिनांक 26.02.2022 को ई-मेल के माध्यम से स्मारित किया गया है ।

पर्यटन रोडमैप प्रारूप की सूची में शामिल है ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, भष्मी देवी शक्ति पीठ है और लाखों श्रद्धालु लोग वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं और .....

अध्यक्ष : फिर भूमिका मत बनाइए, प्रश्न करिए ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : हमारे साथ भी वही है कि 24 तारीख को दिये हैं, 26 तारीख को स्मार दिये हैं, हमारे पास भी उत्तर में वही है ।

इसलिए हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि वो धर्मस्थल है, शक्तिपीठ है, उसका कब तक विकास करायेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, पुनः हम इसको देखवा लेंगे और बात करके जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगकर इसपर कार्रवाई करेंगे ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : कितने दिनों में कार्रवाई कर दीजियेगा ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठे-बैठे एक तो कौमेंट न करें ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : मंत्री जी से .....

अध्यक्ष : बैठ जाइए मुन्ना जी, एक मिनट । दूसरी चीज कि आपका कौमेंट कहीं न कहीं आपको कमजोर करता है । विधायिका को कमजोर करने वाला शब्द या मानसिकता कहीं न कहीं पदाधिकारियों के बीच अराजकता उत्पन्न करता है और यही गलती आज वर्षों से होते चली आ रही है । जिसके कारण पदाधिकारी आपके गंभीरता को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर पाता है । यह गलती न करें । जिस दिन विधायिका और विधायिका को मजबूत करने की मानसिकता सदन बना लेगा, सरकार इसको संरक्षित करेगी, पदाधिकारियों में अराजकता का भाव समाप्त हो जायेगा । इसलिए इसको आगे से ध्यान रखें ।

टर्न-6/शंभु/04.03.22

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि कितने दिन में वहां विकास का काम हो जायेगा ?

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : महोदय, ये पर्यटन रोड मैप में चयनित है जैसे ही प्रतिवेदन आयेगा और पर्यटन निगम से उसका डी0पी0आर0 तैयार कराके अगले वित्तीय वर्ष में राशि की उपलब्धता के आधार पर करा दिया जायेगा ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : यह तो हमको मालूम है महोदय कि वह चयनित है और आज नहीं दो साल पहले से चयनित है, लेकिन आज तक वहां कोई काम नहीं हुआ है । क्या माननीय मंत्री जी अगले वित्तीय वर्ष में वहां सौंदर्यीकरण करा देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : महोदय, हम तो कह ही रहे हैं कि प्रतिवेदन आयेगा, राशि की उपलब्धता होगी तो अगले वित्तीय वर्ष में करा देंगे ।

अध्यक्ष : प्रतिवेदन कहां से आयेगा ?

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन आता है ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : कब तक आ जायेगा ?

अध्यक्ष : एक मिनट, बैठिए । आपने कब पत्र भेजा है ?

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : हमने ज्ञापांक-434, दिनांक- 24.02.22 को भेजा है और फिर एक 26.02.22 को ईमेल द्वारा भेजे हैं । महोदय, दो-दो पत्र भेजा गया है ।

अध्यक्ष : आप इसकी जानकारी मंगाकर चलते सदन में सदन को अवगत करायें ।

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : जी ठीक है । सभी पत्र का चलते सत्र में सदन में हम अवगत करा देंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-484(श्री रामवृक्ष सदा)क्षेत्र सं0-148, अलौली(अ0जा0)</u>

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, 1- आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र, मेघौना का भवन 2020 में हस्तगत कराया गया है ।

2-अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मेघौना में दो सामान्य चिकित्सक, एक आयुष चिकित्सक, एक संविदा जी0एन0एम0 तथा एक ए0एन0एम0 पदस्थापित कार्यरत हैं । जिससे यहां के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । 24x7 की सुविधा सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध कराये जाने की सुविधा नहीं है, केवल वैसे कुछ चिन्हित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसमें प्रसव की सुविधा दी जा रही है वहां ही 24x7 की सुविधा उपलब्ध है । अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेघौना इस सूची में शामिल नहीं है । यहां किसी तरह के अतिक्रमण की कोई सूचना नहीं है ।

3-उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, माननीय मंत्री महोदय का जवाब संतोषजनक नहीं है । जो उत्तर दिया गया है वह सत्य से परे है । अब तक उस स्वास्थ्य उपकेन्द्र का उद्घाटन हुआ ही नहीं और क्षेत्रीय विधायक होने के नाते हमलोगों को पता भी नहीं है कि उस उप स्वास्थ्य केन्द्र का उद्घाटन हुआ है । इसलिए माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि कब उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन हुआ है तो क्षेत्रीय विधायक को जानकारी क्यों नहीं दिया गया, अगर नहीं दिया गया तो वहां प्रसव की क्यों नहीं व्यवस्था हो

रही है जबकि अलौली वहां से 12 कि0मी0 दूर है और प्रसव की व्यवस्था माननीय मंत्री जी कब तक करायेंगे यह जानना चाहते हैं ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, जवाब में लिखा हुआ है कि अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र मेघौना का भवन 2020 में हस्तगत कराया गया है और अभी वहां पर एक आयुष चिकित्सक, दो सामान्य चिकित्सक, एक संविदा पर जी0एन0एम0 और ए0एन0एम0 कार्यरत हैं । जो ए0पी0एच0सी0 होता है वह 24x7 सारे ए0पी0एच0सी0 नहीं काम करते हैं । जो चिन्हित सी0 सेक्शन का ए0पी0एच0सी0 होता है वहीं पर 24x7 सर्विसेज दी जाती है । वह स्वास्थ्य केन्द्र सी0 सेक्शन नहीं है । इसलिए वहां 24x7 नहीं है और बाकी जो सुविधाएं हैं वहां उपलब्ध करायी जा रही है । माननीय सदस्य वहां के हमारे माननीय विधायक हैं उनका कहना है कि अभी भी यह सुविधा उपलब्ध नहीं है । मेरे लिये यह बहुत गंभीर विषय है । मैं मुख्यालय स्तर से निदेशक प्रमुख से इसकी जॉच करवाऊंगा ।

श्री रामवृक्ष सदा : क्या मंत्री जी वहां प्रसव की व्यवस्था कराना चाहते हैं और चाहते हैं तो कब तक ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मैंने कहा कि अभी वह सुविधा तत्काल नहीं है ।

श्री रामवृक्ष सदा : हमलोगों के यहां जो उद्घाटन और शिलान्यास होता है उसमें नहीं बुलाया जाता है, न ही खबर की जाती है ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : ऐसा नहीं होता है । सरकार के स्तर पर निदेशित है, सुन लीजिए बात को । ये 2020 में जिस दिन हुआ है मैं उसको पता कर लेता हूँ, लेकिन सरकार का बहुत स्पष्ट निदेश है, मेरे विभाग का भी निदेश है कि जब भी कोई कहीं उद्घाटन या शिलान्यास होगा तो माननीय विधायक, माननीय सांसद को उसकी सूचना दी ही जाती है और उनसे आग्रह किया जाता है कि वे उपस्थित रहें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय मंत्री का जवाब गुमराह करनेवाला है । यह किसी माननीय विधायक को नहीं हम अपने बारे में बोल रहे हैं, सारे माननीय विधायक से पूछ लिया जाय कहीं भी माननीय विधायक को सभी विभाग में करीब-करीब प्रायः इग्नोर किया जाता है शिलान्यास उद्घाटन में । माननीय मंत्री जी इसकी जॉच करा लें कि कितने जगह शिलान्यास उद्घाटन में नहीं बुलाया गया है उसपर कार्रवाई हो । हम तो माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे आग्रह करना चाहेंगे । एक जगह के बारे में हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में दिया है- टेन प्लस टू हो या उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय हो उसमें भवन बन रहे हैं । हमने एक एक्सक्यूटिव इंजीनियर से कहा कि आपने शिलान्यास क्यों नहीं कराया तो कहा कि हम उद्घाटन कराये माननीय सदस्य से तो हम सस्पेंड हो गये । इसीलिए विधायक से शिलान्यास उद्घाटन का नहीं प्रावधान

है । ये शिक्षा विभाग के एक्सक्यूटिव इंजीनियर दरभंगा बोले, हम मंत्री जी से शिकायत भी किये लेकिन अभी तक उसपर कुछ नहीं हुआ । स्वास्थ्य विभाग में भी हमलोगों के क्षेत्र में जहां भी अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र हो या स्वास्थ्य केन्द्र हो कहीं शिलान्यास उद्घाटन में एम0एल0ए0 को स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया गया । यह घोर आपत्तिजनक है, यह विधायिका का अपमान है । माननीय मंत्री जी इसकी गंभीरता से जॉच करावें और जहां-जहां शिलान्यास उद्घाटन में नहीं बुलाया गया है उसपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, आसन से आग्रह है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, आप सदन के कस्टोडियन हैं । यह माननीय विधायकों का मामला है । चाहे किसी भी विभाग का कोई कार्यक्रम होता है शिलान्यास या उद्घाटन का तो स्थानीय माननीय विधायकों को वहां बुलाना चाहिए, लेकिन कई जगह, अधिकांश जगह नहीं बुलाया जाता है । यह अवमानना का मामला है । इस संबंध में आप आसन से निदेश देने का काम करें ताकि माननीय का सम्मान बच सके ।

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, यह शिलान्यास या उद्घाटन जो सत्तापक्ष के माननीय मंत्री जी हैं वे किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, माननीय मंत्री जी को सोचना चाहिए, जिम्मेवारी समझना चाहिए और उनको निश्चित रूप से स्थानीय विधायक को आमंत्रित करके अपने साथ लेकर के शिलान्यास या उद्घाटन करवाना चाहिए, लेकिन अब परंपरा बिल्कुल समाप्त हो रही है । इसलिए मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि निश्चित रूप से आज आप सत्ता में हैं, कल हम भी सत्ता में थे यह तो होते रहता है, लेकिन जो स्थिति बनी है उस स्थिति में सुधार होना चाहिए और मैं सरकार से और माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अगर सत्ता के विपरित जो माननीय सदस्य हैं उनको भी आप साथ में लेकर के ही कार्यक्रम करें ।

अध्यक्ष : ठीक है बैठ जाइये । अब इसी पर बहस हो ?

श्री आलोक मेहता : यह सिर्फ माननीय विधायकों के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला नहीं है । यदि कोई प्रोजेक्ट बनता है और बिना उद्घाटन कराये हुए हस्तांतरित कराया जाता है उसके बाद उसका पेमेंट भी हो जाता है । जब उद्घाटन होता है तो उसका एक तरह से सोशल औडिट भी हो जाती है कि इसकी गुणवत्ता कैसी है, लेकिन देखा जा रहा है कि जो प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रोजेक्ट किसी माननीय विधायक द्वारा अनुशंसित नहीं है वैसे तमाम प्रोजेक्ट में जो ठेकेदार होते हैं और जो पदाधिकारी होते हैं, लगता है कि उसमें समझौता है कि जल्दी-जल्दी काम खत्म करके हस्तांतरित कर दो, कोई जॉच नहीं, कोई सोशल औडिट नहीं और उसकी गुणवत्ता बाद में खराब दिखलायी पड़ती

है । ऐसे कई केस पंचायत भवन के मामले में क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं । हमारे यहां चार पंचायत में.....व्यवधान ।

अध्यक्ष : हो गया ।

श्री महबूब आलम : महोदय, इतनी अराजकता है कि बारसोई में सूचना प्रौद्योगिकी की एक बड़ी विशाल बिल्डिंग बनी और उसका चुपचाप उद्घाटन कर दिया, मुख्यमंत्री यहां से करते हैं, लेकिन वहां न किसी विधायक को जानकारी, न किसी सांसद को जानकारी यह सवाल है और महोदय, मेरे बारसोई प्रखंड में बेलवा पंचायत के बेलवा में आज छः साल से बना हुआ हेल्थ सब सेंटर है, उसका न उद्घाटन हुआ, न वह समर्पित हुआ और आज की तारीख में जो पांच बनना है सब हेल्थ सेंटर सभी विधान सभा क्षेत्र में उसी बेलवा में जहां एक बेहतर सब सेंटर बना हुआ है, जो चालू नहीं हुआ, जहां पर पसेरियों का अड्डा बन चुका है । महोदय, यह गंभीर मुद्दा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये । इस मामले को गंभीरता से आसन और सरकार ने सुना है । आप बैठ जाइये ।

श्री अजीत शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बताना चाहेंगे यह बात सही है कि कोई भी शिलान्यास हो, उद्घाटन हो कहीं भी किसी भी विधायक को सूचना नहीं दी जाती है, न बुलाया जाता है और अभी माननीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि आपलोगों का आचरण पदाधिकारियों को कंट्रोल करेगा, हमलोग तो आचरण रखते ही हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी सुनिए न, आप ही के लिए है सर। महोदय, कोई भी नहीं बुलाता है और आपको बता देते हैं कि शिलापट्ट में बोलिये कि विधायकों और सांसदों का नाम होगा तभी आपको प्रूफ मिलेगा कि वह बुलाया या नहीं बुलाया । अध्यक्ष महोदय, नाम भी उसमें होना चाहिए यह हम आपसे आग्रह करते हैं ।

टर्न-7/पुलकित/04.03.2022

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस विषय पर पहले भी प्रश्न उठा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में सदन के अंदर ही कहा कि शिलान्यास और उद्घाटन में माननीय विधायकों के प्रोटोकॉल का पालन करें और अभी विशेषाधिकार की बैठक में भी आप कई सदस्य थे, हमने दो-तीन चीजों पर स्पष्ट तौर पर कहा और अभी हमने पहले भी कहा कि विधायिका को मजबूत करना सुशासन को स्थापित करना है और विधायिका की मजबूती के लिए सभी सदस्य स्वयं भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश निर्गत

किया है जिन प्रोटोकॉल की कॉपी सभी पदाधिकारियों के यहां गयी हैं, उसका पालन करें । माननीय उपमुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं । माननीय उपमुख्यमंत्री जी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति से सुनें । मूल विषय से आप लोग भटकते क्यों है ? माननीय सदस्यगण, अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये । अब शांति से सुनिये ।

अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूर्व से ही निदेशित है और मंत्रिमंडल सचिवालय समय-समय पर यह निर्देश भी देता रहा है कि जो विधायिका के अंग हैं माननीय सांसद, माननीय विधायक, बिहार विधान मंडल के सभी सदस्यों के शिलान्यास, उद्घाटन और विशेष अवसर पर उन्हें सादर आमंत्रित करके और जो पट्ट है उसपर उनका नाम भी अंकित रहता है । सरकार की ओर से हम आपको आश्वस्त भी करते हैं कि अगर इस प्रकार से कोई अनदेखी की जाती है, तो सरकार इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब बहुत साफ-साफ शब्दों में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बता दिया है ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, फिर जाकर सो जायेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठीक है, अलग से समीक्षा होगी । हमारे स्तर से विशेषाधिकार कमेटी और प्रोटोकॉल की भी समीक्षा हो रही है । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं । अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ली जायेंगी ।

(व्यवधान)

अब हमसे पहले आप ही बोल लीजिये । सुनिये, धैर्य रखिये ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक- 04 मार्च, 2022 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

श्री महबूब आलम, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री महा नंद सिंह, श्री अरूण सिंह, श्री रामबली सिंह यादव, श्री छोटे लाल यादव, श्री छोटे लाल राय, श्री सुदामा प्रसाद, श्री मनोज मंजिल एवं श्री संदीप सौरभ ।

दूसरा, श्री अजीत शर्मा का है । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श एवं सरकार के उत्तर का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 171(1) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को....

(व्यवधान)

आप ही लोग बोल दिये तो हम क्या बोलें । आप ही लोग बोल दिये कि अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे । श्री मिश्री लाल यादव ।

श्री महबूब आलम : महोदय, यह गंभीर सूचना है ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, विधि-व्यवस्था का सवाल है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अमान्य कर दिया गया । सभी माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये ।

(इस अवसर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

सभी माननीय सदस्यों को बैठाइये । सभी सदस्यगण पहले बैठ जाइये, तभी हम इनको बोलने के लिए कहेंगे । नहीं, वेल में आने के बाद आपकी कोई बात प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगी । पहले सभी माननीय सदस्यगण को बैठाइये । आप जब तक व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक सदन में आपकी बात को सुना नहीं जायेगा । बैठ जाइये सब लोग । अपने स्थान पर जाकर बोलें । माननीय सदस्यगण, आपसे आग्रह है समूचे पोस्टर को बाहर करिये । पोस्टर को हटाइये । कोई भी पोस्टर लेकर अंदर प्रवेश नहीं करेंगे । गेट पर पहले से ही देख लें । जिनके हाथ में पोस्टर है, उनसे ले लीजिये । माननीय सदस्य, पोस्टर वापस दे दीजिये । बैठ जाइये, अपने आसन पर जाइये । अभी बैठ जाइये ।

आज 12.30 बजे तक ही समय है फिर भोजनावकाश हो जायेगा ।

(व्यवधान)

आप सबकी सहमति होगी तभी समय बढ़ेगा, अब बैठ जाइये । आप बोलिये । सभी सदस्य बैठ जाइये ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गये)

दो मिनट में अपनी बात को कहिये ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, गया जिला के बेलागंज थाना के अंतर्गत ग्राम आढ़तपुर जो माफियाओं और पुलिस प्रशासन से मिलीभगत के द्वारा 15.02.2022 को नाबालिग बच्ची के हाथ-पैर बांधकर पीटा गया साथ ही साथ उन सभी को 24 घंटे मेन थाना में बंद किया गया और सबको एक साथ जेल में अभी तक बंद रखा गया है। जबकि दर्जनों महिलाओं और दोषियों पर कार्रवाई भी नहीं हुई, आज तक सरकार ने उसको संज्ञान में भी नहीं लिया । हम चाहते हैं कि विधान सभा की कमेटी इसमें बहाल हो, जांच करे इसको और जो दोषी पदाधिकारी हैं उन पर उचित कार्रवाई करें । हुजूर, उसमें डी0एम0 और सीनियर एस0पी0 छुट्टी में चले गये, जो नीचे के पदाधिकारी थे बालू माफिया से बड़ी रकम लेकर, वसूल कर मिलीभगत से वहां आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और पुलिस गोली चलाई है और पूरे गांव को तहस-नहस कर दिया है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

यह उचित नहीं है । सरकार इसको संज्ञान में ले । बैठ जाइये । श्री मिश्री लाल यादव ।

(व्यवधान)

एक मिनट सुन लीजिये ।

शून्यकाल

श्री मिश्री लाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखण्ड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय गरौल में मात्र एक शिक्षक है । छात्रों की संख्या- 724 है । छात्रों के अनुपात में शिक्षक नहीं है ।

अतः उक्त विद्यालय में पठन-पाठन हेतु छात्रों के अनुपात में शिक्षक नियुक्ति की मांग सरकार से करता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मोहम्मद इजहार असफी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, बेलागंज की घटना का सरकार जवाब तो दे क्या कार्रवाई सरकार करने जा रही है, कितनी गंभीर घटना है ।

अध्यक्ष : सरकार संज्ञान में ली है, बैठ जाइये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा है, सदन के जवाब से प्रभावित होकर प्रशासन को दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर में विस्फोट हुआ है जिसमें एक दर्जन से अधिक लोग मरे हैं और कई घायल हुए हैं, कई लोगों के घर उजड़ गये हैं .. XXX

XXX - आसन के आदेशानुसार अंश को विलोपित किया गया ।

टर्न-8/अभिनीत/04.03.2022

श्री महबूब आलम : महोदय, सरकार जवाब तो दे कि क्या कार्रवाई करने जा रही है ?

अध्यक्ष : सरकार ने इस विषय को संज्ञान में लिया है । आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

बहुत ही दुःखद घटना है । सरकार ने संज्ञान में लिया है और पूरी जानकारी प्राप्त करके सरकार बतायेगी ।

(व्यवधान)

सरकार ने संज्ञान लिया है, पूरी जानकारी प्राप्त करके बतायेंगे ।

माननीय सदस्य, श्री मो0 इजहार असफी ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, पढ़ लेने दिया जाय ।

अध्यक्ष : अब जब विषय आ ही गया है, बिना पढ़े हुए ही आपलोगों ने सब बोल दिया, अब पढ़िएगा क्या ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं नियमापत्ति पर खड़ा हूं । अध्यक्ष महोदय, जब आसन की तरफ से...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब आसन कार्यस्थगन को नामंजूर करता है उसके बाद माननीय सदस्य का कोई हक नहीं है कि कार्यस्थगन को पढ़कर सदन के समक्ष रखें । यह तो आसन का अपमान हो रहा है ।

अध्यक्ष : आसन ने अनुमति नहीं दी है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : जब आसन ने अनुमति नहीं दी है तो फिर माननीय सदस्य पढ़ कैसे रहे हैं ?

अध्यक्ष : गलत है । वह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बन रहा है ।

(व्यवधान)

आप आगे बढ़िए, बोलिए मो0 इजहार असफी जी ।

श्री मो0 इजहार असफी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलांतर्गत कोचाधामन प्रखंड के मौधो और अनारकली अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनकर तैयार है परंतु अभी तक उक्त स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति नहीं हुई है ।

अतः मैं सरकार से उक्त दोनों स्वास्थ्य केंद्रों में अविलंब डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री संजय कुमार गुप्ता ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : महोदय, शिवहर जिलांतर्गत तरियानी प्रखंड के दुमा-हिरौता पंचायत के सीआरसी पोर्टल पर दुनियाही चक भगवती आता है, सरकार से मांग करता हूं कि सीआरसी पोर्टल पर दुमा-हिरौता का ही नाम अंकित हो ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपलोग पहले बैठ जाइये । माननीय सदस्यगण, पहले अपने-अपने स्थान पर बैठ जायं । माननीय उप मुख्यमंत्री जी संज्ञान से संबंधित बात को कह देंगे ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गये)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब आसन से नियमन हो चुका है कि सरकार इसको संज्ञान में ले, तो सरकार तो हमेशा आसन का सम्मान की है और सरकार स्वतः इसको संज्ञान में ले ली है । अध्यक्ष महोदय, वैसे भी सदन में जो

विषय शून्यकाल में और राज्य की कोई विशेष घटनाएं होती हैं और चर्चा होती है तो सरकार उसको वैसे भी गंभीरता से लेती है ।

अध्यक्ष : ठीक है, बहुत अच्छा ।

अब माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह ।

(व्यवधान)

ध्यानाकर्षण कमेटी को चला गया है ।

अब होने दीजिए, आप ही लोगों के हित का प्रश्न है । अरूण जी, बैठ जाइये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, एक मैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मंत्रीजी बोल रहे हैं, बैठ जाइये अजय जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आपने निर्देश दिया और सरकार संज्ञान में लेगी, लेकिन शून्यकाल समिति भी तो है, शून्यकाल की समिति भी उसको देखती है । सदन में जो बातें उठायी जाती हैं वह तो सरकार के संज्ञान में रहती ही हैं और अगर सरकार के ध्यान में नहीं रहे तो कमेटी भी देखती है । यूं भी अगर कोई घटना घटित होती है तो क्या सरकार खुद एक्शन नहीं लेती है ? हमें समझ में बात नहीं आती है, न भी मेम्बर उठावें, कितने दिनों बाद उठा रहे हैं । निश्चित रूप से आपका निर्देश...

(व्यवधान)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : बैठिए तो । बैठ जाइये ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । देखिए, इतना तो कम-से-कम समझिए कि जब माननीय मंत्री, सरकार से आप अपेक्षा रखते हैं कि जवाब आये, तो जो बोलते हैं उसे सुनिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आपका जब निर्देश हो गया, तो कैसे सरकार नहीं देखेगी, संज्ञान में कैसे नहीं लेगी ।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह ।

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, फोरलेन सड़क अथवा रेल मार्ग के लिए रैयती जमीन का अधिग्रहण होता है । राष्ट्रीय राजमार्ग से 200 मीटर के भीतर सर्किल रेट तय है ।

अतएव, राष्ट्रीय राजमार्ग से 200 मीटर के भीतर रैयतों की भूमि का मुआवजा तय सर्किल रेट के अनुरूप मिले इसकी मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलांतर्गत बेगूसराय में सरकार के द्वारा पेप्सीको बॉटलिंग प्लांट एवं इडेन स्मार्ट एग्रेटेक के द्वारा एथनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसमें नौकरी हेतु बेगूसराय जिला के स्थानीय आवेदकों को वांछित योग्यता पर प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दिलाने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलांतर्गत प्रखंड- बोखरा के ग्राम-बनौल में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 1117 (10), दिनांक- 27.02.2019 द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जनहित में चालू कराने की मांग करता हूं।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलांतर्गत फारबिसगंज नगर परिषद् से सटा सीताधार अवरूद्ध होने से बरसात के दिनों में प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण शहरवासियों को भारी तबाही उठानी पड़ती है, पूर्व में सरकार द्वारा कराये गये सर्वेक्षण का फलाफल नहीं निकलने के कारण बाढ़ को लेकर शहरवासी दहशत में हैं । जल निकासी की मांग सदन से करता हूं ।

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग को भेजे गये पत्र पत्रांक- 336/22, दिनांक- 06.01.2022 में वर्णित सड़कों का सरकार प्राथमिकता के आधार पर जनहित में निर्माण करावे ।

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, देश में सबसे ज्यादा बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों की 53.21 प्रतिशत कमी है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से 79 प्रतिशत लैब टेक्निशियन के 77.79 और फार्मासिस्ट के 71.68 पद खाली पड़े हैं । गरीब इलाज को तरस रहे हैं । अविलंब इन पदों पर नियुक्ति की मांग करता हूं ।

श्री अनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, दिनांक- 02.03.2022 को मेंजरगंज ब्लॉक के बसबिट्टा चौक पर सीमेंट व्यवसायी संदीप दास के घर लाखों की डकैती हुई । इस तरह की घटना बसबिट्टा, कन्हौली नेपाल बॉर्डर पर आम बात है । घटना के उचित कार्रवाई एवं बसबिट्टा चौक पर पुलिस चौकी की अविलंब स्थापना की मांग करता हूं ।

श्री निरंजन राय : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत कटरा प्रखंड के शिवदासपुर योजना बांध पर स्लूईस गेट का निर्माण नहीं होने से हजारों-हजार एकड़ भूमि जल-जमाव के कारण प्रत्येक वर्ष कृषि से वंचित हो जा रहे हैं । किसानों की क्षति की भरपाई हेतु उक्त बांध पर स्लूईस गेट के निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री छोटे लाल राय : अध्यक्ष महोदय, सारण जिलांतर्गत प्रखंड-परसा के ग्राम- बनौता एवं अन्याय, प्रखंड- दरियापुर के ग्राम- मगरपाल, टखा, खुशहालपुर एवं बरूआ में बाढ़ तथा बरसात के पानी से जल-जमाव हो जाता है । मैं सरकार से अनुरोधा करता हूं कि उक्त स्थानों पर हो रहे जल-जमाव के निदान की मांग करता हूं ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बांका जिलांतर्गत घोरैया प्रखंड के नवादा-घोरैया मुख्य पथ से बलियास गांव होते हुए अठपहरा गांव तक सड़क की स्थिति काफी खराब है जिससे आवागमन बाधित है । जनहित में उक्त सड़क की मरम्मति एवं कालीकरण कराने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी । ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति होगी तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं भी ली जायेंगी ।

माननीय सदस्य, श्री रत्नेश सादा अपनी सूचना को पढ़ें ।

टर्न-9/हेमन्त/04.03.2022

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री रत्नेश सादा, निरंजन कुमार मेहता एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, ''बिहार राज्य के 38 जिलों के सभी पंचायतों में बिहार सरकार की अनावाद जमीन उपलब्ध है । 38 जिलों के दलित, महादलित, अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को शव जलान में काफी कठिनाइयां हो रही हैं, कभी-कभी तो शव जलाने के दौरान मारपीट की घटनाएं हो जाती हैं ।

अतः जनहित में अनावाद जमीन को चिन्हित कर शवों को जलाने हेतु श्मशान की व्यवस्था करने के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह गृह विभाग को स्थानांतरित हो गया है ।

श्री रत्नेश सादा : कब तक इसका जवाब गृह विभाग देंगे ?

अध्यक्ष : चलते सदन में ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : इसमें समय दे दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी इसमें समय ले रहे हैं ।

सर्वश्री जनक सिंह, पन्ना लाल सिंह पटेल एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर दिनांक-28.01.2022 को फैसला देते हुए यह निर्णय दिया गया है कि पदोन्नति में आरक्षण का मापदण्ड राज्य और केंद्र सरकार तय करेगी, लेकिन उससे पहले उच्च पदों पर उचित प्रतिनिधित्व का सही आंकड़ा जुटाना आवश्यक होगा । वर्ष 2006 में नागराज मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संख्यात्मक डाटा एकत्र करने का आदेश दिया गया था, लेकिन 16 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा उचित प्रतिनिधित्व से संबंधित डाटा तैयार नहीं किया गया है जिसके कारण सभी प्रकार की पदोन्नति पर रोक लगी हुई है ।

अतः अविलम्ब संख्यात्मक डाटा एकत्र कर प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : इसमें समय दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप सबकी सहमति हो तो शून्यकाल आगे शुरू किया जाय ।

(सदन की सहमति हुई ।)

सदन की सहमति है । श्री पवन कुमार यादव, अपना शून्यकाल पढ़ें ।

श्री पवन कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव नगर में मोटर खराब होने एवं जलापूर्ति पाइप फटने के कारण बराबर कई दिनों तक जलापूर्ति बाधित रहती है, इसके स्थायी निदान हेतु पंप हाउस में अतिरिक्त मोटर लगाने एवं पंप हाउस से 200 मीटर पाइप अविलंब बदलने की मैं सरकार से मांग करता हूं ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार प्रशिक्षण पक्ष / संस्थान लिपीकीय संवर्ग नियमावली, 2011; बिहार प्रशिक्षण पक्ष / संस्थान लिपीकीय संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2014; बिहार प्रशिक्षण पक्ष / संस्थान लिपीकीय संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2015 एवं बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली, 2018 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : पुनः शून्यकाल । श्री राजेश कुमार गुप्ता ।

शेष शून्यकाल की सूचनाएं

श्री राजेश कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम अन्तर्गत गौरक्षणी मुहल्ला में शुभम कुमार, पिता- सिव पाल, उम्र-06 वर्ष का अपहरण दिनांक-17.12.2021 को हुआ और 28.12.2021 को उनकी हत्या कर दी गयी, पर आज तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई न मुआवजा ही मिला । सरकार हत्यारों की गिरफ्तारी कर मुआवजा दिलावे ।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के नरपतगंज नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड नम्बर-20 स्थित हनुमान मंदिर से नहर पर नरेश पासवान टोला होते हुए रामघाट रोड तक सड़क निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्रीमती संगीता कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मोहनियां विधान सभा अंतर्गत मोहनियां नगर में भभुआ रोड स्टेशन से आने वाली सड़क के सामने जी0टी0 रोड (एन0एच0-2) पर जनहित में अंडर पास निर्माण कराने की मांग करती हूं ।

श्री प्रणब कुमार : मुंगेर–खगड़िया रेल सह सड़क पुल का मुंगेर स्थित जीरो माइल का नामकरण बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पिछड़ों एवं अति पिछड़ों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जननायक चौक रखने की मांग करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, अनुमंडल अस्पताल महुआ में ब्लड बैंक, अल्ट्रासाउंड मशीन एवं डिजिटल एक्सरे लगाने की मांग करता हूं ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रस्तावित नगर निगम मोतिहारी के सर्किट हाउस चौक से मजुराहाँ गांव को जाने वाली सड़क में सुधीर महतो के घर से खापीटोला रामसुन्दर सिंह के घर होते हुए भक्तिन के घर तक सड़क जर्जर है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि सड़क का जनहित में निर्माण करावे ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर विधान सभा के कहारपुर भ्रैया, चोरहर, सिंहकुण्ड, लोकमानपुर, कालूचक विश्वपुरिया, ढोढिया–दादपुर गांव का कोशी नदी के द्वारा भीषण कटाव हो रहा है । स्थिति बहुत ही भयावह है ।

अतः सरकार से तुरंत कटाव रोकने हेतु ठोस कार्य कराने की मांग करता हूं।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला, अनुमंडल, प्रखण्ड, स्कूल के खेल मैदान सार्वजनिक स्थल मठमंदिर की जमीन भूमाफिया द्वारा अतिक्रमित है शेष जमीन हड़पने में लगे हैं ।

अतः मैं सरकार से पूर्णिया जिला के उक्त सभी खेल मैदान की घेराबंदी तथा मठमंदिर की जमीन का सीमांकन कर जनहित में स्कूल, अस्पताल खोलने की मांग करता हूं ।

श्री राज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, शामोह प्रखंड की भौगोलिक स्थिति एवं अनुमंडल मुख्यालय से दूरी को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज बनाने की वर्तमान नीति को शिथिल करते हुए शामोह प्रखंड में 1 डिग्री कॉलेज की स्थापना करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री अवध विहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों का 22 माह से वेतन भुगतान लंबित है, जिनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश से (34500 प्रशिक्षित शिक्षक) हुई थी । उनके परिवार भुखमरी के शिकार हैं । जनहित में बकाये वेतन का भुगतान करावे ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, राज्य भर के 10 वर्षों से न्यूनतम मानदेय पर कार्यरत निजी पशु टीका कर्मियों को कृषि सलाहकार के तर्ज पर पशु सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाय ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय, चेनारी विधानसभा अंतर्गत डीहरियां पंचायत के कैथी ग्राम के बेलवई नदी पर पुल न होने के चलते पियाकलां उच्च विद्यालय आने-जाने वाले छात्रों को पानी के रास्ते जान जोखिम में डाल कर गुजरना पड़ता है ।

अतः उक्त नदी पर पुल निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री सतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार में सरकार के द्वारा संचालित छात्रावास जैसे अम्बेडकर छात्रावास, बाबू जगजीवन छात्रावास, अल्पसंख्यक छात्रावास, जन नायक कर्पूरी ठाकुर व अन्य छात्रावास में पुस्तकालय स्थापित करने की मांग सदन से करता हूं ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, कई वर्षों से विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन जो 400 रु0 तक दिया जाता है । इतनी कम राशि से वह अपना जीवन-यापन भी ठीक ढंग से नहीं कर सकते । विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ाई जाय । इस हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

टर्न-10/धिरेन्द्र/04.03.2022

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला में नील गायों की संख्या बढ़ जाने के कारण लाखों एकड़ फसल नष्ट कर देते हैं, किसान तबाह हैं । नील गायों एवं घोड़परासों पर रोक लगाने की नीति बनावें तथा नुकसान फसल का मुआवजा दिलावें ।

श्री विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बेनीपुर प्रखंड के महिनाम गांव में रोदिया पीपर से अरूण झा के घर होते हुए सुकन पासवान के घर होते हुए सज्जनपुरा तक सड़क का निर्माण कराया जाय ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिये लगभग 224 एकड़ भूमि चयनित है । इसमें निर्माण कार्य के लिए 136.82 करोड़ रुपये एलौट किया गया है, जिसमें केवल 10 करोड़ रुपये खर्च हुए । शेष राशि 2014 से भुगतान नहीं होने के कारण ए॰एम॰यू॰ केन्द्र किशनगंज की स्थिति जस की तस बनी हुई है ।

अतः ए॰एम॰यू॰ फण्ड रिलीज करवाने की मांग करता हूँ ।

श्री राम चन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत बहेड़ी प्रखंड का निबंधन कार्यालय लहेरियासराय (सदर दरभंगा) था जिसे वर्तमान में निबंधन कार्यालय बहेड़ा कर दिया गया है, जो भौगोलिक एवं यातायात के दृष्टिकोण से बिल्कुल उचित नहीं है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि निबंधन कार्यालय को पुनः लहेरियासराय (सदर दरभंगा) किया जाय ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, आज जुम्मा का दिन है, सदन 12.30 बजे तक चलती है, इस परम्परा को आगे बढ़ाया जाय, इस परम्परा को निभाया जाय ।

अध्यक्ष : सहमति देने वाले में आप सब लोग हैं । माननीय सदस्यगण, हमने इसलिए पहले ही पूछा और पहले ही कह दिया और उसके बाद आपलोग सहमति कर, फिर आप राजनीति कीजियेगा तो दोनों विषय सदन में नहीं चलेंगे । फिर एक बार पूछ रहे हैं, सदन चलाने के पक्ष में हैं ? शून्यकाल लिया जाय ?

(व्यवधान)

आपके बगल में ही प्रह्लाद यादव जी कह रहे हैं कि शून्यकाल लिया जाय । ठीक है।

(सदन की सहमति हुई)

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, गया जिला के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विभाग में गत 15 वर्षों से जमे विभागाध्यक्ष एवं चिकित्सकों को तुरंत अन्यत्र स्थानों पर स्थानान्तरण किया जाय ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड अन्तर्गत लरूआ पंचायत में स्वास्थ्य उपकेन्द्र नहीं रहने के कारण प्राथमिक उपचार के लिए 14 किलोमीटर दूर मोरवा अस्पताल जाना पड़ता है ।

जनहित में लरूआ पंचायत में स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्थापित करने की मांग करता हूँ ।

श्री ऋषि कुमार : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा दाउदनगर प्रखण्ड स्थित डिहरा, तेजपुरा, सिपहां पन बिजली परियोजना का निर्माण वर्ष 2004 से विभागीय उदासीनता के कारण लम्बित है । मैं उपरोक्त पन बिजली परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूरा करने की सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत करगहर प्रखण्ड में निर्माणाधीन करगहर-रीवाँ पथ जो कि ग्राम-बभन बरेहटा से होकर गुजरता है, उक्त ग्राम को ग्राम-रीवाँ से जोड़ने हेतु सहदेई नदी पर एक आर॰सी॰सी॰ पुलिया बनाने के लिए सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री भरत बिन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अंतर्गत रामपुर प्रखंड के बेलाव बाजार में कोई सरकारी शुलभ शौचालय नहीं होने के कारण महिलाओं को काफी परेशानी होती है । सरकार से बेलाव बाजार में शौचालय निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, सदर अस्पताल, खगड़िया के प्रांगण लो-लेण्ड होने के कारण बरसात में पानी जमा हो जाती है तथा जल निकासी की आधुनिक व्यवस्था की कमी है । सदर अस्पताल, खगड़िया के प्रांगण की मिट्टी भराई के साथ ऊँचीकरण और जल निकासी हेतु आधुनिक नाला निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, अरवल जिला में राजकीयकृत 39 उच्च विद्यालय में रात्रि प्रहरी के लिए मानदेय नहीं मिलता है जबकि उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में सरकार मानदेय देती है । सरकार से उच्च विद्यालय में रात्रि प्रहरी को मानदेय देने की मांग करता हूँ ।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, 60 साल पुराने इंटर कॉलेज, गढ़हारा को बंद करने का फैसला रेल मंत्रालय ने किया है ।

अतः उक्त इंटर कॉलेज को राज्य सरकार के अधीन संचालित करने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जिनको जुम्मे की नवाज अदा करने के लिए जाना है, उनका पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा और आगे आपकी सहमति हो तो उनको प्राथमिकता दे दी जायेगी । क्या ?

(सदन की सहमति हुई कि पढ़ा हुआ मान लिया जाय)

पढ़ा हुआ मान लिया जाता है और आगे उनको सहमति दे दी जाती है ताकि सदस्य का जो शून्यकाल है....

(व्यवधान)

आपकी और सबकी भावना को देखते हुए ऐसा किया गया ।

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, लक्खीसराय जिलान्तर्गत सूर्यगढ़ा थाना की पुलिस रात के 12 बजे निस्तागाँव में घर का दरवाजा तोड़कर काजल देवी, पति-प्रमोद यादव वगैरह की गाली-ग्लौज, मारपीट एवं दुर्व्यवहार किया गया और झूठा केस सूर्यगढ़ा कांड संख्या-52/2022 किया गया ।

अतः घटना की उच्चस्तरीय जाँच सरकार से करावाने की मांग करता हूँ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत ग्राम-लाडू एवं कोशिला के बीच निरंजना नदी पर पुल नहीं है, जिसके अभाव में आम जनों को घोर कठिनाई होती है । अति महत्वपूर्ण एवं जनहित में पुल का निर्माण कराने की मांग सदन से करती हूँ ।

श्री फते बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला में सरकार की बी॰एड॰ कॉलेज नहीं है ।

अतः रोहतास जिला अन्तर्गत डिहरी में बी॰एड॰ कॉलेज बनवाने के लिए सरकार से मांग करता हूँ ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, सदर अस्पताल, हाजीपुर में नौ साल पहले कार्डियक केयर यूनिट (सी॰सी॰यू॰) खोला गया परन्तु आज तक चालू नहीं हुआ है क्योंकि आधारभूत संरचना एवं विशेषज्ञ चिकित्सक का अभाव है ।

अतः सदर अस्पताल स्थित सी॰सी॰यू॰ में आवश्यक आधारभूत संरचनाएं एवं विशेषज्ञ चिकित्सक का पदस्थापन कर सी॰सी॰यू॰ चालू किया जाय ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखण्डान्तर्गत एन0एच0-28 चाँदचौर स्कूल से नाजिरगंज स्टेशन होते हुए नाजिरपुर हाट तक सड़क अत्यधिक जर्जर स्थिति में है । मैं जनहित में मांग करता हूँ कि उक्त सड़क का शीघ्र चौड़ीकरण एवं जीर्णोद्धार कराया जाय ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, 2015 में बिहार सरकार द्वारा नर्सरी से स्नातकोत्तर तक छात्राओं और एससी एसटी छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा देने की घोषण की गई । इतने दिन बाद भी घोषणा पूरी नहीं हुई । बिहार के सभी छात्राओं एवं एससी एसटी छात्रों को नर्सरी से स्नातकोत्तर तक नि:शुल्क शिक्षा देने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती बीना सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिलान्तर्गत महनार प्रखण्ड में चयनित शिक्षकों को अभी तक नियोजन पत्र नहीं मिला है, शिक्षक अभ्यार्थियों को जल्द से जल्द नियोजन पत्र देने और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की मैं सरकार से मांग करती हूँ ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, पटना-गया-डोभी (एन०एच०-83) परियोजना के अन्तर्गत खपरैलचक, थाना नं०-96 में पईन (प्लॉट नं०-105) पर अंडर पास निर्माण करने के लिए राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग करता हूँ ।

टर्न-11/संगीता/04.03.2022

श्री सुर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय के बलिया से रोसरा भाया डंडारी बखरी, गढ़पुरा सड़क के चौड़ीकरण से पूर्वी और उत्तरी बिहार की दूरी 40 कि0मी0 कम हो जाएगी और एन0एच0 से गाड़ियों का दबाव भी घटेगा, उक्त सड़क का चौड़ीकरण और स्टेट हाइवे का दर्जा देने की मांग करता हूं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों की हत्या की घटनाएं अत्यधिक हो रही हैं । इनको सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदत्त नहीं है ।

अत: पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख एवं जिला परिषद् सदस्य को अंगरक्षक प्रदान किये जाने की मांग करता हूं ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, बेतिया मनुआपुल भाया- योगापट्टी नवलपुर रतवल पथ को शीघ्र यातायात योग्य बनवाने की मांग मैं सदन से करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

मोहम्मद इसराईल मंसुरी : अध्यक्ष महोदय, उर्दू राज्य की दूसरी कार्यालयी भाषा है, मगर मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत समाहरणालय के मुख्य द्वार पर सिर्फ हिन्दी भाषा का प्रयोग

हुआ है और पर्याप्त जगह भी उपलब्ध है । अतः उर्दू भाषा का भी प्रयोग करते हुए समाहरणालय अंकित अतिशीघ्र कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री सुदामा प्रसाद ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्रीमती मीना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, कार्य अंचल दरभंगा अन्तर्गत मधुबनी जिला में परमानेन्ट रेस्टोरेशन का कार्य माह अक्टूबर, 2021 में पूरा होने के बावजूद अबतक संवेदकों को भुगतान संबंधी कार्रवाई नहीं की गयी है ।

अतः सरकार से उक्त कार्य हेतु संवेदकों को यथाशीघ्र भुगताने कराने की मांग करती हूं ।

श्रीमती भागीरथी देवी : अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखण्ड गौनहा के पंचायत मझरिया के ग्राम पटखौली से महेशपुर जाने वाली कच्ची पथ का पक्कीकरण कराने की मांग करती हूं ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज नगर परिषद् में दुर्घटना एवं आपराधिक घटना को देखते हुए नगर में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने की मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूं ।

अध्यक्ष : श्री संदीप सौरभ ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत गोविन्दगंज विधानसभा में माह फरवरी, 2022 में ओलावृष्टि के कारण किसानों द्वारा हजारों एकड़ में लगाया गया सरसों, आलू, गेहूं, मसूर व अन्य फसल नष्ट हो गया है ।

अतः मैं सदन से इसकी जांच कराकर उनकी फसल क्षति का मुआवजा दिलाने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री अरूण सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी सरकारी वेतन भोगी अपने-अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं और अपना एवं अपने परिवार का ईलाज सरकारी अस्पताल में करायें । जिसके कार्यान्वयन के लिए मैं सरकार से ठोस कानून बनाने की मांग करता हूं ।

श्री मोहम्मद कामरान : नवादा जिला के एन0एच0-31 पर आकस्मिक दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को शीघ्र चिकित्सा हेतु ट्रामा सेंटर का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के सुलतानगंज प्रखंड के असियाचक पंचायत के मंझली गांव के किसानों के बोरिंग तक यथाशीघ्र विद्युत आपूर्ति कराया जाय ।

श्री शमीम अहमद : पूर्वी चम्पारण जिला के बनकटवा प्रखंड अन्तर्गत बनकटवा नहर चौक से झझरा तक काफी जर्जर सड़क है जिससे आमजन को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उक्त सड़क शीघ्र निर्माण करवाया जाय ।

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, शेखपुरा जिला के जय कुमार पिता श्री विजय कुमार, मो0-बंगालीपर, आशीष आनंद, पिता श्री सुभाष सिंह, ग्राम-डीहकुसुम्भा, दानिश खान, पिता-मो0 राशिद खान, चरुआवा, अंजन कुमार, पिता-मनोज कुमार, ग्राम-परसोंबीघा सहित सभी भारतीय छात्र को यूक्रेन से सुरक्षित भारत वापसी हेतु केन्द्र सरकार से प्रस्ताव भेजने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल कर संवैधानिक दर्जा दिलावे खातिर हम बिहार सरकार से केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे के मांग कर तानी ।

श्री मोतीलाल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 में सीतामढ़ी जिला के रीगा सहित विभिन्न प्रखंडों में अतिवृष्टि, बाढ़ एवं जल जमाव के कारण खरीफ फसल क्षति होने के एवज में ऑनलाईन आवेदन लेने के उपरांत फसल क्षति वाले किसानों को अनुदान मिला, किन्तु जो किसान बाढ़ एवं जल जमाव के कारण रोपनी नहीं कर सके, उसे कोई अनुदान नहीं मिला । अतः वैसे किसानों को भी अनुदान की राशि मिले ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, बिहार में आंगनबाड़ी सेविका को 5950 रुपया एवं सहायिका को 2975 रुपया मानदेय दिया जाता है जबकि दिल्ली सरकार द्वारा सेविका को 12,720 रुपया एवं सहायिका को 5610 रुपया दिया जाता है ।

मैं राज्य सरकार से दिल्ली की तर्ज पर बिहार में सेविका को 12720 एवं सहायिका को 5610 मानदेय देने की मांग करता हूं ।

श्री महबूब आलम : कटिहार जिलान्तर्गत कदवा विधान सभा की क्षेत्र की जनता को सुधानी होकर बारसोई अनुमंडल तक पहुंचने के लिए कोटा-कसवाटोली धार को नाव से पार करना पड़ता है । पुल के अभाव में जनता को अनुमंडल की जनता को 40 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है, पुल निर्माण की मांग करता हूं ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय शेरघाटी में पदस्थापित पुरूष प्रभारी प्राचार्य के कारण नामांकित छात्राओं के साथ-साथ महिला शिक्षिकाओं को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है । उक्त विद्यालय में महिला प्राचार्य की नियुक्ति की मांग करती हूं ।

श्री प्रेम शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुण्ठपुर प्रखण्ड मुख्यालय से अत्यधिक दूरी पर डिग्री महाविद्यालय अवस्थित होने से इस क्षेत्र के उच्च शिक्षा से मरहूम छात्रों को उच्च शिक्षा मुहैया कराने हेतु डिग्री महाविद्यालय की स्थापना जनहित में शीघ्र कराने की मांग करता हूं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, राज्य में शराब बेचने एवं पीने वालों पर मुकदमा न्यायालय एवं कारा पर बढ़ते दबाव को ध्यान में रखकर मुकदमों के शीघ्र निपटारा हेतु अतिरिक्त न्यायालय एवं कारा की समुचित व्यवस्था की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आधुनिक हिन्दी साहित्य के महान साहित्यकार, उपन्यासकार, कथा शिल्पी, स्वतंत्रता सेनानी एवं महान चिन्तक श्रद्धेय फणीश्वर रेणु जी की जयन्ती है । उन्होंने अपनी विरल लेखन शैली, अनुपम अलौकिक कल्पना शक्ति और मोहिनी आंचलिक मिठास से अपने शब्दों में तत्कालीन समाज का ऐसा यथार्थवादी चित्रण किया है, जिससे उनकी रचना देश और काल की सीमा से परे होकर आज भी हमें उस समाज की पीड़ा और जिजीविषा से अवगत कराती है । उनका साहित्य हमारी प्रेरणा है तथा वह हमारी समृद्ध बौद्धिक विरासत हैं । मैं पूरे सदन की ओर से उनकी जयन्ती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं ।

माननीय सदस्यगण, आज सभी विकारों से मुक्त करने वाली प्रकृति को सींचने वाली आदिशक्ति माँ काली के अनन्य भक्त एवं स्वामी विवेकानन्द जी के गुरू श्रद्धेय स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जयन्ती है । जिनका मानना था कि जो व्यक्ति दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करता है वह स्वयं के लिए अच्छे का निर्माण कर रहा होता है । जिनका साधनामय व्यक्तित्व और सत्कर्म आज भी हमारे लिए प्रेरक और प्रासंगिक है । मैं अपने तथा पूरे सदन की ओर से ऐसे महान साधक संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को उनकी जयन्ती पर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं ।

अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न-12/सुरज/04.03.2022

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर दिनांक- 03 मार्च, 2022 से जारी सामान्य विमर्श अब प्रारंभ होगा । नेता विरोधी दल अपना पक्ष रखें आपका समय 65 मिनट है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 के बजट को लेकर के वाद-विवाद में बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और जब भी बजट आता है किसी राज्य का या देश का, तो पहले ऐसा देखा जाता था कि लोगों में एक्साइटमेंट होता था, उत्सुकता होती थी जानने के लिए कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार का अगर बजट हो तो केन्द्र सरकार देश के लोगों के लिए क्या दे रही है और किस दिशा में आने वाले समय में जो पांच साल का होता है, क्या काम करेगी, लेकिन हाल में ही आजकल जो देखने को मिल रहा है अब लोगों को उम्मीद और विश्वास नहीं रह गया । अब बजट जो है, चाहे भारत सरकार का भी बजट आता है तो उसमें पहले रेलवे का अलग होता था और आम बजट जो होता था वह अलग होता था । रेलवे को तो हटा ही दिया गया, खत्म ही कर दिया गया । अब जब भारत सरकार का भी बजट आता है तो लोगों को पता नहीं चलता है क्या बजट में आया और बिहार सरकार का बजट आया है तो इस पर कई सहयोगियों ने ही उप मुख्यमंत्री जी के दल के ही प्रदेश अध्यक्ष ने कई बार इस पर सवाल भी उठाया कि बजट का पैसा तो खर्च ही नहीं हो पाता है, जो सच्चाई है और हमलोग अगर सेन्ट्रल एजेंसियों की बात करें, अपनी नहीं चाहे नीति आयोग हो, चाहे सी0ए0जी0 हो या और जितनी भी संस्थाएं हैं जो आकलन करती रहती हैं और भी एजेंसियां जो हैं जो लगातार रिसर्च करती रहती हैं, हकीकत जो है वह बताने का काम करती है । अगर वह देखें तो बड़ा निंदनीय लगता है बिहार का बजट, लगातार जिस तरह से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, लोग जो हैं उम्मीद खो बैठे हैं, लोगों की अब दिलचस्पी नहीं रह गई, उनको केवल लगता है कि यह कागज है और पढ़ दिया जाता है लेकिन गांव-देहात, गली-कूचों तक जो भी योजनाएं हैं या जो सही काम है वह नहीं पहुंच पाता । चाहे किसानों की बात करें, चाहे मजदूरों की बात करें, चाहे गरीबों की बात करें, चाहे नौजवानों की बात करें, चाहे रोजगार के सवाल की बात करें, चाहे इंडस्ट्री की बात करें या एजुकेशन की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ की बात करें तो कहीं

भी आप देखियेगा, लोग जो हैं, निराश हैं और लोगों में एक आक्रोश जो है वह पैदा होता जा रहा है । यहां तक कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वह भी परेशान हैं, हताश हैं । अब उप मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, बजट लगभग जो है, 2 लाख 37-38 हजार करोड़ का उन्होंने पेश किया । हमने लगातार जो है बजट को दिखवाया कि बजट में नया क्या है और पिछली बार के बजट में कितना खर्च हुआ और कितना काम हुआ । हालांकि बजट की बात की जाय तो its about revenue or expenditure मतलब पैसा आयेगा कहां से, कैसे आयेगा और जो पैसा आयेगा उसको हम खर्च कहां करेंगे, किस दिशा में करेंगे, किन योजनाओं के तहत करेंगे, ये पूरा होता है महोदय बजट । अध्यक्ष महोदय, अब आप शायरी पसंद करते हैं तो हम इस बार शायरी अच्छी-खासी लेकर आये हैं और अंत में जो है कहानी के तौर पर वह भी हम बात करेंगे तो महोदय हम पहली शायरी अगर कहें तो

''तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है
मगर ये आंकड़े झूठे हैं यह दावा किताबी है ।''

महोदय, हम अपनी बात नहीं जो अखबारों में जो चर्चाएं चली हैं, जो बातें चली हैं अब इस पर जरा गौर करें । शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में केरल सबसे अच्छा बिहार सबसे खराब, यह हकीकत है । यह तो जितनी भी एजेंसियां हैं उन सबकी ही रिपोर्ट है जो हम आपके सामने लाना चाहते हैं । बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल अव्वल बिहार सबसे नीचे । महोदय, आधारभूत साक्षरता सूचकांक में अगर फाउन्डेशनल लिटरेसी इंडेक्स में बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर बिहार सबसे नीचे । यह देखिये महोदय, सभी राज्यों को 17 मानकों पर आंका बिहार 92 अंक के साथ देश में सबसे निचले पायदान पर । महोदय, आप देखियेगा रिपोर्ट देश के सबसे ज्यादा ग्रेजुएट जो हैं वह बेरोजगार हैं । How much do farmer earns मतलब कि किसान की कितनी आय होती है, बिहार उसमें सबसे निचले पायदान पर है यानी बिहार के किसान की आय जो है देश भर में सबसे कम है । आप देखियेगा कि सी0एन0आई0ई0 का खुलासा बिहार में 23 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मतलब 23 राज्यों में देखा जायेगा तो बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है । अभी गरीबी न्यूट्रिशियन, मैटरनल हेल्थ्स, स्कूल इंडेक्स, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग और फ्यूल के मामले में बिहार देश में सबसे नीचे है । नीति आयोग की रिपोर्ट में भी देखियेगा सारा जो है बिहार को स्कोर ही नहीं मिला 6 सबसे नीचे, हर जगह यही है । डेवलपमेंट इंडेक्स में देखा जाय तो बॉटम 5 स्टेट्स में बिहार सबसे नीचे । अब इसपर ज्यादा कुछ नहीं यह तो सबलोग जान रहे हैं लेकिन बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है जहां 52 फीसदी आबादी गरीब है, यह सच्चाई है । अब महोदय सबसे ज्यादा गरीब 15 साल

से भी ज्यादा डबल इंजन सरकार के लोग राज कर रहे हैं । बजट का आकलन या बजट का जो प्रारूप है हमेशा जो है वह बढ़ता जा रहा है । आप देखियेगा महोदय कि लगातार सरकार पीठ बार-बार थपथपाती है कि हमने जो है बजट देखो पहले क्या था अब हमने देखो 2 लाख 37 हजार करोड़ का कर दिया । लेकिन 15 साल से भी ज्यादा वही मुख्यमंत्री, केन्द्र में भी सरकार लेकिन क्या स्थिति है । महोदय, आपने तो मुख्यमंत्री जी का बयान देखा ही होगा, उन्होंने कहा अब तो नीति आयोग ने ही गरीब बता दिया, सबसे पिछड़ा बता दिया तो हमको स्पेशल राज्य का दर्जा दे दो तो इसके लिये क्या पीठ थपथपानी चाहिए मुख्यमंत्री जी की ? ये सवाल जो है क्या मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपायी जाय और विशेष राज्य का दर्जा मांग कौन रहा है, वह तो पार्टनर हैं न गर्वनमेंट ऑफ इंडिया में । अपने ही पार्टनर से मतलब बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं या अमेरिका के राष्ट्रपति से, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मांग रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा देगा कौन ? लेकिन जब हमने परसों ही अपने अभिभाषण में कहा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजिज हैं, सबके अलग-अलग मतलब हैं इस क्षेत्र में तो उसमें हमने यह भी बताया कि उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है । मतलब ये लोग, चर्चा देखिये 52 फीसदी गरीब लोग हैं बिहार में और बजट हमेशा बढ़ता जा रहा है इतना लाख करोड़, इतना लाख करोड़ और गरीबी सबसे ज्यादा । यह तो आप खुद मान रहे हैं, यह तो सरकार खुद मान रही है कि बिहार जो है सबसे गरीब है और गरीब होने का श्रेय किसको दिया जाय फिर, जिन्होंने 15 साल से भी ज्यादा 17 साल तक राज किये तो, डबल इंजन की सरकार को ही न बोलियेगा, किसको बोला जाय । महोदय, यह स्थिति जो है पूरे तरीके से अब देखियेगा कि बिहार के 38 में से 22 जिलों में आधे से अधिक लोग गरीब हैं, यह स्थिति बनी हुई है और इन 11 जिलों में 60 फीसदी से भी ज्यादा लोग गरीब हैं जैसे किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, मधेपुरा हो गया, पूर्वी चम्पारण हो गया, सुपौल हो गया, जमुई हो गया । अध्यक्ष महोदय, थोड़ा निर्देश दिया जाय...

(व्यवधान)

आपको समय मिलेगा, बोलेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति । अब शांति से सुनिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय...

टर्न–13/राहुल/04.03.2022

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष का शांति से सुनियेगा, फिर इधर का भी ये लोग शांति से सुनेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आप देखिये बजट की जहां तक बात करते थे, हमारे पास सी0ए0जी0 की रिपोर्ट है । हम चाहेंगे कि उप मुख्यमंत्री जी थोड़ा गौर करें । सी0ए0जी0 की रिपोर्ट में अगर उप मुख्यमंत्री जी देखें तो अध्याय 5 में पेज नंबर 32 पर अगर आप जाइयेगा, उप मुख्यमंत्री जी तो इसमें वर्ष 2019–20 के बारे में विनियोग लेख दिया हुआ है उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो मूल अनुदान जो है जो वर्ष 2019–20 में था वह दो लाख पांच सौ दो करोड़ रुपये का था और कुल अगर बात की जाय तो 2 लाख 28 हजार 487 करोड़ रुपय का था यह हकीकत है लेकिन आप लास्ट के कॉलम में जाइयेगा तो बचत भी होती है वह 80 हजार करोड़ खर्च ही नहीं कर पाए आप लोग । अगर इसका हम डिपार्टमेंट वाइज आंकड़ा निकालें तो मान लीजिये जैसे कृषि विभाग है, कृषि विभाग में अगर आप देखें महोदय तो 41 फीसदी पैसा खर्च ही नहीं किया गया, सहकारिता विभाग में देखा जाय तो 74 परसेंट पैसा खर्च नहीं किया गया, पंचायती राज विभाग में देखा जाय तो 36 फीसदी खर्च नहीं, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में देखा जाय तो 50 फीसदी नहीं, स्वास्थ्य विभाग में 31 परसेंट पैसा खर्च ही नहीं किया गया, शिक्षा विभाग में 32 फीसदी खर्च नहीं किया गया, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 51 फीसदी पैसा खर्च नहीं किया गया ऐसे देखा जाय तो टोटल मान लीजिये कि 80 हजार करोड़ खर्च ही नहीं कर पाए । बजट जो आप लोग पेश करते हैं तो वह खर्च क्यों नहीं हो पाता यह बिहार की जनता जानना चाहती है । बेरोजगारी है, इतने पद रिक्त हैं शिक्षा विभाग, हर विभाग में तो आप क्यों नहीं नौकरी देकर शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में जॉब देने का काम करते हैं जब पैसा बचा हुआ है तो । यह तो देना न चाहिए, यह सारा काम करना चाहिए । आखिर क्यों नहीं कर पाते और खूबसूरती यह देखिये महोदय, अगर 33 पेज पर जाइयेगा तो मेरा कमेंट नहीं है । उप मुख्यमंत्री जी आप वित्त मंत्री हैं । यह सी0ए0जी0 का कमेंट है उसी पेज पर ''किसी अनुदान के अन्तर्गत लगातार बचत का होना इस बात का द्योतक है कि या तो कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हुआ या क्रियान्वयन धीमी गति से हुआ'' । यह मेरी रिपोर्ट नहीं महोदय, यह तो सी0ए0जी0 का कमेंट है । कुछ अनुदानों के अंतर्गत लगातार हुई बचतें तथा विशिष्ट बचतें एवं ये है जो मैंने आपको विभाग के सारे गिनाये हैं । अब इंटरेस्टिंग यह है सी0ए0जी0 की रिपोर्ट में 34 नंबर पेज में कि वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 21 हजार 88 करोड़ का अनुपूरक अनुदान कुल व्यय का 14 प्रतिशत जो

कुछ प्रावधानों के अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि वर्ष के अंत में मूल प्रावधान के विरूद्ध ही विशिष्ट बचतें हुई हैं तथापि अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया । कुछ उदाहरण हैं जो हम बताना चाहेंगे मतलब आपका जो मूल बजट है उसमें इतनी बचत हुई तो फिर अनुपूरक क्यों लेकर आते हैं आप लोग ? मान लीजिये जैसे राजस्व विभाग का एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि मूल था 2 हजार 939 करोड़ रुपया और टोटल वास्तविक व्यय हुआ 2 हजार 152 करोड़ रुपया यानी 800 सौ करोड़ रुपया तो ऑलरेडी बचा हुआ है तो आप लोग 533 करोड़ का अनुपूरक फिर क्यों लेकर आए? मतलब मूल में से ही मान लीजिये बजट का है सब डिपार्टमेंट को हमको एक हजार रुपया खर्च करना है तो मान लीजिये एक हजार में से इन्होंने केवल छः सौ रुपया खर्च किया, चार सौ रुपया बचा तो ये अलग से फिर आ जाते हैं पैसा लेने सदन के अंदर कि हमको दो सौ रुपया और दो, इसका मतलब क्या है ? महोदय, ऐसे ही अगर हम भवन निर्माण में अगर आप देखें, तो 4 हजार 582 करोड़ रुपये का था अनुपूरक ये लोग ले आए 754 करोड़ रुपये का बल्कि वास्तविक बचत थी 1385 करोड़ रुपया बचा हुआ था । ऐसा कितना देखियेगा जो यहां बचत है जिसका कोई काम नहीं किया जा रहा है । अब इस पर बात की जाय हमारे पास पिछले बजट का कल तक का खर्च करने का डेटा है यानी डिपार्टमेंटवाइज एक्सपेंडिचर की लिस्ट हमारे पास है जो 03 मार्च, 2022 तक का है डिपार्टमेंटवाइज एक्सपेंडिचर । अब इसमें देखा जाय तो लास्ट बजट जो था, पिछला बजट जो था दो लाख अठारह हजार तीन सौ दो का था और कल, 03 मार्च तक जो है केवल एक लाख पांच हजार एक सौ सात रुपया ही खर्च किया गया है । यह सच्चाई है । आप जाइये डिपार्टमेंटवाइज एक्सपेंडिचर में कल तक का है, 03 मार्च तक का । आप केवल एक लाख पांच हजार एक सौ सात यानी 48 फीसदी ही पैसा खर्च हुआ और 48 फीसदी तब हुआ जब आप ट्रांसफर टू पी0एल0, पी0डी0 लिये तब 48 फीसदी हुआ, अगर पी0एल0, पी0डी0 और अदर बी0टी0 हटा दें तो केवल जो खर्चा हुआ वह केवल 74 हजार 468 का हुआ है जो कि 34 फीसदी है । अब आप बताइये आप फिर ले आए हैं लगभग 2 लाख 38 हजार करोड़ का । महोदय, आश्चर्य है, लोग देखते हैं, सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि पैसा जाता कहां है ? ये क्या इन्फ्लेटिड करके बजट बनाया जाता है या भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है या मार्च लूट, जरा अधिकारियों से उप मुख्यमंत्री जी पूछियेगा, हमको भी नहीं पता था मार्च लूट क्या होती है । मार्च लूट यह होती है कि हैन्ड टेन हैन्ड, गायब, कहां गया पैसा ? वह तो सी0ए0जी0 की जो रिपोर्ट है इसमें आप देखें सी0ए0जी0 का वित्त लेखा खंड-1 में अगर आप जाइयेगा उप मुख्यमंत्री जी तो इसमें साफ है कि 80 हजार करोड़ रुपये का बिहार सरकार ने

वर्ष 2019-20 में हिसाब-किताब दिया ही नहीं है । आप बताइये 80 हजार करोड़ का कोई हिसाब-किताब नहीं है कि बिहार सरकार ने उस पैसे का क्या किया । अब बताइये क्या हो रहा है भाई, इसीलिए 80 घोटाले हो रहे हैं । कोई अधिकारी, कोई मंत्री किसी पर जो है...

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष यह सी0ए0जी0 की रिपोर्ट कब की है ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : यह वर्ष 2019-20 की है । अध्यक्ष महोदय, हम तो.

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, सी0ए0जी0 का कंपोजिसन जो है, उसका जो फंक्शन है हर विभाग का 10 परसेंट ही वह चेक करता है और बाकी का वह एवरेज बना देता है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जब जांच कर लेती है तब जो सदन में रिपोर्ट पेश होती है वह ऑथेंटिक रिपोर्ट है । अभी एक कंप्लेंट उनकी है, तो यह जांच का विषय है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जांच के बाद ही उसको बोला जाता है यही नियम है फिर सदन में पेश होगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट, तो माननीय, चूंकि वित्त मंत्री रहे नहीं है । इसीलिए अपना जो ज्ञान है उसके आधार पर बोल रहे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अब तो सी0ए0जी0 पर ही सवाल उठाया जा रहा है । मतलब आप अगर...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आप समझ नहीं रहे हैं सी0ए0जी0 पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, सी0ए0जी0 की प्रक्रिया का मैंने बताया और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आप ही के...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सबका समय आयेगा...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : एक मिनट, आप ही की तरफ से, विरोधी पार्टी के लोग ही उसके अध्यक्ष होते हैं, आप ही की पार्टी का कोई होगा अध्यक्ष उसका । मैंने बतलाया कि सी0ए0जी0 सौ परसेंट नहीं करता है कभी-कभी विभाग से हिसाब आने में भी लेट होता है जो आप कह रहे हैं 3 मार्च तक का,

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, तो हर साल की एक ही कहानी...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अच्छा सुनिये न । 31 मार्च तक का नहीं है वह...

टर्न-14/मुकुल/04.03.2022

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सी0ए0जी0 जब भी रिपोर्ट देती है तो 5 साल का ही न दे रही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप आगे बोलिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : ललित जी, ठीक है ।

अध्यक्ष : देखिए, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हमारे ही समय को क्यों बर्बाद किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : आपके समय को बर्बाद नहीं, बल्कि सदुपयोग किया जा रहा है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, तो सरकार का उत्तर कौन देगा, कोई भी खड़ा होकर बोलते रहेंगे इसका क्या मतलब है ।

अध्यक्ष : यहां पर कई माननीय नये सदस्य भी बैठे हैं, थोड़ी जानकारी भी जाती है कि यह रिपोर्ट लोक लेखा समिति के विचाराधीन होनी चाहिए और नियम-236, नियमावली के अंदर...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : अच्छा ठीक है, आप बोलिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, यह सारा वर्ष 2019-20 का है ।

(व्यवधान)

जब यह मानना ही नहीं है तो सदन में क्यों बंटवाते हैं, ले ही क्यों करवाते हैं, फेंक दीजिए, फेंकवा ही दीजिए ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, आप अपनी बात को बोलिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, यह कोई मतलब नहीं हुआ । हम तो अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, हम कोई कल्पना या एज्युम नहीं कर रहे हैं कि ऐसा किया गया होगा । जो साइंटिफिक डेटा है, जो संवैधानिक एजेंसियां हैं उसी की हम बात कर रहे हैं तो उसपर भी आपलोग सवाल उठा रहे हैं, मतलब सच सुनने की किसी को ताकत नहीं है तो इसे मिटवा दीजिए । बिजेन्द्र जी कह रहे थे, ये हमारे अभिभावक हैं, अनुभवी हैं, सबकुछ रह चुके हैं बस मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, लेकिन हम वह नहीं कहना चाहते हैं, हम यह कहना चाहते हैं....

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आप एक बात सुन लीजिए कि मैं वित्त मंत्री भी रहा हूं और सुरेन्द्र जी आपके अध्यक्ष...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हम कह रहे हैं...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : सुन तो लीजिए, दूसरे की बात भी एक मिनट जरा सुन लीजिए ।

अध्यक्ष : सुन लीजिए, आपने नाम तो ले लिया, आप नाम लिये हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आपके दल के सुरेन्द्र जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सभापति हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हम जान रहे हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : नियमावली में लिखा हुआ है कि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट फाइनल नहीं आई है तो उस मैटर को माननीय सदस्य भी हाउस में नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वह जांच का विषय है । सुरेन्द्र यादव जी रिपोर्ट पेश करेंगे कि 80 हजार करोड़ रुपये भ्रष्टाचार में चला गया कि चारा घोटाला में चला गया तो हमलोग उसको कबूल करेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : ठीक है ।

अध्यक्ष : जब नेता प्रतिपक्ष और हमारे सबसे वरिष्ठ अनुभवी लोग बोलते हैं तो सुनिये कि क्या कह रहे हैं, सीखने की चीज है, समझने की चीज है । नेता प्रतिपक्ष अपनी बात बोलिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, एकदम यह सीखने की चीज है, सब कुछ है, सबको जानना चाहिए । अब हम तो चाहेंगे कि जब भी डिबेट चल रही होती है, जब वाद-विवाद चल रहा हो तो जो भी स्पीकर जिनको सभी दल के लोगों को मौका मिलता है, जो उनके प्रश्न हैं, जो उनकी चिंतायें हैं वह मंत्री जी को दूर करना चाहिए, लेकिन मंत्री जी क्या लाते हैं अधिकारी की पढ़ी हुई रिपोर्ट, लिखी हुई रिपोर्ट वे पढ़ देते हैं और वह खत्म हो जाती है । हम चाहते हैं कि हमारी चिंता दूर कीजिए तब न पॉजिटिव एक डिबेट होगी, तब न उसका फायदा होगा । अब कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है और यहां से लोग भाग खड़े होते हैं ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट । आपने बहुत अच्छी चीज उठाई है कि मंत्री जी अब रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं, 17वीं विधान सभा में सरकार के जवाब पढ़ने का अवसर अब कम गया है, अब हमारे माननीय सदस्य जवाब पढ़ते हैं और उसमें पूरक बनाकर मंत्री जी को अब जवाब देना पड़ता है, मौसम बदल गया है । अब आप बोलिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हमलोग तो आपकी बात का हमेशा पालन करते ही हैं, करेंगे भी, लेकिन विषय जो है इस पर आना चाहिए । आज हम डेटा लाये हैं, आंकड़े जो हैं वह सदन को पता होने चाहिए कि आखिर वास्तविकता क्या है ? अगर हम कोई झूठ बोल रहे हों, आंकड़े गलत हों तो मंत्री जी या सरकार अपने वक्तव्य में उसे हटा सकती है । अब बिहार विधान सभा में बजट के दौरान वित्त मंत्री तारकिशोर जी ने कहा कि बिहार का पर कैपिटा इनकम 50,555 रुपये है, जबकि भारत का लगभग 86,659 रुपये है । अब मंत्री जी के अनुसार बिहार जो है भारत से अच्छा काम कर रहा है, अब हमको यह कल्पना के परे है कि जब बिहार का ही पर कैपिटा इनकम 50,555 रुपये है और भारत का 86,659 रुपये है तो बिहार भारत से कैसे अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इनके अनुसार बिहार अच्छा काम कर रहा है । महोदय, अब ये बातें भ्रमित करने वाली हैं क्योंकि बिहार पहले भी प्रति

व्यक्ति आय रैंक में 33वें स्थान पर था और अभी भी 33वें स्थान पर ही है । स्टेट जी0डी0पी0 में 14वें स्थान पर है और मानव विकास सूचकांक में 36वें स्थान पर है अंतिम में, यह सच्चाई है, यह नीति आयोग पढ़ लीजिए और वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा कि बिहार का शहरीकरण का स्तर वर्ष 2011 में 11.3 फीसदी था, अब बढ़कर 15.3 फीसदी हो गया । महोदय, इन्होंने ये बातें कही, अब हकीकत क्या है अगर हम वर्ष 1981 की बात करें, छोड़िये वर्ष 2011 में 11.3 फीसदी था तो वर्ष 1981 में शहरीकरण के आंकड़े को देखें तो पाते हैं कि बिहार में उस समय 9.59 फीसदी था, जबकि भारत का 22.89 फीसदी था तो आप समझिए कि वर्ष 2011 में जहां बिहार में शहरीकरण का आंकड़ा 11.29 फीसदी था वहीं भारत का 31.16 फीसदी है । आज के दिन बिहार में शहरीकरण की दर 15.3 फीसदी है तो भारत की 35.4 फीसदी है, कितना पीछे हैं आप और आप कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं और अर्थ होता है कि शहरीकरण के मामले में बिहार जो है पूरे देशभर में सबसे फिसड्डी राज्य है, ये आंकड़े बताते हैं । अब आप देखिएगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी दर बिहार में 51.91 है, जो देश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक है और आप बताते हैं कि विकास किया । 12वें 2005 से 10, 13वें में 2010 से 15, 14वें में, 15वें में, फाइनेंस कमीशन देखते हैं तो पाते हैं कि बिहार ऐसा दूसरा राज्य है जिसको सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन का पैसा मिला और 12वें फाइनेंस कमीशन में 11 परसेंट, 13वें में 10.9 परसेंट, 14वें 9.6 और 15वें में 10.6 मिला फिर भी बिहार जो है अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे पीछे क्यों है ? जब सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन में दूसरे नम्बर पर राज्य में था तो सबसे फिसड्डी राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट में, हरेक सूचकांक में बिहार सबसे पीछे क्यों है, इसका तो जवाब देना चाहिए । अब प्रति व्यक्ति आय में 33वें स्थान पर, मानव सूचकांक (एच0डी0आई0) में 36वें स्थान पर, जी0डी0पी0 में 14वें स्थान पर बिहार में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में सिर्फ 9 परसेंट है, वहीं फिमेल फोर्स पार्टिसिपेशन में केवल 4.3 है, यह बिहार की सच्चाई है । बिहार में क्रेडिट रेश्यो डिपॉजिट सिर्फ 32 फीसदी है, जबकि नेशनल एवरेज 75 परसेंट है । बिहार की टोटल अर्निंग को देखें तो पता चलता है कि एक्सपेंडिचर का 78 परसेंट, यह आप सब लोग ध्यान से सुनियेगा । टोटल एक्सपेंडिचर जो है 78 परसेंट केन्द्र से आता है और 22 परसेंट टैक्स कलेक्शन बिहार सरकार करती है और वह एक्सपेंडिचर में डालती है तो बताइये कि 78 परसेंट तो भारत सरकार से आ रहा है और 22 परसेंट में अगर हिसाब किया जाय केवल 22 परसेंट का तो इसका 70 फीसदी हिस्सा जी0एस0टी0 और पेट्रोल से आता है और 30 फीसदी हिस्सा रजिस्ट्री से आता है, यानी बिहार में जो हमको टैक्स मिलता है वह केवल जी0एस0टी0 पेट्रोल/डीजल का

है और रजिस्ट्री से जो पैसा आता है वह आता है । अगर यहां इंडस्ट्री लगी होती तो हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ता कि नहीं बढ़ता, क्यों नहीं बढ़ता । क्या है बिहार में, कुछ भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री, कोई कारखाना नहीं है, कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है और 22 परसेंट । सोचिए खर्च कितना होता है तो उसे हम बता ही दिये हैं, उसमें से भी लोगों को मिलता क्या है, यह पैसा कहां जा रहा है और किस बात की आपलोग पीठ थपथपा रहे हैं । वहीं बिहार का कमिटेड एक्सपेंडिचर सैलरी, पेंशन देखिएगा तो यह इंट्रेस्टिंग डाटा है ।

...क्रमशः...

टर्न–15/यानपति/04.03.2022

...क्रमशः...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः सैलरी में, पेंशन में इंटरेस्ट 34 परसेंट है कितना 34 परसेंट, वहीं बिहार का अर्निंग केवल 22 परसेंट है, न लोगों को पेंशन मिल रही है, न लोगों को सैलरी मिल रही है, न कुछ हो रहा है, यह सच्चाई आंकड़ा है महोदय, मतलब पिछले 17 सालों का औसत देखें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे फाइनेंस कमीशन ने 28 परसेंट शेयर दिया तब जाकर यह हाल है और हमलोगों के जमाने में तो सौतेला व्यवहार होता था, सबलोग जान रहे हैं लेकिन 28 परसेंट, इसके बावजूद भी महोदय बिहार की हालत न पढ़ाई, न दवाई, न सिंचाई, न कमाई, न सुनवाई, न सरकारी, सबकुछ बंद है, होती चली जा रही है । सी0ए0जी0 की रिपोर्ट देखिए, विभिन्न विभागों में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, यही है लेकिन कार्रवाई और सुनवाई कहीं नहीं होती है । अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय को दर्शाता है उसको देखें तो पाते हैं जहां पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के कार्यकाल में बिहार का स्थान 32वां था और आज 2022 में वह 33वां है । हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उस समय के कार्यकाल में दो बार तो राष्ट्रपति शासन लगा तब यह स्थिति है महोदय । आज 33वें पर, पहले थे हमलोग 32वें पर । सबलोग जान रहे हैं कितना सौतेला व्यवहार हुआ । उस समय फाइनेंस कमीशन भी हमलोगों को इतना पैसा नहीं देती थी, स्पेशल पैकेज की बात करें या हरेक योजना, जो अधिकार भी था वो भी कटता रहा था महोदय, तब भी राबड़ी देवी जी की सरकार और उसमें कई राज्य मतलब बिहार और झारखंड एक थे, शुरुआती दौर में, क्षेत्रफल भी बड़ा था और पॉपुलेशन भी बड़ी थी । महोदय, आप समझ सकते हैं । इसलिए तब भी सरकार में लगभग 5 प्रतिशत की विकास दर थी, राबड़ी देवी जी के समय में 5 प्रतिशत की जो विकास दर थी, उस समय भारत की जो

जी0डी0पी0 थी महोदय, वह 6.5 थी, तब भी हम इतने करीब रहते थे और आज देख लीजिए कितने का गैप है जो पहले मैंने आपको डाटा में बताया । कितना बड़ा गैप होता जा रहा है महोदय, तो महोदय, सौतेला व्यवहार इससे भी पता चलता है कि सेन्टर टैक्सेशन का शेयर राबड़ी जी के कार्यकाल में कम दिया गया जबकि बिहार में लगभग आधा दर्जन से अधिक केंद्र में मंत्री थे उस समय । आधा दर्जन से भी ज्यादा उस समय केंद्रीय मंत्री बिहार के थे महोदय । अब थोड़ा उसको डिफाइन अगर हम करें तो आंध्र प्रदेश को 3507 करोड़ 1998-2000 में मिला वहीं बिहार को केवल 306 करोड़ रुपया मिला, ये हकीकत है । 2000 से 2003 आंध्र प्रदेश को 9790 करोड़ का सेंट्रल ग्रांट मिला वहीं बिहार को 4047 करोड़ मिला, सोचिए 5 हजार करोड़, कोई और राज्य को ज्यादा मिल रहा है । उस समय हमलोगों का ग्रांट फंड जो था सेंट्रल का वह तो बहुत कम था तब भी जो है जी0डी0पी0 में और 22वें स्थान पर थे । 2002-03 में आंध्र प्रदेश को नेट लोन में भी 6902 करोड़ रुपये मिला वहीं बिहार को 2849 करोड़ रुपये मिला । पर कैपिटा सेंट्रल असिस्टेंस में भी 2000-01 में आंध्र प्रदेश को 626 मिला वहीं बिहार को रुपये 276 मिला महोदय । कितना बड़ा डिफरेंस होता था, कितना पक्षपात होता था उस समय । बिहार का बजट 2005 में, जो बजट का ये लोग आंकड़ा देते हैं कि हम पिछले साल 218 था इस बार देखो हम 237 कर दिए, इसका हम उत्तर देते हैं कि 2005 में बिहार का बजट 24 हजार करोड़ था और भारत का 4 लाख 53 हजार करोड़ रुपये था, आज 2022 में बिहार का बजट 2 लाख 37 हजार करोड़ है वहीं भारत का 39 लाख 70 हजार करोड़ रुपये है महोदय । राजद शासनकाल में 1990 से लेकर 2005 तक जो बजट में लगभग 8 गुना की बढ़ोत्तरी हुई और 2005 से 2020 में भी 8 गुना की ही बढ़ोत्तरी हुई । यानी उस समय भी 8 गुना की बढ़ोत्तरी हुई, इस बार भी 8 गुना की बढ़ोत्तरी हुई । यानी बजट जो है आप कह सकते हैं कि समय-समय के साथ बढ़ता रहता है, उतना ही गुना बढ़ा तो अपनी पीठ थपथपाने की इनको कोई जरूरत नहीं है महोदय । अब बात करें:-

''अपने चेहरे से जो जाहिर हुआ छुपाएं कैसे,
तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आएं कैसे,
लाख तलवारें बढ़ी आती हों गर्दन की तरफ,
सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे''।

महोदय, ये इंपॉर्टेंट बातें अब डेवलपमेंट मॉडल की बात करें, मुख्यमंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजना है, फ्लैगशिप योजना क्या-क्या है, कृषि रोड मैप, 7 निश्चय, जल-जीवन-हरियाली, महोदय, यह बिहार सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना

है, उसको फ्लैगशिप योजना कहते हैं । अब व्यवस्था इतनी, और ये जितनी योजनाएं चल रही हैं महोदय, इसमें देखिएगा एक मंत्रालय की जवाबदेही नहीं है, न किसी पर जिम्मेवारी है, भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी पर कार्रवाई नहीं होती है, काम पूरा नहीं होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, आखिर क्यों ऐसा होता है । हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं कि भारत ने और कई एक राज्यों ने प्रिस्मैटिक मॉडल छोड़ दिया है, प्रिस्मैटिक मॉडल क्या होता है कि जहां 15 डिपार्टमेंट को जोड़ लिए एक योजना को पूरा करने में, अब बताइये, इनकी जो योजना है सात निश्चय इसमें कितने डिपार्टमेंट लगे हैं इकट्ठे, जल-जीवन-हरियाली में कितने डिपार्टमेंट लगे हैं, कृषि रोड में कितने लगे हैं, किसी पर जवाबदेही है, किसी पर जिम्मेदारी है, सब उसको दोषी ठहराता है, उसको दोषी ठहराता है यही काम चल रहा है । केवल जो है टैक्स कलेक्शन हो रहा है, टैक्स कलेक्शन हो रहा है आर0सी0पी0...

(व्यवधान)

भाई, अब आप बात कीजिएगा...

(व्यवधान)

हम नाम लिए ही नहीं हैं, नाम कहां लिए हैं ।

(व्यवधान)

क्या बात कर रहे हैं, नाम हम कहां लिए हैं, नाम नहीं लिए हैं महोदय, कहां नाम लिए हैं ।

अध्यक्ष: अच्छा बोल दीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: आर0सी0पी0 टैक्स, आर का मतलब रिजर्व, सी का मतलब कमीशन और पी का मतलब प्रिविलेज, रिजर्व कमीशन प्रिविलेज टैक्स,

(व्यवधान)

बैठिए न ।

अध्यक्ष: आगे बढ़िए, आगे बढ़िए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अब हम तो नहीं कहते हैं कि 15 दिनों में 100 करोड़ रुपये मेरी पार्टी में आ गया । 15 दिन में 100 करोड़ रुपया कहां जा रहा है, वह तो हम तय नहीं करते हैं । अच्छा चलिए, बैठिए न ।

अध्यक्ष: बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: हां, मंत्री बन जाइएगा, बैठिए ।

(व्यवधान)

महोदय, प्रिस्मैटिक मॉडल जिसको हमने सदन में समझाया कि प्रिस्मैटिक मॉडल जहां बहुत लोग को ले गया, एक को नॉडल डिपार्टमेंट बना दिया, वो पल्ला

झाड़ रहा है, वो पल्ला झाड़ रहा है । अब पूरे देश में और कई राज्यों में डिफ्रेक्टेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट चल रहा है । डिफ्रेक्टेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जहां एक-दो विभाग को जिम्मेवारी होगी, उनको ही काम पूरा करना है, उनकी ही जिम्मेदारी तय होगी, उनकी ही जवाबदेही होगी, तब काम होता है । जब पूरे देश ने, कई राज्यों ने छोड़ दिया है तो आप जो है प्रिस्मैटिक, उसके तहत जो है क्यों काम कर रहे हैं, तो यह छोड़ देना चाहिए । इसी वजह से महोदय पारदर्शिता नहीं होती है, कहीं पारदर्शिता नहीं होती है । लोगों को कंफ्यूजन होता है, विधायक लोग सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं उधर ट्रांसफर हो गया, उधर ट्रांसफर हो गया । होता है कि नहीं होता है । लोगों को दिक्कत होती है, तो महोदय यह सारी चीज जो है 80-80 घोटाले ऐसे थोड़े ही हुए हैं जो छुपा हुआ है । इसलिए यह जानना जरूरी है इसलिए मेरी सलाह है कि यहां डिफ्रेक्टेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अपनाना चाहिए ।

(व्यवधान)

अच्छा सुनिये ।

अध्यक्षः अब शांति रखिए, बीच में टोका-टोकी उचित नहीं है, बैठिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, यहां तक आते-आते...

अध्यक्षः अब दोनों व्यक्ति आपस में टोका-टोकी मत करिए । सुनिये शांति से ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः महोदय,

''यहां तक आते-आते सूख जाती हैं कई नदियां,
मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा होगा''

महोदय, ये इनका प्रिस्मैटिक मॉडल जो है इसको छोड़ देना चाहिए और हमने कहा डिफ्रेक्टेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, इसको अपनाने की जरूरत है । अब बात करेंगे हम एजुकेशन की, तो कल मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे, अरे, हमको तो पता ही नहीं कि बिहार के इतने लोग यूक्रेन में हैं ।

...क्रमशः...

टर्न-16/अंजली/04.03.2022

(क्रमशः)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ने0वि0द0ः बताइए ताज्जुब है, इसके लिये कुछ करना चाहिए । कितने साल हो गये अब तो अंतिम पड़ाव पर हैं ।

अध्यक्ष : राजनीति में पड़ाव नहीं होता है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ने0वि0द0ः मतलब शुरुआती देखा जाय ।

अध्यक्ष : आपसे ज्यादा अनुभवी कोई नहीं है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ने0वि0द0: ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है । यह हम अपनी बात नहीं, जो जनता कह रही है वही कह रहे हैं । जो जनता कह रही है, वही हम कह रहे हैं।

अध्यक्ष : राजनीति में पड़ाव नहीं होता है । अंतिम दिन तक राजनीति के लिए सब हिस्सेदार और जिम्मेवार होता है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ने0वि0द0: महोदय, बिहार चुनाव में तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यह मेरी अंतिम रैली है । हमने नहीं कहा ।

अध्यक्ष : अब आपके प्रश्न का जवाब तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ही देंगे, तीन शेर हुआ है वह भी तैयारी कस के किये हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ने0वि0द0: ठीक है । महोदय, जवाब दें, मजबूती के साथ दें हमको अच्छा लगेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब शांति से सुनिये, फिर एक शेर सुना देंगे यह ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ने0वि0द0: महोदय, तो कल आप भी थे ही, तो आपने सुना होगा कि भाई इतना लोग बिहार का बाहर पढ़ने जा रहा है एक और देश बताया, वहां भी लोग पढ़ने जा रहा है । अब आप बताइए, जाय क्यों नहीं । बिहार से बाहर जाय क्यों न और सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ें ? कितना सरकारी स्कूल में लोग पढ़ रहा है सब तो प्राइवेट ही ज्यादातर जा रहा है । क्यों ? अब बताते हैं ।

अध्यक्ष : यहां बहुत लोग सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट बैठे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ने0वि0द0: अच्छी बात है न, अच्छी बात है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलिये, आप बोलते जाइए । आप बैठ जाइए । सुनिये इनका, पूरी बात सुनियेगा तब न ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ने0वि0द0: अध्यक्ष महोदय, देखिए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : समीर जी, अब आप क्यों बोलने लगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ने0वि0द0: महोदय, यह सदन केवल सच बोलने के लिए होना चाहिए, जनता की मुसीबतों को दूर करने के लिए होना चाहिए, न कि टी0टी0एम0 करने के लिए होना चाहिए । अब कुछ लोग ताबड़तोड़ तेल मालिश करते रहें तो हम क्या कर सकते हैं, जनता आकलन करेगी । महोदय, अब आंकड़े देखिये बिहार में 18 से 23 वर्ष में लगभग 1.25 करोड़ युवा हैं यानी सबसे ज्यादा भारत में युवा हैं जिसमें से बिहार में मात्र 1 लाख, 78 हजार, 831 स्टूडेंट ही इन्रोल्ड हैं, इसका मतलब यह है कि 1 करोड़, 23 लाख, 21 हजार, 167 युवा उच्च शिक्षा से दूर हैं यानी 1 करोड़,

23 लाख से भी ज्यादा लोग शिक्षा से दूर हैं या फिर अन्य प्रदेशों में पढ़ाई करने जाते हैं यह सच्चाई है । ब्रेन-ड्रेन के साथ-साथ मनी भी ड्रेन होता है यानी खर्चा भी बाहर हो रहा है, बिहार का पैसा बाहर जा रहा है वहां खर्च हो रहा है । ब्रेन-ड्रेन, मनी ड्रेन सब हो रहा है वहां, पढ़ाई भी वहीं, बाहर लोग बस भी जा रहे हैं तो यह स्थिति पैदा हुई । अब क्यों ? क्योंकि स्कूल में छात्र ड्रॉप आउट रेट जो है देश में सबसे ज्यादा अगर सर्वाधक ड्रॉप आउट रेट है तो वह बिहार में है । गुणवत्ता शिक्षा में टॉप 20 में से बिहार 19वें नंबर पर है अब बताइए । एक भी ग्रेजुएशन समय पर पूरी होती है किसी छात्र की, समय पर कोर्स चलता है, किसी का नहीं चलता है । कॉलेज की क्या व्यवस्था है कि हमारा स्तर उस लायक है कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है अब तो टीचर को बोला जा रहा है जाइए सब दारू वाले को पकड़ के लाइए। अपने गलती कर रहे हैं और अपने अफसोस जता रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे हैं जा रहा है, अच्छा लगा कि आज पता चला कि बाहर जा रहा है, उनको तो यह भी बता दें आपके माध्यम से महोदय कि बिहार का हर दूसरा परिवार पलायन कर रहा है । पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार के लिए, क्या हालत बनी हुई है, क्या बिहार चला रहे हैं हम कुछ गलत नहीं न कहें कि भाई आप थके हुए हैं, अब ऊब चुके हैं, अब ऊबे भी क्यों न ?

अध्यक्ष : बीच में सही बात है, सही बात है यह उचित नहीं है । ये बोल रहे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ने0वि0द0: अब सही बात है, ऊबना ही चाहिए ।

अध्यक्ष : तो आप सपोर्ट चाहते हैं क्या ? आप नेता प्रतिपक्ष सपोर्ट चाहते हैं ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ने0वि0द0: सहयोगी का काम होता है सहयोग करना ।

अध्यक्ष : तो फिर सहयोग करने लगेंगे, तो आप बोल नहीं पायेंगे इतना हल्ला करेंगे सब ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ने0वि0द0: ठीक है । अब हो सकता है न भाई कि कोई ऐसा शर्त हो कि खाली बोले कि हमको मुख्यमंत्री रहने दीजिये, आप ही चलाइए पीछे से । रिमोट वाला भी होता है न । तो हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं तो महोदय..

अध्यक्ष : अनुभवी हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ने0वि0द0: महोदय, वही बिहार में सबसे ज्यादा 70 परसेंट बच्चों का पहली से दसवीं कक्षा के बीच ड्रॉप आउट रेट है । पहली से दसवीं का 70 परसेंट ड्रॉप आउट रेट है महोदय, ए0एस0ई0आर0 रिपोर्ट वर्ष 2017-18 देखें तो पता चलता है कि बिहार में 90 फीसदी स्कूल में कंप्यूटर लैब है ही नहीं । अब 90 परसेंट स्कूलों में कंप्यूटर लैब नहीं है । 30 परसेंट लाइब्रेरी में, 30 परसेंट लाइब्रेरी है ही नहीं। 60 फीसदी स्कूलों में प्लेग्राउंड नहीं है । 45 फीसदी स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है । बिहार के लगभग स्कूलों में साढ़े तीन लाख शिक्षक के पद खाली हैं और

हमने आपको बताया सी0ए0जी0 की रिपोर्ट में कि कितनी शिक्षा विभाग में बचत है, पैसा बचा हुआ है तो क्यों नहीं आप पद देते हैं, समय पर सैलरी देते हैं, समय पर पेंशन देते हैं यह तो बताना चाहिए ? राष्ट्रीय औसत के मुताबिक टीचर स्टूडेंट रेश्यो 1.27 है, वहीं बिहार में सबसे ज्यादा 1.55 है, एक पचपन, समझ जाइए महोदय यह सारी बात । उर्दू शिक्षकों और मदरसों की हालत सामान्य स्कूलों की तुलना में बहुत खराब है महोदय । क्राई, क्राई मतलब चाईल्ड राइट्स एंड यू रिपोर्ट और सेंटर फोर बजट एंड गवर्ननेंस अकाउंटबिलिटी, सी0बी0जे0ए0 से पता चलता है कि भारत में अन्य राज्यों की तुलना में स्कूली शिक्षा पर, पर-कैपिटा खर्च बिहार में सबसे ज्यादा कम है, अब कोई परीक्षा होती है तो पेपर लीक कर जाता है, कोई एक एग्जाम बता दीजिए, कोई एक परीक्षा बता दीजिए जिसमें पेपर लीक न हुआ हो ? कांट्रैक्चुअल टीचर्स हैं, पैसा है विभाग में तो आप परमानेंट नौकरी क्यों नहीं देते हैं भाई । आप कांट्रैक्ट पर टीचर क्यों रखे हुये हैं अगर आप बजट खर्च नहीं कर पा रहे हैं । 5-7 साल में तो ग्रेजुएशन होता है सब को पता है मतलब नये किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक वही पुराना चल रहा है यह सच्चाई है महोदय । आप देखिए, फेल्योर है इनका बिहार स्टार्ट अप की नीति अंतर्गत युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 सौ करोड़ के वेंचर कैपिटल का प्रावधान किया गया है जो स्टार्ट अप योजना है उसके लिए 5 सौ करोड़ के लिए वेंचर कैपिटल खड़ा किया गया है वहीं 2018 में अगर देखा जाय तो इतना जटिल प्रक्रिया है इसका कि 5 हजार आवेदन में से मात्र 60 को ही मिला स्टार्ट अप योजना, कैसे आप चला पाइएगा ? एक रिपोर्ट के अनुसार देश में किसानों की सबसे कम आय है, हम पेपर का कटिंग भी आपको पढ़ के बता रहे हैं, जांच एजेंसियां बता रही हैं औसत हर भारतीय किसान परिवार, आप किसानों का औसत देखिये आय का, भारतीय किसान परिवार 77,124 रुपये सलाना कमाता है वहीं बिहार में यह आय देश में सबसे कम है महज 42 हजार रुपये यानी मात्र 6,223 रुपया प्रति माह किसान का परिवार कमा रहा है आप बताइए ? महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बार-बार बोलना उचित नहीं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ने0वि0द0: महोदय, किसानों की आय को तो छोड़िये महोदय, खाद नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है इतना महंगा हो चुका है, किसान तबाह हो रहा है क्या सरकार कर रही है महोदय । नीति आयोग मे एम0पी0आई0, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक समझ लीजिये, सुन लीजिये । बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार देश के सबसे गरीब राज्य में है । बिहार में 52 फीसदी

आबादी गरीब है, गरीबी न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, स्कूल अटेंडेंस इत्यादि मानकों में बिहार सबसे नीचे हैं । नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 38 में से 22 जिलों में 50 फीसदी से भी कम गरीब लोग हैं और 11 जिलों में तो 61 फीसदी से भी ज्यादा गरीब लोग हैं । प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकर परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता स्तर को बताने वाले फांउडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इंडेक्स में बिहार सबसे नीचे है साक्षरता वाले में, जो उम्र है महोदय, अनुसार 10 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे बिहार का कम है । महिलाओं का शोषण और कुपोषण बिहार में चरम पर है । आप इस बात से सहमत होंगे । यह हमारा नहीं, सारे आयोगों का, एजेंसियों की रिपोर्ट है । महिलाओं की बात करते हैं लेकिन महिलाओं का शोषण ओर कुपोषण में बिहार चरम पर है क्या कहना है इस पर ? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन रिपोर्ट के अनुसार हम बता भी रहे हैं कि कौन एजेंसियां कर रही हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन रिपोर्ट के अनुसार 70 फीसदी महिलाएं 15 से 49 वर्ष के ग्रुप में कुपोषित हैं, बताइए क्या स्थिति है । (क्रमशः)

टर्न-17/सत्येन्द्र/04-03-22

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल(क्रमशः) देश में सबसे अधिक महंगी बिजली है । देश में सबसे अधिक बिहार में महंगी बिजली है और मात्र 350 किलो वाट परकैपिटा बिजली खपत है जो भारत में सबसे कम है, सबसे कम, यहां तक कि नागालैंड 356 कि0वा0, मणिपुर 371 कि0वा0 और त्रिपुरा 514 कि0वा0 बिजली परकैपिटा कंजप्सन है । महोदय, बिहार सबसे कम है, बताईए मणिपुर ये सब राज्य जो है पूर्वी क्षेत्र के वह भी आगे है, आपका कंजप्सन इतना कम है क्यों ? ठीक इसी प्रकार हर घर नल योजना जो है वह कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है । हम तो सुने कि एक सांसद महोदय, कौन कौन क्या क्या बोलता रहता है, भाई पार्लियामेंट में यानि देश के सबसे बड़े पंचायत में कहा कि 90 फीसदी नल से पहुंच रहा है जल, ये मजाक, क्या कर रहे हैं भाई, 90 फीसदी पहुंच रहा है, जरा कलेजा पर हाथ रखकर बोलिये तो, ईश्वर की शपथ खाईए तो, भगवान की कसम खाईए तो कि 90 प्रतिशत नल का जल आपके क्षेत्र में पहुंच रहा है, खड़े होकर बताईएगा, कलेजा पर हाथ रखकर बतलाईए, कोई नहीं कसम खा सकता है कि 90 फीसदी नल से जल मिला है,यह केवल भ्रष्टाचार में फ्लॉप हो गयी योजना, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है तो इसलिए महोदय जो सच्चाई है उसको बोलना चाहिए । केवल गुलाबी किताब में कुछ लिख देने से थोड़े ही हो जाता है । अरे, आंखों में आपलोग चश्मा लगाईए, जाकर के जमीनी स्तर पर देखिये कि क्या स्थिति बनी हुई है । महोदय, भूमिहीन जो दलित,

महादलित हैं, सरकार ने वादा किया था कि उनको सरकार तीन डीसमिल जमीन देगी लेकिन वह भी एक छलावा साबित हुआ, इससे मांझी जी इंकार नहीं कर सकते हैं । बोलिये, सरकार ने बोला था कि नहीं बोला था कि तीन डीसमिल जमीन महादलित को देगी, ये छलाबा है कि नहीं है ? मांझी जी सरकार के सहयोगी है लेकिन हमको अच्छा लगता है कि ये सच बोलते हैं, गरीबों के पक्ष में कभी कभी बोलते हैं । ये बतायेंगे तो महोदय,

जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिन्दा है
वो भी आयें हैं, यहां करने नसीहत हमको ।

महोदय, अब हेल्थ की भी बात करें तो..

अध्यक्ष: समय आपके पास सीमित है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल: कितना है ?

अध्यक्ष: 9 मिनट ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल: 9 मिनट, तो ठीक है आप हैं तो..

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप लोग डिस्टर्ब नहीं कीजिये, सुनिये । ये शेर-शायरी आप देते हैं क्या सुरेन्द्र बाबू?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय, आजकल देखा जाता है कि कई घोटाले होते हैं लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि उसको रिटायर कर दिया जाता है और रिटायर करने के बाद फिर कहीं न कहीं उनको सलाहकार के रूप में, बड़े बड़े अधिकारियों को एक्सटेंशन दिया जाता है, आखिर क्यों? क्यों, एक्सटेंशन दिया जाता है भाई, क्या बात है, तो महोदय ये नई परम्परा बनती जा रही है, इस पर मुख्यमंत्री जी को, उपमुख्यमंत्री जी लोगों को जवाब देना चाहिए । महोदय, हेल्थ पर भी बात करें तो नीति आयोग ने हेल्थ मानकों में भी बिहार को फिसड्डी राज्य माना है । आपका आदेश होगा, 9 मिनट बोलना है तो यह डेटा जो है, हम चाहेंगे हेल्थ का नीति आयोग का जो रिपोर्ट है इसको इंक्लूड कर लिया जाये, इसको पढ़ा हुआ माना जाय ।

अध्यक्ष: अभी बोलिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल: अनइम्प्लायमेंट में मुख्यमंत्री जी आप बताईए, अपने भाषण में आपको नहीं लगा कि बेरोजगारी पर बोलना चाहिए । देश सबसे युवा देश है, उसमें सबसे युवा बिहार है और देश में बिहार का जो आपको डाटा गिनाये, यहां कितनी ज्यादा बेरोजगारी है, कितने गेजुऐट बेरोजगार हैं लेकिन फिर भी आप लोग जो है रोजगार सृजन नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं । हम तो कहे थे आकलन करके, रिपोर्ट देखकर कि पैसा भी है, सबकुछ है, तब हमने कहा था कि

10 लाख रोजगार देंगे, अगर सरकारी बनी तो सरकारी नौकरी देंगे, ये हमने बोला था और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं असंभव, यह कोई नहीं कर सकता, तब बी0जे0पी0 के लोगों ने कहा, वित्त मंत्री यहां आयीं भारत की और उन्होंने कहा कि हम जो है 19 लाख रोजगार की व्यवस्था करवा देंगे, वह भी सरकारी नहीं, वे भी तो जान ही रहे हैं, काम तो है ही लेकिन भई कहां है 19 लाख, क्या रोड मैप है, क्या विजन है, लोग आते हैं, मेरिट वाले लोगों की परीक्षा होती है लेकिन उसको नहीं दाखिला मिलता है और सन्नी लियोनी पास कर जाती है, साउथ की जो रूपमा है वह पास कर जाती है कई कई एक्जाम में, पता नहीं कैसे आपकी एजेंसी सब काम कर रही है । भाई, 2013 वाला अभी तक लटका हुआ है, एस0टी0ई0टी0 वाला हो या अन्य कोई परीक्षा हो, हर विभाग में लोग परेशान हो चुके हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है । सारी व्यवस्था है, विभाग का पैसा आप खर्च नहीं कर पाते हैं । हम आपको बतलायें, बिहार में अदभुत है जो जितना शिक्षित है वह उतना ही बेरोजगार है । जो जितना शिक्षित, वह उतना ही बेकार । ग्रेजूएट ऐंड एवभधारी ग्रेजुएट जो है, या उससे ऊपर डिग्री लिये हुए हैं 26 फीसदी और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर जो हैं 20 फीसदी लोग बेरोजगार हैं । अब आप बतलाईए, बिहार में चार में से तीन युवा बेरोजगार है, युवाओं को काम नहीं मिल रहा है जिससे यहां एक भयावह स्थिति पैदा होती जा रही है । विकास तभी संभव है जब रोजगार सृजन की दूरगामी नीति अपनायी गयी हो । बजट में बताईए, क्या दूरगामी नीति है भाई ,कोई नीति नहीं, कोई विजन नहीं है, कोई नयापन नहीं, कोई नया ब्लू प्रिंट नहीं, वहीं मजदूरी का योगदान जी0डी0पी0 में देखें तो पाते हैं कि लगभग 18 फीसदी कृषि का, 18 प्रतिशत उद्योग का और 64 फीसदी योगदान सेवा क्षेत्र का, यह साबित करता है कि बिहार में विभिन्न श्रमिक योगदान और मजदूर के क्षेत्र में भारी अंतर है । लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, हमने पहले भी बताया महोदय कि 4.3 है बिहार में, महिलाओं के जॉब मार्केट में जो कि भारत के सबसे कम पार्टिशिपेशन में है । इंडस्ट्री, आई0टी0 सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, सुगर मिल सब बंद, कुछ नहीं चालू है, सब चौपट, इसका कहीं जिक्र नहीं है । इंडस्ट्रीज का जिक्र नहीं किया, आई0टी0पार्क का जिक्र नहीं किया, फुड प्रोसेसिंग यूनिट का जिक्र नहीं किया, केला, मखाना, मक्का, कितना ज्यादा होता है, क्यों नहीं आप यहां फुॅड प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं, क्यों नहीं बंद पड़े हुई चीनी मिल खोलते हैं, क्यों नहीं इंडस्ट्रीज लगाते हैं, क्यों नहीं आई0टी0 पार्क लगाते हैं, सेज लगाते है, SEZ क्यों नहीं लगाते हैं, क्या कर रहे हैं भाई, डिजीटल जमाने में रह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी खाली कहते हैं कि मिक्सिंग कीजिये, विडियो बनाईए, मिक्सिंग कीजिये । अच्छी बात

है, उनकी बात होगी, वह अपना समझे होंगे लेकिन बिहार में तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ?

अध्यक्ष: प्रधानमंत्री जी लोकल फॉर वोकल कहते हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: ठीक है छोड़िये । अब बताईए, सबसे ज्यादा मैन पावर हमारे पास है लेकिन उसका उपयोग ही नहीं करता है । कोई इंकार इससे कर सकता है कि कितना लोग मजदूरी के लिए बाहर जाता है कि नहीं जाता है, विदेश तक जाता है लेकिन हमारे यहां कोई उपयोग उसका है ही नहीं, क्यों नहीं है भाई, अब जब कोरोना काल में लोग फंसा था तो क्या स्थिति बन गयी थी परिवार पर, पैदल चलकर आये लोग, भूखे रहे, कितने लोग मर गये, क्या स्थिति बनी हुई थी तो महोदय, पलायन हो रहा है, हर दूसरे घर के लोग काम के लिए दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं और ये डबल इंजन की सरकार ने कमाल कर दिया, गरीबों को गरीब और अमीरों को मालामाल कर दिया और ये स्थिति है महोदय । अब महंगाई पर भी हमलोगों को बोलना था, इस पर हम एक पक्ष रखना चाहेंगे । 45 वर्षों बाद महंगाई शरीर को तोड़ रही है । तेल, डीजल, पेट्रौल, किराया, मसाला, फल, सब्जी सभी चीज पर टैक्स लगा दिया गया, गरीब मर रहा है तो इस पर एक शायरी–

''आपके हाकिम की फकीरी पे तरस आता है,
जो गरीबों से पसीनों की कमाई मांगे ।''

महोदय, किसान बदहाल और कर्मचारी और मध्यम वर्ग को जो पेंशन है परेशान हैं । हमारी मांग है पूरे विपक्ष की, मजबूती के साथ हम सदन में रखना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन को लागू होना चाहिए । ये हमारे घोषणा पत्र में भी था कि पुराने पेंशन को लागू करना चाहिए, समाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1000 रू0 करना चाहिए यह हमलोगों की मांग है ।

(क्रमश:)

टर्न–18/मधुप/04.03.2022

..क्रमश:..

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, बस हम आपसे तीन–चार मिनट और चाहते हैं, ज्यादा नहीं । हमलोग तो अध्यक्ष महोदय का पालन करते हैं न, बाकी और कुछ भी कहते हों मंत्री । हमलोग तो पालन करते हैं न !

''मैं अपनी आँख पर हकीकत का चश्मा चढ़ाकर देखता हूँ
हुनर जितना है सारा आजमा कर देखता हूँ
नजर उतना ही आता है जितना वह दिखाता है

मैं छोटा हूँ मगर हर बार कद अपना बढ़ाकर दिखाता हूँ''

महोदय, अब हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक कहानी कहेंगे ।

अध्यक्ष : एकाध शेर कह सकते हैं आप ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : शेर हो गया, अब कहानी सुनिये । नहीं तो आप फिर समय दीजियेगा ?

अध्यक्ष : कहानी सुनाइये लेकिन समय का अपना ध्यान रखें । दो मिनट बचा हुआ है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : ठीक है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति । इनका समय बर्बाद करना चाहते हैं आप ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, कहानी है कि एक राज्य का राजा था । वह राजा पहले दूसरे राज्य में सेनापति था, छल-कपट से वह दूसरे राज्य का राजा बन गया । अब थोड़ा बूढ़ा हो गया था, अब थका हुआ महसूस कर रहा था, उसका कोई वारिस नहीं था, उसके जो अपने सहयोगी थे, सिपहसालार थे, कई सेनापति भी ऐसे थे जिससे वह बहुत परेशान और उब चुके थे । तो एक दिन हुआ क्या कि राजा अपने खास से कहते हैं....

अध्यक्ष : एक मिनट बचा है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : कहानी खतम हो जायेगा, कितना टाइम लगेगा । एक दिन राजा अपने खास सिपहसालार से बात करता है कि अब हम उब चुके हैं, अब हमसे सम्भल नहीं रहा है, अब एक काम करते हैं कि कुछ सहयोगी को बुलाकर किसी खास सहयोगी में से किसी को उत्तराधिकारी, राजा का ताजपोशी कर दिया जाय, राजा बना दिया जाय । किसी खास सिपहसालार को यह बताते हैं तो किसी सेनापति को यह बात पता चल जाता है । वह सेनापति राजा के पास आता है, कहता है कि हमको राजा बनाइये और ब्लैकमेल करने लगता है उसका पुराना कोई गलती होगा उसको गिनाते हुये । राजा बड़ा परेशान हो जाता है । फिर बोलता है, मन में मानता है कि अब हम किसी को राजा नहीं बनायेंगे । एक अपने कमंडलधारी सहयोगी को राजा बुलाता है और बोलते हैं कि भाई ऐसी-ऐसी परिस्थिति है, वह ब्लैकमेल कर रहा है, अब तो राजा हमको बनना होगा नहीं तो सब बर्बाद हो जायेगा । हम क्या करते हैं कि तुम ही चलाओ राजपाट, हम खाली चेहरा दिखाने के लिए बनते हैं, नहीं तो वह हमको ब्लैकमेल कर रहा है, अब तुम ही चलाओ राजपाट ।

अध्यक्ष : अब आपका....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : बस दो मिनट । इतना तो आप सबको समय दिये । कहानी खतम हो जाय ।

महोदय, राजपाट चलने लगता है तो वह अपना आराम करता है, बुजुर्ग हो गया था और जो कमंडलधारी उनके सहयोगी थे, वे राजपाट चलाते थे । उनके राजपाट में उन्होंने अपने यहाँ धार्मिक अनुष्ठान शुरू कराया, प्रतिमाएँ लगवाईं, उन्होंने भंडारा लगवाना शुरू किया और राज्य लगभग कंगाल हो चुका था, कुछ बचा नहीं था तो इतनी बुरी स्थिति होने लगी, फिजूलखर्च होने लगा तो इतनी बुरी स्थिति हो गई कि राज्य का खजाना खतम होने के कगार पर आ गया । राजा और सलाहकार ने सोचा कि अब क्या किया जाय तो उन्होंने कहा कि जो चीजें हैं, संपत्ति बेच दो । कुछ पूंजीपतियों को उधार के लिए लगा दो । यह हुआ और हुआ कि कुछ दिन और चलाते रहा, भंडारा लगाते रहो, हलवा-पुरी खिलाते रहो । तो एक बार जनता परेशान हो गई, कृषि व्यवस्था चौपट हो गई, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, सब बर्बाद हो गया, कोई आय नहीं हो रहा, लोग पलायन कर रहे हैं, एक बार राजमहल में जाकर लोग घुस गये और बोले कि ऐसा राजा अपना पद खाली करे । अब यह बात राजा को जाकर उसका सिपहसालार बताता है कि राजमहल में घुस गया है लोग, तो राजा ने बोला कि भाई, अब तो हम बुद्ध धर्म अपनाने जा रहे हैं, हमने एक कुटिया भी बना रखी है, तुम एक काम करो कि अपना कमंडल लेकर हिमालय पर्वत चले जाओ। अब जानेगा नया राजा और जानेगी प्रजा । हमको क्या लेना-देना है ।

महोदय, वाकई में स्थिति जो है, यह बिहार से मिलता-जुलता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब शांत रहें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, लगता ऐसा ही है कि चल नहीं पा रहे हैं, थक चुके हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कंट्रास्टिंग आइडियोलॉजी है, कोई कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, वह उसका नहीं मान रहा है, वह इसका नहीं मान रहा है, आपस में अपने ही दल के विधायक मंत्रियों पर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : लोग परेशान हो चुके हैं । महोदय, हम बस चाहेंगे कि भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, किसान, पलायन, आई0टी0 सेक्टर, इंडस्ट्री, महँगाई, आखिर इतना चिकित्सा, शिक्षा, हर चीज में बिहार सरकार फिसड्डी है और ये बजट का खाली रूप देते जा रहे हैं कि इतना-इतना है । जरा, जिन मुद्दों को हमलोगों ने उठाया है, इसपर ये सटीक जवाब दें । जिन आंकड़ों पर हमलोगों ने पूछा है, उसपर ये जवाब दें । अब अधिकारी कुछ भी करते रहते हों लेकिन अधिकारियों का क्या है?

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : जो सच्चाई है, वह सदन में बोले । बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : एक मिनट । महोदय, आपके नियमावली में, मैंने जो जिक्र किया था, राज्य के विनियोग और वित्त लेखे तथा उनपर....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । हम चाहेंगे कि जो पार्ट हमारा नहीं आया है, उसको प्रोसिडींग का पार्ट बना दिया जाय । यह हेल्थ वाला है ।

अध्यक्ष : ठीक है । दे दीजिये ।

(नेता विरोधी दल का शेष वक्तव्य-परिशिष्ट द्रष्टव्य)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, नियम-236 : राज्य के विनियोग और वित्त लेखे तथा उनपर एवं स्थानीय निकायों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों पर सभा में विमर्श न होगा, जबतक कि नियम 239 के अधीन ऐसे लेखाओं और प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित न कर दिया जाय ।

एक और मैं पढ़ना चाहता हूँ, महोदय । लोक लेखा समिति के सभापति निम्न प्रस्ताव करेंगे :-

राज्य के विनियोग लेखे, वित्त लेखे एवं उनपर स्थानीय निकायों के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों पर दिए गए लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाए ।

उपस्थापन के बाद प्रतिवेदन प्रकाशन और बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जायेगा जब तक कमिटी के पास है, that can not be given the refrence हाउस में भी यह प्रतिबंध है । अब अद्‌भुत चीज है । कहा गया, महालेखापरीक्षक पर आपत्ति हो रही है । आपके नियमावली में है, महोदय । मैंने नियमावली नहीं बनाया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, हमने नियमावली का हवाला करके आपको सूचना दे दी ।

एक बात कहना चाहेंगे कि विमर्श बड़ा सकारात्मक भाव में हो । अच्छा है, थोड़ा-सा लोकतंत्र की खूबसूरती भी झलकती है, शेरो-शायरी के माध्यम से थोड़ा सदन का माहौल भी सकारात्मक बनता है । आठ शेर-शायरी हो चुका है, हम तो जहाँ बैठे हैं.. (व्यवधान)

तो हम भी कह दें । एक चीज कहना चाहेंगे, सुन लीजिए ।

औरों का झंडा झुका-झुका, अपना झंडा फहराना क्या,
रंग कर तन को सोनित से, अपनी लाली दिखलाना क्या ?

लकीर मिटाने में जितना समय हम लगायेंगे, हम इतनी लम्बी लकीर खींच दें कि आने वाली भावी पीढ़ी हम पर गर्व महसूस करे ।

अब श्री राणा रणधीर अपना पक्ष रखें ।

श्री राणा रणधीर : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । बजट के आय-व्ययक पर चर्चा के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ । अपने नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, अपने नेता द्वय उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी और बहन रेणु देवी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ ।

...क्रमशः...

टर्न-19/आजाद/04.03.2022

.... क्रमशः ....

श्री राणा रणधीर : अपने उप मुख्य सचेतक आदरणीय श्री जनक सिंह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और दो मिनट रुक जाईए तेजस्वी जी, आपसे मिठाई मांगने वाला हूँ। सबसे ज्यादा मैं मधुबन की महान जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिसके आशीर्वाद से, जिसके वोट से मैं आज सदन में खड़ा हूँ और आय-व्यय की चर्चा पर अपना पक्ष रख रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात चंद पक्तियों के माध्यम से शुरू करना चाहूंगा, नेता प्रतिपक्ष ने पक्तियों से बात शुरू की थी, मैं भी वही से शुरू करता हूँ-

मंजिलें और लक्ष्य बड़े जिद्दी होते हैं,
हासिल कहां नसीब से होते हैं,
पर वहां तूफां भी हार जाते हैं,
जहां कश्तियां जिद पर होती हैं ।

कल बड़ा महत्वपूर्ण दिन था । मुझे सौभाग्य मिला नुसरवानजी टाटा जिन्होंने देश में इतना बड़ा उद्योग का कारखाना स्थापित किया, उनका जन्म दिवस 3 मार्च को था । हम सबों के नेता, हम सबों के अभिभावक श्री नन्द किशोर यादव जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बहुत बढ़िया तरीके से विषय को रखा । हमलोगों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी जन्म दिन था, उनको भी शुभकामनायें देता हूँ और तेजस्वी जी आज आये और उन्होंने अच्छा विषय रखा है। एक तो इस बजट सत्र में उनका विवाह हुआ है तो उनको भी नये दाम्पत्य जीवन की शुभकामनायें देता हूँ लेकिन हम सब सदस्यगण मिठाई की आकांक्षा में बैठे हैं, हमारे नन्द किशोर यादव जी अपने भतीजे की मिठाई के इन्तजार में और मैं अपने छोटे भाई की तरफ से मिठाई के इन्तजार में पूरा सदन बैठा है ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर चर्चा हुई और बिहार का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है और बिहार ने एक लम्बी यात्रा तय की है । माननीय अध्यक्ष महादेय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि बजट विभागवार केवल पैसों के आवंटन का जरिया नहीं है बल्कि आने वाले वित्तीय वर्ष में राज्य के विकास का जीवन्त और सेल्फ एक्सप्लेनरी दस्तावेज है । मेरी प्राथमिकतायें क्या-क्या होंगी, हम किन चीजों पर काम करेंगे और नेता, प्रतिपक्ष ने कहा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली पर जो बिहार को उन्होंने मार्गदर्शन दिया और हमलोग 105 नये लोग जीतकर आये । इतना बड़ा मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का हुआ और 2005 की बजट की चर्चा होती है । उस समय विकास दर निगेटिव था, माईन्स में थी -1.69 और वहां से यात्रा शुरू हुई है, आबादी भी कम थी और आज आबादी बढ़ी है और उस नाते आज यह बजट और कोरोना जैसे महामारी 100 वर्षों में इतनी बड़ी महामारी नहीं आयी और इस महामारी में जिस तरह से प्रबंधन करके बजट का आकर पिछले 10 वर्षों में ढ़ाई गुना से ज्यादा बढ़ा है और यह बजट 2,37,691 करोड़ का बजट आया है तो मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन रहता है -

''जहां रहेंगे, वहीं रोशनी फैलायेंगे,
किसी चिराग का कोई मका नहीं होता,
फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए,
चाँद सूरज बनेंगे गगन के लिए,
लाख बाधायें आये कोई गम नहीं,
हम जियेंगे, मरेंगे वतन के लिए ।''

इस जज्बे के साथ उन्होंने काम शुरू किया है । अध्यक्ष महोदय, मैं तो चम्पारण से आता हूँ .....

अध्यक्ष : संक्षिप्त कर लीजिए अब ।

श्री राणा रणधीर : अब बस 5 मिनट में अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : 5 मिनट नहीं, आप एक मिनट के अन्दर समाप्त कीजिए ।

श्री राणा रणधीर : दो मिनट में अध्यक्ष महोदय, सिर्फ आपके संकल्प की चर्चा करके बस बता देता हूँ ।

अध्यक्ष : सरकार का उत्तर 3.30 बजे से है ।

श्री राणा रणधीर : बस अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण देना चाहता हूँ । 2005 में हमारे पास ग्रामीण सड़कें कितनी थीं, हमारे 105 नये सदस्य हैं, 3112 कि0मी0 ग्रामीण सड़कें थीं, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि आज 1,02,306 ग्रामीण सड़कें सरकार बना रही है । 2005 में पी0डब्लू0डी0 की सड़कें कितनी थीं, हमारी सरकार ने 6047 पुलियों

का निर्माण कराया है और हमारे माननीय नन्द किशोर जी ने इस विषय को बहुत अच्छा तरीका से रखा है और हमारे संजीव चौरसिया जी ने भी रखा है । न केवल गंगा नदी पर, कोशी पर, गंगा पर, गंडक पर सब जगह पुलों का जाल बिछाया गया है । अध्यक्ष महोदय, पी0डब्लू0डी0 की.....

अध्यक्ष : अब संक्षिप्त कर लीजिए ।

श्री राणा रणधीर : पी0डब्लू0डी0 की सड़कें 18952 कि0मी0 सड़कों का निर्माण कराया गया है। कृषि के क्षेत्र में 5 कृषि कर्मण्य पुरस्कार मिला है अंडा के उत्पादन में, मछली के उत्पादन में अनिल भाई चिन्ता कर रहे थे, तीन गुना मछली का उत्पादन बढ़ा है, अंडे का उत्पादन बढ़ा है, मीट का उत्पादन बढ़ा है .....

अध्यक्ष : अब समाप्त कर लीजिए ।

श्री राणा रणधीर : बस सर, एक मिनट । आपका ही है, आप सर इतना बढ़िया समाज सुधार का संकल्प कर रहे हैं, नैतिक संकल्प और सामाजिक संकल्प । बस सुन लीजिए अंतिम बोलकर बैठ जाता हूँ -

कि हरगिज न छोड़ेंगे कोशिशें तामिरे गुलिश्तां

समाज को बनाने को, समाज को सुधारने में बिहार को आगे ले जाने में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जज्बा है -

कि हरगिज न छोड़ेंगे कोशिशें तामिरे गुलिश्तां ,
गिरती है अगर बिजली तो सौर बार गिरे और ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खॉं, तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कीजियेगा।

श्री शकील अहमद खॉं : महोदय, हमने समझा कि 9 मिनट का वक्त है बहरहाल नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें रखी हैं, मुझे यह विश्वास है कि जो हमारे फाईनांस मिनिस्टर हैं, हमारी उम्मीद थी कि वे लिखते रहे होंगे लेकिन लगता है कि उनकी याद ध्यानी बहुत मजबूत है और वे सभी का जवाब देंगे । दुष्यंत कुमार का एक शेर है -

कहां तो तय था चढ़ावा, हरेक घर के लिए,
यहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए ,
तो सूरतेहाल आपके बजट की यही है ।

आपने बजटरी प्रोविजन्स में जो आंकड़ा दे रहा था, आपका 2021-22 और 2022-23 में जो एनोमली है या जिस-जिस एरिया में आपने बजट बढ़ाया या घटाया है, मुझे आश्चर्य है श्रवण जी यहां बैठे हैं, आपका बजट 100 करोड़ रू0 घटा दिया गया । क्या आपके बजटरी प्रोविजन जो मिले थे, आपके सारे काम हो गये । वह आंकड़ा दे दिया । माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, उसके बाद जल, जीवन, हरियाली में भी इस बार बजट में कटौती कर दी गई । क्या जल, जीवन, हरियाली

जैसे विषय पर जिस पर इतनी बड़ी डिबेट हुई, उसकी बजट कटौती कर दी गई । अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट में भी सिर्फ 8 करोड़ की बढ़ोतरी हुई । सिर्फ एस0सी0/एस0टी0 जो हमारा दलित समुदाय है, उसके बजट में 2021-22 के मुकाबले में इस बार घटा दिया गया तो क्या वजह होती है कि 2021-22 में आप कुछ बजट पेश करते हैं और उसके बाद उसको घटा देते हैं । अगर बढ़ाते हैं तो उसका कारण बताइए और अगर घटाते हैं तो उसका कारण भी आपको इजलास में पेश करना चाहिए । भाई, शायरी का दौर है तो गालिब का एक शेर सुन लीजिए और खासतौर से .....

अध्यक्ष : अब इसी के साथ आप समाप्त कीजियेगा ।

श्री शकील अहमद खॉ : मैं जानता हूँ सर -

रगो में दौड़ने-फिरने के हम नहीं कायल,
जो ऑखों से नहीं टपका, वह लहू क्या है,
दिल है नादां तुझे हुआ क्या है,
आखिर इस दर्द की दवा क्या है ,
हमें मुश्ताक वो बेजार, काश पूछो कि मुद्दा क्या है ।

आप एकदम से जो यहां क्वेश्चन रखे गये हैं तमाम प्रतिपक्ष के तरफ से, आपकी पूरी पराकाष्ठा ....

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री शकील अहमद खॉ : आपकी पूरी पराकाष्ठा आपके काम की, वह देखी गयी है और जिस तरह से आपने बजटरी प्रोविजन्स में जो काम दिया गया था, उसको आपने नहीं किया । कहीं कटौती की, कहीं बढ़ोतरी की । खासकर के नौकरी के सिलसिले में जो आपने छल किया है बिहार के नौजवानों के साथ, उसको जमाना और तारीख याद रखेगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, गालिब की शेर बहुत कह रहे हैं । इसपर हमको भी गालिब का ही शेर याद आ रहा है -

उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा,
चेहरे पर इतनी धूल और आईना साफ करता रहा ।

यही हाल आपका है ।

अध्यक्ष : श्री शाहनवाज, दो मिनट में अपनी बात को रखें ।

श्री शाहनवाज : यह अवसर देने के लिए धन्यवाद महोदय । दो मिनट का समय है तो मैं इस सदन का ध्यान बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र सीमांचल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। महोदय, हम दो लाईन बोलकर मैं अपने क्षेत्र की बात का बयान करना चाहता हूँ ।

जब टूटने लगे हौंसले तो बस यही याद रखना,
बिना मेहनत के हासिल तख्त-ओ-ताज नहीं होते,
ढूढ़ लेना अँधेरे में मंजिल अपनी,
जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते ।

यही हाल हम सीमांचलवासियों का है महोदय । अभी कुछ दिन पहले नीति आयोग की रिपोर्ट आयी थी, उसमें बिहार सबसे अंतिम पायदान पर था और हमारा जो अररिया, पूर्णिया और किशनगंज है, वह सबसे नीचे था । महोदय, हमारी सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है और हर वर्ष बाढ़ आती है और हजारों हेक्टर कृषि योग्य जमीन जो है, वह पानी में विलीन हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं

..... क्रमशः .....

टर्न-20/शंभु/04.03.22

..... क्रमशः .....

श्री शाहनवाज : लोग बेघर हो जाते हैं, लेकिन बजट में बिहार के बाढ़ प्रभावित एरिया के लिए भी प्रावधान होना चाहिए । महोदय, हर साल बाढ़ आता है और बाढ़ जब आ जाता है तो बांस बल्लों से कटाव निरोधक कार्य होता है और मेरा दावा है महोदय, एक मिनट मेरा दावा है कि ठेकेदार और पदाधिकारी इस कार्य को करके घर नहीं पहुंचते हैं और वह बांस बल्ला पानी में फिर से विलीन हो जाता है । मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ कि हमलोगों के यहां कटाव निरोधक कार्य ठोस होना चाहिए । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री राजकुमार सिंह, दो मिनट में अपनी बात रखें ।

श्री राजकुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार । आज मैंने जो देखा अभी कि आंकड़ों की कारीगरी, बाजीगरी दिखायी गयी । मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने भी बजट के बारे में कुछ पढ़ा है और मेरे विचार से बजट इज मोर दैन जस्ट ए सीरिज ऑफ नंबर ऑन पेपर, इट इज इन इम्बोडीमेंट ऑफ आवर वैल्यूज । यानी बजट सिर्फ कागज के पन्नों पर आंकड़ों की श्रृंखला नहीं है । यह सरकार की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक जो मूल्य है उसका पूरी तरह से बजट के माध्यम से अंतरण होता है, उसका प्रदर्शन होता है । जिस तरीके से 2022-23 का बजट राज्य की 12 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास का विस्तृत प्रारूप पेश करता है, तमाम विपरित परिस्थितियों के बावजूद कोरोना की महामारी से जूझते हुए भी जिस तरीके से बिहार ने पूरे देश में आर्थिक दर के हिसाब से अपना सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया है । इसका सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी

के नेतृत्व वाली इस कुशल प्रबंधन वाली सरकार को जाता है । बहुत सारे आंकड़े कहे गये, मैं भी कुछ बातें बता देना चाहता हूँ । महोदय, 2022-23 का जो बजट है वह 23 हजार करोड़ से 2 लाख 37 हजार करोड़ के सफर का साक्षी यह पूरा सदन रहा है कि किन विपरित परिस्थतियों में यह सफर किया गया । स्वास्थ्य के क्षेत्र में 16 हजार करोड़ का जो अभी आवंटन किया गया है उससे ज्यादा का वह 7.2 प्रतिशत पूरे आवंटन का है और मैं यह सदन को बताना चाहता हूँ कि अन्य राज्यों के औसत जो हैं वह 6 प्रतिशत है । इसमें बिहार सबसे अधिक है । इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में 39 हजार करोड़ से अधिक का आवंटन जो 16.5 प्रतिशत पूरे आवंटन का है । यह भी अन्य राज्यों का जो औसत है देशभर में 15.2 प्रतिशत सबसे अधिक बिहार का है ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री राजकुमार सिंह : इस तरीके से बिहार ने अपने तमाम क्षेत्र में अपने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र में सकारात्मक औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, खाद्य प्रसंस्करण नीति, इथेनॉल प्रोत्साहन नीति इन सभी क्षेत्रों में जो कृषि और उद्योग को संबद्ध करने का प्रयास किया है इससे न सिर्फ बजट को बिहार के सरकार की आर्थिक गति को गतिशीलता मिलती है बल्कि नये रोजगार सृजन के अवसर भी प्रदान करती है ।

महोदय, सबने अपनी-अपनी शायरी सुनायी है तो मैं भी दो पंक्तियां सुना देना चाहता हूँ क्योंकि जिन विपरीत परिस्थितियों में हमारी सरकार ने काम किया है उसके बारे में मैं अपनी कविता के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि - वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हों । नाविक की धैर्य परीक्षा क्या धाराएं यदि प्रतिकूल न हों ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री राजकुमार सिंह : मैं विपक्ष को इस बजट के माध्यम से आग्रह करूँगा कि वे अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करें । यही मेरा आग्रह है और अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी की एक कविता है आपको अच्छी लगेगी ।

अध्यक्ष : अगले बार । अब आप समाप्त कीजिए । श्रीमती निक्की हेम्ब्रम, प्रारंभ करें ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया गया जिसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूं । आपका आभार प्रकट करती हूँ । महोदय, वर्तमान बजट एवं आगामी वित्तीय वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण को पेश करता है । साथ ही यह सरकार के आर्थिक क्रियान्वयन को रूपरेखा भी प्रदान करता है । वर्तमान वित्तीय परिप्रेक्ष्य में भविष्य की योजनाओं

एवं उसकी नीति सरकार के विचारों एवं बहुमूल्य सुझाव को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी विकास का बजट प्रस्तुत किया गया है । सचमुच राज्य के समग्र विकास के लक्ष्य को हासिल करने में कारगर साबित होगा । महोदय, 2022-23 का बजट कुल 2 लाख 23 हजार 21 करोड़ रूपये का है जो कुल प्राप्ति 23 हजार 21 करोड़ है । 2 लाख 33 हजार 892 करोड़ रूपये की अनुमानित है । इस कुल प्राप्ति में केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा मद 91 हजार 181 करोड़ रूपये है । राज्यकर में 41387 करोड़ रूपये, राज्य के गैर कर राजस्व मद में 6136 करोड़ रूपये की अनुमानित है । महोदय, 2022-23 का मुख्य फोकस विकास, गरीबी उन्मूलन, वित्तीय स्थायित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि का है । इसके इजाफे के लिए निम्नलिखित प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं । शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति में 16 प्रतिशत, ग्रामीण विकास में 19 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 9 प्रतिशत, समाज कल्याण एवं पोषण में 26 प्रतिशत, पुलिस में 4 प्रतिशत, ऊर्जा में 14 प्रतिशत, आवासन में 5 प्रतिशत, सड़क एवं पुल पुलियों में 8 प्रतिशत, कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में 1 प्रतिशत, शहरी विकास में 19 प्रतिशत । हर प्रकार के क्षेत्र को देखते हुए राज्य चहुंमुखी विकास की ओर अग्रसर है । इसमें हमारे मुख्यमंत्री एवं माननीय उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद् के तमाम मंत्रियों की मेहनत एवं खून पसीना छिपा हुआ है, परन्तु विपक्ष द्वारा बजट को कम महत्व दिया जा रहा है । कहा गया कि बजट लोक लुभावन नहीं है । अर्थशास्त्री एवं प्रोफेसर डा0 ज्ञानचन्द्र ने कहा था कि वादों और हरितक्रांति के कारण ही समाज में विषमता फैलेगी और समाज विरोधी ताकतों के द्वारा ही समाजवाद आयेगा । मैं समझती हूँ कि प्रोफेसर ज्ञानचन्द्र के इस स्टेटमेंट की संजीदगी सभी विपक्ष के माननीय सदस्य अच्छी तरह से समझते हैं । आज समाज में तनाव और नक्सलवादी गतिविधियों से टूट दिखायी पड़ रही है वह ऐसे ही वादों और हरितक्रांति के ख्याली पुलाव और हवाई घोषणाओं के कारण है । हमारी सरकार काम पर विश्वास करती है ख्याली पुलाव और घोषणाओं पर नहीं । योजनाओं को ससमय लागू कर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोग हैं उन्हें समाज की मुख्य धाराओं में लाने के लिए पारदर्शी तरीके से प्रयास किये जा रहे हैं । महोदय, जल जीवन हरियाली को ध्यान में रखते हुए इस बजट में भूजल की कमी वाले इलाकों में सतही जल के दोहन खेतों वैकल्पिक जल संसाधनों को विकसित किये जाने का प्रावधान किया गया है । जलापूर्ति योजना को समुचित सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया गया है । पेयजल के उचित उपाय और संवर्द्धित व्यवहार परिवर्तन की दिशा में लक्ष्य जागरण कार्यक्रम शुरू

किये गये हैं । कृषि के क्षेत्र में गन्ने को बढ़ावा देने के लिए बिहार गन्ना उद्योग के संवर्द्धन नीति पर भी विचार किया जा रहा है । पशु स्वास्थ्य सेवा के लिए बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जा रहा है और पशु विकास के संस्थाओं के साथ सात निश्चय-2 के अन्तर्गत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । सात निश्चय के तहत सरकार द्वारा सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, स्वस्थ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर सुलभ संपर्क तथा सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं की योजनाओं को राज्य के निचले पायदान तक पहुंचाये जाने का प्रावधान किया गया है । महोदय, एक मंजिल के छत पर से जमीन के लोग बौने दिखते हैं, दो मंजिल के छत से भी वही व्यक्ति बौना दिखता है, लेकिन वास्तव में बौना कोई नहीं होता क्योंकि बौनापन देखने की प्रवृत्ति के कारण होता है । विपक्ष ने यह बजट अच्छा नहीं कहा है । धूप में चलते हो तो सांझ दिखती है शाम को जाओगे तो उजाले ढूढ़ोगे । महोदय, अंत में कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार न्याय के साथ विकास का विजन रखती है वह समाज के हर क्षेत्र, हर लोग, हर वर्ग के विकास की सोच रखती है ।

(क्रमशः)

टर्न-21/पुलकित/04.03.2022

(क्रमशः)

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विकास हो, रोजगार हो, रोडमैप हो या जीरो टोलरेंस की नीति हो । यानी आज बिहार विकास का एक दर्पण है और उस दर्पण के माध्यम से बिहार की करोड़ों जनता के विकास की गाड़ी को हम उसकी मंजिल तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं । मुझे आश्चर्य नहीं, क्योंकि बिहार के विकास के लिए जितना प्रयत्नशील, चिंतित इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और न सिर्फ चिंतन की योजनाएं ही बनती हैं बल्कि योजनाओं के कार्यान्वयन करने के लिए उसके लिए राशि और समीक्षा भी करने का काम करते हैं ।

अध्यक्ष : संक्षिप्त कर लीजिये ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : हमें दुख नहीं है स्वामी विवेकानंद जी ने कहने का काम किया है कि अगर कोई काम करते हो, पहले तो लोग उपहास करेंगे फिर उसका विरोध करेंगे और बाद में जाकर उसका अनुकरण करेंगे । इसी प्रकार विपक्ष द्वारा विकास के कार्यों के लिए हमेशा उपहास किया जाता है परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे भी अच्छे कार्यों का अनुसरण करेंगे ।

''ऊपर सब शून्य-शून्य था, कुछ भी नहीं गगन में,

धर्मराज जो कुछ भी है, वह इसी बजट में ।''

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग को । आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से कार्यान्वित होने वाले विभिन्न विषयों से संबंधित कार्यों के मेंटेनेंस के लिए कौन-कौन विभाग या पदाधिकारी जिन्हें वह परिसंपत्ति हस्तांतरित की गई है, उससे संबंधित संकल्प की सूचना माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग ने दी है । यह करीब 11 पृष्ठों की मार्गदर्शिका है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसकी प्रतियां सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा देने का कष्ट करें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, सदन करायेगा, हम तो आपको दे दिये ।

अध्यक्ष : नियम के तहत तो विभाग को ही कराना है ।

माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर हुए सामान्य विमर्श पर अब सरकार का उत्तर का होगा ।

सरकार का उत्तर

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी, 2022 को महामहिम राज्यपाल के संबोधन के साथ बिहार विधान मंडल का बजट सत्र प्रारम्भ हुआ था । उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक वित्तीय विवरण मैंने सदन के पटल पर रखा था । जिसमें आंकड़ों के साथ राज्य की प्राप्तियां एवं व्यय का लक्ष्य निहित था । हमारी सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से विस्तार से इन्होंने अपना वक्तव्य दिया था और विस्तार से राज्य की प्रगति आने वाले दिनों में सरकार की दृष्टि, विस्तार से इन्होंने अपनी बातों को रखने का काम किया । सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा पक्ष, विपक्ष के कई हमारे माननीय साथियों ने आज की इस बहस में भाग लिया । मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं । माननीय श्री आनन्द शंकर सिंह, श्री संजीव चौरसिया, श्री संदीप सौरभ, सुश्री श्रेयसी सिंह, श्री मनोज मंजिल, श्री ललित नारायण मंडल, श्री सुर्यकान्त पासवान, श्रीमती ज्योति देवी, श्री रामविलास कामत, श्रीमती स्वर्णा सिंह, डॉ0 सत्येन्द्र यादव, श्री अनिल कुमार साहनी, श्री राणा रणधीर जी, श्री शकील अहमद खां, श्री शाहनवाज, श्री राजकुमार सिंह एवं डॉ0 निक्की हेम्ब्रम । इन लोगों ने विस्तार से बजट पर अपने-अपने विचारों को रखने का काम किया है और मैं सबों को स्पष्ट बता दूं कि

आपकी बातों को हमने गंभीरता से सुना भी है और राज्य के विकास में आपकी जो बातें हैं निश्चित तौर पर हम उसको देखने का काम भी करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, विगत कई वर्षों से हमारी सरकार का लक्ष्य राज्य के समावेशी, सतत् एवं सर्वांगीण विकास का रहा है । हमने राज्य के विकास में साल-दर-साल अपने नये आयामों को भी जोड़ने का काम किया है । जो कि वर्तमान अपना आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन है उसमें काफी स्पष्ट भी है । वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट भाषण एवं बजट दस्तावेजों में वह स्पष्ट तौर पर दिख भी रहा है । हमारी यह दृढ़-संकल्पता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में । उसी का यह सकारात्मक परिणाम है कि इतना बेहतर ढंग से हमने बिहार के चेहरे को रखने का काम किया है । कोविड- 19 जैसी विकट आपदा का हमने सामना किया, लेकिन उसके बावजूद भी वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य की आर्थिक विकास दर 9.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है । विकास की इस रफ्तार को आगामी वित्तीय वर्ष में भी हम बनाये रखना चाहते हैं । हम आपका सहयोग चाहते हैं क्योंकि प्रतिपक्ष भी सरकार का अंग है । बिहार के विकास के लिए आज हम इस बिहार विधान मंडल में बैठे हैं और हमारी प्रतिबद्धता है । इस विधान मंडल के लिए प्रतिबद्धता है कि हम राज्य के जो लोग हैं, बिहार के जो हमारे लोग हैं, उनके विकास में उनका जीवन कैसे बदले, उनके विकास में आपकी और हमारी भूमिका हैं, इसके प्रति हमलोग सदन के प्रति भी जवाबदेह हैं । हमने राज्य के विकास के लिए इस बार के बजट में छह सूत्रों को आपके सामने रखने का काम किया है । महोदय, हम सभी ने कोरोना के कुप्रभाव को देखा हैं लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश से कोरोना संक्रमण के प्रभाव को खत्म करने के लिए आम आदमी को संक्रमण से बचाने के लिए जो कदम उठाये हैं उसे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने आमजनों की भागीदारी से टीकाकरण अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर कोरोना के विरुद्ध सफलता प्राप्त की है । बिहार कोविड टीकाकरण के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में हम शामिल हुए हैं और लगातार सघन कोविड जांच नि:शुल्क की जा रही है । स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में भी विगत दो वर्षों में तेजी से सुधार हुआ है । अब तक 11.80 करोड़ से अधिक टीकाकरण किया जा चुका है । 11.80 करोड़ जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं उसमें निरंतर लगातार वृद्धि भी हो रही है और हम 12 करोड़ से ऊपर भी पहुंच चुके हैं । राज्य सरकार ने सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में 122 जगहों पर पी0एस0ए0 ऑक्सीजन जेनेरेशन प्लांट का अधिष्ठापन कर क्रियाशील किया है । राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य सुविधाओं को और

बेहतर बनाने के लिए वर्ष 2021-22 की तुलना में 2,869 करोड़ रुपये अधिक का प्रावधान किया है । पूर्व वर्ष की तुलना में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । महोदय, हम इन चीजों को इसलिए बताना चाहते हैं कि हम लगातार वर्ष 2005 से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और वास्तव में लोगों ने कहा भी है कि -

''यूं ही बनाते रहो पहचान अपनी,
हवाएं खुद तुम्हारा तराना गायेगी ।''

वर्ष 2005 से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के विकास में जो एक बड़ा परिवर्तन हुआ है आज बिहार की जनता खुद इस बात को कह रही है । अखबार में छपी बातों, हमने अखबार के आंकड़ों से बिहार का विकास नहीं किया है । हमारे बिहार के लोगों का जो दर्द है, बिहार के लोगों का दर्द वर्ष 2005 से हमने देखा, जो महसूस किया है ।

(क्रमशः)

टर्न-22/अभिनीत/04.03.2022

-क्रमशः-

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : जो हालात थे उन हालातों को जमीनी तौर पर परिवर्तित करने का काम किया है । महोदय, राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में भी नवोन्मेषी सुधार किए गये हैं । राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में कुल 6,298 उत्क्रमित एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 7,530.42 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है । महोदय, हम यह आंकड़ा इसलिए बताना चाहते हैं कि कुछ फोटोकॉपी के पन्नों से बिहार की तकदीर को बदला नहीं जा सकता है । बिहार की तकदीर के लिए सबल नेतृत्व, कुशल नेतृत्व और विजन होना चाहिए कि हम किस प्रकार का बिहार चाहते हैं, 2005 के पहले का बिहार चाहते हैं या 2005 के बाद का बिहार चाहते हैं । बिहार के लोगों ने जो, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश रहा है भारत और पांच वर्षों में लोकतंत्र का जो अनुष्ठान होता है उसने इस बात को दर्शाया है कि बिहार में जो विकास के पन्ने बने हैं, जो मान्यता दी है, लोकतंत्र का पर्व इस बात को दर्शाता है, इसके लिए फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है। यहां हमलोग ओरिजनल कॉपी से काम करते हैं, इस बात को हम कहना चाहते हैं। राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एवं राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद के सृजन की भी हमने स्वीकृति दी है । वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार,

गुणात्मक तथा आधारभूत अधिसंरचना को मजबूत करने के लिए सर्वाधिक बजट का प्रावधान किया है महोदय, जो कुल बजट का लगभग 16.5 प्रतिशत है और यह पूर्व वर्ष 2021-22 की तुलना में लगभग 1,156 करोड़ रुपया अधिक है । यह जो वृद्धि है इस बात को दर्शाती है कि शिक्षा के प्रति जो हमारा संकल्प है उस संकल्प को हमने अपने बजट की तैयारी में आगे बढ़ाने की दृष्टि से रखा है । माननीय महोदय, राज्य में निजी निवेश एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है । इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, स्टार्ट अप नीति इत्यादि लागू किया गया है । इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 के तहत 151 इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित करने की दिशा में हमने प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी की है जिसकी अनुमानित लागत 30,382 करोड़ रुपया है । राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्यमंत्री उद्यमी योजनांतर्गत 15,986 उद्यमियों को प्रोत्साहित किया है जिसमें 800 करोड़ रुपया का निवेश होगा । इस योजना में राज्य के वंचित वर्ग को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हमने बिहार के लोगों से जो वादा किया है उस वादे को हम याद रखते हैं । हम कोई व्यक्तिगत अपने लिए काम नहीं करते हैं, बिहार के आवाम के लिए जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प की सिद्धि के लिए जो पांच वर्ष का कार्यकाल है, उस पांच वर्ष के कार्यकाल में दिखायेंगे कि हमारा जो कुशल नेतृत्व है और जो मजबूत मार्गदर्शन केंद्र का है, आने वाले दिनों में उन सारे संकल्पों को हम पूरा करने का काम करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति से सुनिए । माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हम रास्ते में ठहरने वाले राही नहीं हैं । महोदय, हम रास्ते में रूकने वाले राही नहीं हैं, हम उस पथ के पथिक हैं जो अपनी मंजिल तक पहुंचना जानते हैं । राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को हमेशा..

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति से सुनिए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : सर्वोच्च स्थान दिया है, जिसके फलस्वरूप 4,000 महिला उद्यमियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है । इसके अतिरिक्त 4,000 अत्यंत पिछड़ी जाति, 3,999 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को इस योजना का लाभ मिला है । महोदय,

हम जानते हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सकारात्मक पहल की है यह इनको बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इनके भी शासनकाल को बिहार ने देखा है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सभी बैठ जाइये । बैठिए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : इन्हें बेचैनी है, बिहार के विकास की जो गाथा आज हर घर में गायी जा रही है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय...

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : गांव की सड़कें, गांव में जलते हुए बिजली के बल्ब, स्कूल के भवन, शिक्षक जो इस बात के गवाह हैं, इस बात की कहानी कह रहे हैं कि बिहार विकास के पथ पर बढ़ा है । इस योजना को ई-प्रशासन के माध्यम से क्रियान्वित किया गया ।

(व्यवधान जारी)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हमने मंत्री जी से पहले भी अनुरोध किया था..

अध्यक्ष : आपकी पूरी बातों को लोगों ने धैर्य से सुना है । अब आप सुनिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हम अनुरोध कर रहे हैं जो हमलोगों ने पूछा उसका जवाब...

(व्यवधान जारी)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : इसके तहत ऑनलाईन आवेदन लिया गया और चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी रखा गया । यह योजना राज्य की आर्थिक वृद्धि में अतिरिक्त गति प्रदान करेगी । साथ ही, इससे राज्य के युवाओं को अतिरिक्त रोजगार मिल रहा है । इन निवेशों से राज्य में आद्योगिकीकरण का बेहतर माहौल बन रहा है । उल्लेखनीय है कि उद्योग एवं उद्योग निवेश मद में पूर्व वर्ष 2021-22 की तुलना में 358 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये)

महोदय, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 से कृषि रोड मैप के तहत कृषि क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की गयी हैं । महोदय, हम चाहते थे कि बिहार के विकास में इनकी भी भूमिका सदन के सदस्य के नाते सुनिश्चित हो, लेकिन महोदय दुख है कि ये विनाश की गति के वाहक हैं, इसलिए विकास की गति को सुनना ये पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि सच इन्हें बर्दाश्त नहीं है । जब हमने इन्हें 2005 के पहले के बिहार और 2005 के बाद के बिहार की बदलती तस्वीर का आईना दिखाया, तो ये

बाहर चले गये । हम चाहते थे कि विपक्ष की भूमिका भी बिहार के विकास में सुनिश्चित हो, लेकिन हमें अपने नेतृत्व पर भरोसा है । अध्यक्ष जी, हम अपने नेतृत्व से, सबल नेतृत्व से हमने आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 में जो वादा बिहार के लोगों से किया उस वादा को पूरा करना जानते हैं । महोदय, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 से कृषि रोड मैप के तहत कृषि क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की गयी हैं । मुर्गी पालन, मछली पालन, गौवंश का विकास एवं सहकारिता का विकास किया जायेगा । कृषि को उद्योग से जोड़ने तथा अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाई है । इसके अतिरिक्त किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पाद को अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से बढ़ने हेतु कृषि निर्यात नीति बनाई गई है । वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के विकास के लिए 7,712.30 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है । महोदय, बिहार की आत्मा ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है और करीब 80 प्रतिशत जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है, इसलिए राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने एवं ग्रामीणों को विश्वस्तरीय सुविधा प्रदान करने के लिए जहां एक ओर सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल इत्यादि के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण एवं शहरी विकास पर प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 29,749.64 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । महोदय, हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है । इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं अन्य वंचित वर्गों के हितों के संरक्षण एवं कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुन लीजिए । बैठिए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, इन वर्गो के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं । वर्ष 2022-23 में इन वर्गों के कल्याणार्थ कुल 12,375.07 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए । अभी पूरा सुन लीजिए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में लोक व्यय से राज्य में जहां एक ओर मानव विकास सूचकांक में वृद्धि होगी वहीं दूसरी ओर राज्य को स्वस्थ, शिक्षित एवं कुशल नागरिक मिलेंगे । उद्योग, औद्योगिक निवेश, कृषि, सहकारिता एवं पशुपालन आदि प्रक्षेत्र में व्यय के फलस्वरूप

राज्य के आर्थिक विकास को एक नयी दिशा दी जायेगी, इससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे नवयुवकों को रोजगार के असीम अवसर उपलब्ध होंगे । महोदय, राज्य का फोकस ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आधारभूत संरचना के विकास पर रहेगा

-क्रमशः-

टर्न-23/हेमन्त/04.03.2022

..क्रमशः..

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : इससे एक तरफ जहां राज्य में औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालीन पूंजीगत संरचना का निर्माण होगा वहीं दूसरी ओर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होने से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित होंगे जो अंततोगत्वा राज्य की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार के सतत विकास के लिए वर्ष 2015 में राज्य सरकार द्वारा विकसित बिहार के सात निश्चय योजना प्रारम्भ की गई थी । इसके अंतर्गत पांच वर्षों के लिए विकास के सात लक्ष्य निर्धारित किये गये थे । सात निश्चय के अंतर्गत आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार एवं हर घर बिजली निश्चय के लक्ष्य प्राप्त किये जा चुके हैं । इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम का योजनावार एक बार मैं सदन में विवरण रखना चाहता हूं । उल्लेखनीय है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 1,17,923 बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत हुए हैं । वर्ष 2022-23 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

महोदय, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत कुल 5,16,730 आवेदकों को लाभान्वित किया गया है तथा 697 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है । वर्ष 2022-23 में इस योजना अंतर्गत 200 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है ।

महोदय, कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत 19,74,443 (मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना सहित) आवेदनों को प्रशिक्षण हेतु ऑनलाईन प्रेषित किया गया है । वर्तमान में 1,496 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं तथा सभी 534 प्रखंड आच्छादित हैं । अभी तक इस कार्यक्रम पर 702 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है । महोदय, वर्ष 2022-23 में इस योजना अंतर्गत 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

हर घर नल का जल । महोदय, इस निश्चय के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा 57,995 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 57,603 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। महोदय, कुल लक्षित घरों में से 88.12 लाख घर आच्छादित किये गये हैं ।

महोदय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 26,239 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 26,088 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है । गुणवत्ता प्रभावित 30,163 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 29,335 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।

महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 3,370 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 3,042 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है । महोदय, कुल लक्षित घरों में से 14.03 लाख घर आच्छादित किये गये हैं । महोदय, यह विकास की गाथा है, यह लाफेबाजी नहीं है और विकास की गाथा को सुनने में लोगों को तकलीफ होती है । क्योंकि उन्होंने कभी इस धारा पर काम किया नहीं । इसीलिए उन्हें तकलीफ होती है, लेकिन हम विकास की गाथा कर रहे हैं । आने वाले दिनों में बिहार का क्या स्वरूप होगा, उसकी एक बानगी है महोदय और विगत 15 वर्ष में बिहार में शासन रहा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वह इस बात को दर्शाता है कि हमने काम किया है और आने वाले दिनों में भी हम काम करेंगे ।

वर्ष 2022-23 में इस निश्चय अंतर्गत 1001.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

घर तक, पक्की गली नालियां । महोदय, इस निश्चय के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा 1,14,469 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 1,14,469 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है । कुल लक्षित घरों में से 177.08 लाख घर आच्छादित किये गये हैं । शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 3,340 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 3,133 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है । कुल लक्षित घरों में से 8.22 लाख घर आच्छादित किये गये हैं ।

ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना के तहत सभी 4,643 टोलों के लिए योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है । इस योजना के तहत 3,955.68 कि0मी0 सड़क का निर्माण पूर्ण करते हुए 4,601 बसावटों को संपर्कता प्रदान की गई है । वर्ष 2022-23 में इस निश्चय अंतर्गत 230 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, इनके भाषण की समाप्ति तक सदन की अवधि तो बढ़ा ली जाय, 4 बजने वाले हैं ।

अध्यक्ष : सरकार के उत्तर की समाप्ति तक सदन की अवधि बढ़ाई जाती है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान । इस निश्चय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी 8,386 पंचायत ओ0डी0एफ0 घोषित एवं सभी 115.60 लाख घर आच्छादित किये गये हैं सभी 534 प्रखण्ड एवं 101 अनुमंडल तथा सभी 38 जिला ओ॰डी॰एफ॰ घोषित किए गए हैं ।

शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अब तक कुल 3.84 लाख वैयक्तिक शौचालय एवं 20,476 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। सभी 3,367 शहरी वार्ड एवं 142 नगर निकाय ओ॰डी॰एफ॰ घोषित किए गए हैं ।

अवसर बढ़े, आगे पढ़ें - इस निश्चय के तहत राज्य में निर्धारित 54 के विरुद्ध 41 अनुमंडलों में ए॰एन॰एम॰ संस्थान खोला गया है तथा शेष पर कार्य चल रहा है । 23 चयनित जिलों में से 12 जी॰एन॰एम॰ संस्थान स्थापित किया गया है तथा शेष में कार्य चल रहा है । 28 जिलों में पारा मेडिकल संस्थान खोले जाने के लक्ष्य के विरुद्ध 20 संस्थान खुल चुके हैं । 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की जानी है जिसमें से 4 में स्थापित कर दिया गया है । 4 चिकित्सा महाविद्यालयों में बी॰एस॰सी॰ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की गयी है । 3 नये मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है । राज्य के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु राज्य में 15 पॉलिटेक्निक संस्थान, 22 अभियंत्रण महाविद्यालय, 17 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 41 अनुमंडल स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जा चुके हैं और अन्य पर कार्रवाई चल रही है ।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य के बहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्पित है । विकसित बिहार के लिए सफलतापूर्वक क्रियान्वित सात निश्चय-1 की उपलब्धियाँ उत्साहवर्धक रही हैं । सरकार द्वारा पांच वर्षों (2020 से 2025) के लिए सात निश्चय-2 योजना प्रारंभ किया गया है । वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसके लिए 5 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

युवा शक्ति- बिहार की प्रगति योजना अन्तर्गत सात निश्चय के तहत बिहार में युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाये गये हैं । वित्तीय वर्ष 2022-23 अन्तर्गत कुल 1153.00 करोड़ रुपये का उपबंध विभिन्न योजनाओं में किया गया है ।

सशक्त महिला, सक्षम महिला योजना अन्तर्गत उच्चतर शिक्षा एवं उद्यमिता हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस निश्चय के तहत राज्य सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 900 करोड़ रुपये का उपबंध इस निश्चय अन्तर्गत किया गया है ।

हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना अन्तर्गत राज्य सरकार हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 600 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है । इसके लिए हम अपने ऊर्जा विभाग को धन्यवाद देते हैं । माननीय मंत्री भी यहां बैठे हुए हैं । उन्होंने हर खेत तक सिंचाई के लिए बिजली पहुंचाने के लिए हर संभव उपाय किये हैं ।

स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव योजना अन्तर्गत राज्य सरकार गांवों को समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 847 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है ।

स्वच्छ शहर विकसित शहर योजना अन्तर्गत राज्य सरकार शहरों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 550 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है ।

सुलभ सम्पर्कता योजना अन्तर्गत राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य में आवागमन को सर्व-सुलभ करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 450 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है ।

सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा योजना अन्तर्गत राज्य सरकार गाँव-गाँव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता एवं बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 500 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, राज्य के वंचित वर्गों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं, बच्चों, निर्धन, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों आदि के विकास के बिना राज्य का विकास पूर्ण नहीं हो सकता है । महोदय, इसलिए हम इन वंचित वर्गों के विकास के लिए कटिबद्ध हैं, हमारी सरकार कटिबद्ध है, हमारा सबल नेतृत्व कटिबद्ध है महोदय । विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत डी॰बी॰टी॰ के माध्यम से सरकारी कोष से राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में ऑनलाईन अंतरित की जा रही है । जरूरतमंदों को जब भी धन राशि प्राप्त होती है, तब वे सीधे बाजार का रुख करते हैं, जिससे बाजार में मांग का सृजन होता है और यह उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि का कारण बनता है । परिणामस्वरूप उद्योगों की उत्पादन क्षमता सतत् एवं टिकाऊ होती है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के विस्तृत आंकड़ों को सदन के पटल पर रख चुका हूँ और पूर्व में हमने विस्तार से इसकी चर्चा की है । इसलिए बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं ।

(क्रमशः)

टर्न-24/धिरेन्द्र/04.02.2022

...क्रमशः...

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन के तमाम माननीय सदस्यों से सादर अनुरोध है, हमारे प्रतिपक्ष के सभी साथी चले गये हैं मुझे तो तब

अच्छा लगता कि बिहार के विकास में अपनी भी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए वे उपस्थित रहते, आने वाले बिहार के विकास में उनका भी नाम अंकित होता लेकिन महोदय, बजट के प्रत्येक बिन्दु पर विस्तृत चर्चा की जाय तथा सुझाव भी दिये जायें । मेरा पूर्ण प्रयास होगा कि यथासंभव आपके सुझावों पर हम विचार भी करेंगे । विकासोन्मुखी बजट के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मैं इस महान सदन के माननीय सदस्यों से सहयोग की भी अपेक्षा करता हूँ । आइये, हम सब सदस्य अपने राज्य वासियों के कल्याणार्थ सरकार के कार्यक्रमों में सहयोग कर आने वाले बिहार को एक उज्ज्वल बिहार, एक विकसित बिहार के रूप में हम उसे विकसित करें, उस बिहार को एक विकसित बिहार के रूप में हम आज देखना चाहेंगे । इसके लिए हम सबों से अनुरोध करते हैं और अंत में-

''जिगर और दिल को बचाना भी है,
नजर आप ही से मिलाना भी है,
सियासत का हर भेद पाना भी है,
मगर अपना दामन बचाना भी है,
जमाने से आगे तो बढ़िये साहब,
जमाने को आगे बढ़ाना भी है ।''

जय बिहार, जय भारत ।

श्री नंद किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय ...

अध्यक्ष : आप भी कुछ कहेंगे ।

श्री नंद किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री जी कुछ छोड़ दिये । जो उनका बयान था, नेता विरोधी दल का, विरोधी पार्टी के लोगों का । मैं दो पंक्ति कहना चाहता हूँ अगर आपकी अनुमति हो तो-

''मुफलिसी का यह आलम है कि दोस्तों, आम बेचकर मंजर खरीद लाये हैं,
ये किसके तालीम का असर है कि वे कलम बेचकर खंजर खरीद लाये हैं ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ और वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श भी समाप्त हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 04 मार्च, 2022 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-46 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 07 मार्च, 2022 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल के वक्तव्य का लिखित अंश – परिशिष्ट द्रष्टव्य

Health:-

परिशिष्ट

1. नीति आयोग के अनुसार **स्वास्थ्य मानकों मे बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है**

2. **NSSO डाटा देखें तो पाते हैं कि प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च में भी बिहार सबसे कम खर्च करता है| बिहार मात्र 495 रु. प्रति व्यक्ति खर्च करता है** वहीं उत्तर प्रदेश 800 और हिमाचल प्रदेश 2000 खर्च करता है।

3. **जब हम मरीज-डॉक्टर अनुपात देखते हैं कि बिहार में एक डॉक्टर पर लगभग 30 हजार जनसंख्या है।** जबकि WHO का कहना है कि 1000 जनसंख्या पर 1 डॉक्टर होना चाहिए| भारत में 10000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर मान्य है| दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं अन्य राज्यों में भी 1000 से कम जनसंख्या पर 1 डॉक्टर है।

4. **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NHRM) के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रों मे लगातार पिछले 15 सालों से सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा है।**

5. **वहीं बिहार में जनसंख्या और हॉस्पिटल बेड का Ratio देखे तो पाते हैं कि यह देश मे सबसे कम है। बिहार मे 1 लाख की जनसंख्या पर मात्र 6 बेड है जबकि 1 लाख की जनसंख्या पर कम से कम 22 बेड होने चाहिए।**

6. **नीति आयोग का Health Index देखें तो पाते हैं कि बिहार में कोई भी CHC-कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भारत के मापदंड पर खरा नहीं उतरा है जहाँ हर एक CHC में 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए।**

7. बिहार में 800 Community Health Center होना चाहिए पर लगभग 150 है। 3314 (PHC) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए पर 553 ही है,। Referral Hospital 622 होना चाहिए पर मात्र 70 है। इससे पता चलता है कि डबल इंजन सरकार मे पढ़ाई और दवाई में बिहार सबसे पीछे है।

8. आयुष्मान भारत योजना मे सबसे कम कवरेज और खराब प्रदर्शन वाला राज्य बिहार है।

9. इसी कारणवश Human Development Index में बिहार सबसे निचले स्थान पर है।

"जहाँ सच हैं, वहाँ पर हम खड़े हैं,

इसी खातिर आँखों में गड़े हैं."